[Dr. K. L. Shrimali]

Table, under section 18 of the University Grants Commission Act, 1956, a copy of the Annual Report of the University Grants Commission for the period from April, 1957 to March, 1958 [*Placed in Library, See* No LT-1212/59]

AMENDMENTS TO INTERNATIONAL COPYRIGHT ORDER

The Minister of Scientific Research and Cultural Affairs (Shri Humayun Kabir): Sir, I beg to lay on the Table, under Section 43 of the Copyright Act, 1957, a copy of each of the following Notifications, making certain amendments to the International Copyright Order, 1958 —

(i) S O No 166 dated the 20th January, 1959

(ii) S O No 222 dated the 22nd January, 1959 [*Placed in Library, See* No LT-1213/59]

AMENDMENTS TO REGULATIONS OF INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION

The Deputy Minister of Finance (Shrimati Tarkeshwari Sinha). Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (3) of Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948, a copy of Notification No 2/59 dated the 31st January, 1959 making certain amendments to the General Regulations of the Industrial Finance Corporation of India [*Placed in Library, See* No 1214/59]

12.17 hrs.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS—1958-59

The Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Sir, I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 1958-59

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS RAILWAYS—1958-59

The Minister of Railways (Shri Jagjivan Ram): Sir, I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1958-59

ESTIMATES COMMITTEE

THIRTY-SEVENTH REPORT

Shri B G. Mehta (Gohilwad) Sir, I beg to present the Thirty-seventh Report of the Estimates Committee on the Ministry of Health—Public Health (Part I)

---

12 18 hrs

MOTION ON ADDRESS BY THE PRESIDENT—*contd*

Mr. Speaker. The House will now resume further discussion on the Motion of Thanks regarding the President's Address Shri Braj Raj Singh may continue his speech He has taken 3 minutes already Out of the time allotted for the discussion, time already taken is 7 hours and 12 minutes and the time at our disposal is 7 hours 48 minutes

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह निवेदन कर रहा था कि जब हम गावो के लिये, ग्रामीण जनता के लिये एक तरह की सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे है तो इस का यह मतलब नही है कि शहरी जनता और शहरी उद्योगपतियो के लिये हम किसी तरह की सीलिंग मुकर्रर न करें । मैं इस का समर्थक हू कि सीलिंग जीवन के हर क्षेत्र में मुकर्रर होनी चाहिये । आज हमारे देश की जनता की आमदनियो में बहुत बडा अन्तर है ? इस से उस जनता को जिस को भर पेट खाना नही मिलता, कपडा पहनने के

लिये नहीं मिलता, जिस की शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाती, उस को अपने प्रयत्नो को सफल बनाने के लिये और देश के निर्माण के लिये कोई उत्साह नहीं मिलता । इस लिये इस तरह की बात करना कि हम सिर्फ गाव की जनता के लिये कोई सीलिंग मुकर्रर करेंगे, शहर की जनता के लिये और जो लोग छोटे उद्योगो में लगे हुए हैं उन के लिये कोई सीलिंग मुकर्रर नही की जायेगी, बहुत हानिकर है और इस से देश के नवनिर्माण में बहुत ही बाधा आ सकती है । इस के साथ ही मैं यह कह देना चाहता हू कि जहा तक खेती का प्रश्न है, उस मे आज एक आवाज उठ रही है सीलिंग के विरोध में तथा उस की अधिकतम सीमा बाधने के विरोध में लेकिन वह एक ऐसी आवाज है जो प्रतिक्रियावादियो की तरफ से उठाई जा रही है । कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि देश की खाद्य समस्या हल हो और देश में इस तरह का समाज बने जिस में करीब करीब सब लोग बराबर के हो सकें, वह कभी भी इस तरह की चीज का विरोध नही कर सकता । लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार की तरफ से कोई इस तरह का सक्रिय कदम नही उठाया जा रहा है जिस स यह बराबरी आ सके । एक तरफ तो यह ऐलान किया जाता है कि हम सीलिंग कायम करेंगे और दूसरी तरफ सैकडो हजारो लोगो को जेल भेजा जाता है सिर्फ इसलिये कि उन्होने, जिन के पास एक इच भी जमीन नही है, सरकार की परती जमीनो पर कब्जा किया और शातिपूर्ण तरीके से किया और अपने लोगो मे बराबर से बाट ली । मध्य प्रदेश में रायपुर जिले की धमतरी तहसील मे एक गाव सेहावा है, उस में १५,००० आदिवासियो ने जिन के पास एक इच जमीन नही थी सरकार की २०,००० एकड़ परती जमीन पर पिछले दिनों कब्जा कर लिया शातिपूर्ण तरीके से । जो सरकार आज ऐलान करती है कि भूमि का सीलिंग होना चाहिये और इस तरह से जो अतिरिक्त भूमि मिलती है उस का उचित वितरण होना चाहिये, वही आज हम को इन कामो से हटा रही है । इस सरकार के द्वारा उन लोगों को जिन्होने परती जमीनो को अपने कब्जे में लिया उन जमीनो से बेदखल किया जाता है । ऐसी हालत में किस तरह से आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि आप कुछ लोगो के विरोध के होते हुए जमीन पर सीलिंग कर के जो अतिरिक्त भूमि मिलती है उस का उचित बटवारा करने की कोशिश करेंगे और जिन लोगो के पास भूमि नही है उन का दिलवाने की कोशिश करेंगे ? जैसा मै ने कल निवेदन किया था हमें निश्चित रूप से यह कह देना चाहिये कि हम ऐसा अवश्य करेंगे और जल्दी करेंगे, क्योकि इस में देर करने से ऐसा हो सकता है कि लोगो को कुछ भी जमीन न मिले, और उस को उन लोगो में बराबर से बाटेंगे जिन से कि मुल्क का उत्पादन बढने की आशा हो । आप की सरकार इन्तजार करती रही है और इस का नतीजा यह होगा कि लोग बनावटी ढग से उस जमीन को दूसरे लोगो को दे देंगे चाहे बैनामा कर के या दूसरे तरीके से । और इस तरह से उस जमीन का बटवारा कम से कम बिना जमीन के लोगो में नही होगा । जब हम आर्डिनेंस बना कर के कानून बना सकते है जब कि लोक सभा नही बैठी होती है, तो आज तो लोक सभा का अधिवेशन चल रहा है । फौरन ही इस में कानून लाया जाये और कानून ला कर के सीलिंग मुकर्रर की जाय अतिरिक्त भूमि की । सीलिंग का विस्तार भी उतना ही होना चाहिये जितना एक व्यक्ति अपने श्रम से

[श्री बजराज सिंह]

एक बैल की जोड़ी से जोत सकता है। उस की अधिक से अधिक सीलिंग तिगुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। अच्छा होता कि इस तरह की सीलिंग मुकर्रर करने के लिये इसी सेशन में कोई विधेयक लाया जाता और इस तरह के कानून से जो प्रतिक्रियावादी लोग जमीन की समस्या का हल न होने देने के लिये हर तरह के कार्य कर सकते हैं उन को जवाब दिया जाता। इसी तरह से यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन इस के साथ साथ यह बहुत ही आवश्यक है कि हम लोगो में इस का गलत प्रचार न होने दें। इस के लिये यह आवश्यक है कि शहर के लोगों की जो आमदनी है उस पर भी एक तरह की सीलिंग कायम हो। उस मे कहा तो यह जा सकता है कि एक और तीन का अनुपात रक्खा जाय, लेकिन अगर यह न हो तो कम से कम एक और दस का अनुपात तो हो ही। यानी हम को गारेन्टी देनी चाहिये कि किसी भी व्यक्ति की आमदनी १०० रु० माहवार से कम न होगी और १००० रु० माहवार से अधिक नही होगी। आज हमारे यहा क्या स्थिति है? आज देश में एक और हजार का फर्क है। इस मुल्क में आज लोग भूखों मर रहे हैं, हम उन का इन्तजाम नही कर पाये हैं। हम आज उन से कैसे कह सकते हैं कि अपनी योजना को सफल बनाने के लिये वह और सैक्रिफाइस करें और अधिक टैक्स दें? मुझे ताज्जुब होता है कि एक तरह तो हम खाद्य की समस्या को हल करने के लिये यह बात कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ आप जोतों को अनार्थिक जातें बनाते जा रहे है। साथ ही आज प्लैनिंग कमिशन के एक माननीय सदस्य की तरफ से इस प्रकार की चर्चा चलने लगी है कि भूमि पर जो टैक्स है उसे दूना किया जाना चाहिये। आप उस जमीन का टैक्स दूना करना चाहते हैं जो कि अनार्थिक जोत है, जो उस की जोत है जिस को खाने के लिये कुछ नहीं मिलता। इस तरह से आखिर खाद्य की समस्या कैसे हल की जा सकती है? खाद्य समस्या को हल करने के लिये मुल्क में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ना चाहिये। इसक लिय यह जरूरी है कि जो अपने यहां अनार्थिक जोत है उस के लगान को माफ किया जाये और उस में खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिये और सुविधायें दी जायें, छोटी सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायें।

12.25 hrs.

[SHRI MOHAMMED IMAM *in the Chair*]

लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नही है। सरकार गम्भीरतापूर्वक इस पर विचार नहीं करना चाहती, वह तो सिर्फ बार बार इस तरह की बात कहती रहती है कि हम इस समस्या को हल करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वह हल नहीं होती इसलिये हम को कहना पड़ता है। सन् १९४८ में प्रधान मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि हम अब इस समस्या का हल करने वाले हैं। उस समय हल नही हुई तो उस के बाद कहा जाता है कि हम उस को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हल कर लेंगे। और अब कहा जाने लगा है कि हम खाद्य समस्या को तृतीय पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक पूरी तरह हल कर चुकेंगे। तब तक हम खाद्यान्न का उत्पादन दूना कर चुकेंगे। लेकिन जिस गति से चला जा रहा है, यदि उसी गति से हम चलते रहे तो किसी भी प्रकार देश की खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती, कोई तरीका नहीं है इसके लिये। जब तक

देश के किसान के दिल और दिमाग में हम इस बात को नहीं पैदा करते हैं कि जो कुछ वह पैदा कर रहा है उस को उस का पूरा बदला मिलेगा, पूरा एवज मिलेगा तब तक देश का किसान कैसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा करने का प्रयत्न करे ? एक ओर तो आप गल्ले के राजकीय व्यापार की योजनायें बनाते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो जूट पैदा करने वाले हैं उन किसानों को उन की पैदावार का पूरा मुआवजा नहीं मिलता है । उन के जूट का खरीदार कोई नहीं है । आज चावल जो देश के खाद्यान्नों का बहुत बड़ा हिस्सा है छत्तीसगढ़ इलाके में पड़ा हुआ है । सरकार ने ६ रु० मन उस को खरीद करने का एलान किया हुआ है लेकिन वहां पर कोई भी उसे ७ रु० मन खरीदने को तैयार नहीं है । जब गेहूं यहां पर ३०, ३२ रु० मन मिलता रहा तो उस का आप इन्तजाम नहीं कर सकते लेकिन चावल को कोई ६ रु० की जगह पर ७ रु० मन भी खरीदने के लिये तैयार नहीं । यह आप की नीति की असफलता नहीं तो और क्या है ? अगर यही हाल बना रहता है तो अगली फसल पर भी गेहूं जो आज २६ रु० मन बिक रहा है उस का भाव २० या २२ रु० मन होगा और उस को लोग १८ रु० और १६ रु० खरीदेंगे । ऐसी हालत में क्या हो ? मौलिक चीज यह है कि जब तक आप खाद्यान्न पैदा करने वालों के लिये यह सुविधा नहीं प्रदान करते हैं कि उस को उस की पैदावार का जो मुआवजा मिलेगा, जो कीमत मिलेगी, उस में जब से खाद्यान्न पैदा होता है और जब तक वह बिकता है इस बीच में ४ नये पैसे प्रति सेर से ज्यादा का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती, तब तक हमेशा भावों में इस तरह के उतार और चढ़ाव आते रहेंगे । खाद्य समस्या को हल करने के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम यह घोषणा करें कि किसान को उस की पैदावार का उचित मुआवजा मिलेगा और किसी भी व्यक्ति को उस में कोई मुनाफा उठाने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

यहां राजकीय व्यापार की बात कही गई है । मैं जानता हूं कि राजकीय व्यापार यहां सफलतापूर्वक चल सकेगा तो वह एक अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे खतरा है कि जिस तरह की हमारी मशीनरी है उस के रहते हुए राजकीय व्यापार हिन्दुस्तान में सफल नहीं हो सकता । इस के लिये आवश्यक है कि जो अपनी मशीनरी है, सरकारी नौकरशाही है, उस में हम अच्छी तरह से परिवर्तन करें । उन के दृष्टिकोण में परिवर्तन आये, जिस की वजह से भ्रष्टाचार चलता है वह कम हो सके । तभी हम खाद्यान्न के राजकीय व्यापार में सफल हो सकते हैं, इस के बिना उस का सफल होना सम्भव नहीं है ।

दूसरी बात उद्योगों के सम्बन्ध में आती है । सरकार की तरफ से कहा जाता है, अभिभाषण में भी, इस की चर्चा की गई कि हम छोटे उद्योगों को पनपाना चाहते हैं, उन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । लेकिन प्रोत्साहन किस तरह से दिया जाता है ? उस का तरीका यह है कि हमारे यहां एक छोटा उद्योग चलता है कांच का । उस की एक नई यूनिट को, जिस की कपैसिटी १२० टन की है उस को आप २० टन बोरेक्स का लाइसेंस देते हैं । अब आप देखें कि लाइसेंस से जो माल मिलता है और जो चोर बाजार में मिलता है उसमें एक हजार रुपये प्रति टन का फर्क है अब दूसरे कारखाने को जिसकी कपेसिटी १५० टन की उसको आप लाइसेंस

[श्री बजराज सिंह]

देते हैं केवल २ टन बोरेक्स का । तो आप देखें कि इस दूसरे कारखाने को कितना नुकसान होगा । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या छोटे उद्योगो को पनपाने का यह तरीका है । उद्योग धधो के मत्रालय का जो डवलपमेन्ट विग यह काम करता है वह डेस्ट्रेक्टिव तरीके से काम करता है । उनका काम यह हो गया है कि किसी तरह से बाजार में कच्चे माल की कमी दिखायें और उसकी कीमत को बढाते चले जायें और जो उद्योगपति है उनसे पैसा वसूल किया जाये, इस तरह से वे उद्योग धंधो को बढावा दे रहे है ?

मैं मानता हू कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना एक अच्छी बात है । जब तक आप इन छोटे उद्योगो को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हिन्दुस्तान में जो बेकारी की समस्या है वह हल नही हो सकेगी । लेकिन यह काम तब तक नही हो सकता जब तक कि कच्चे माल का वितरण ठीक तौर से नही होगा ।

अभी सिलेक्ट कमेटी मे हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेश था । वहा पर यह सवाल उठाया गया कि छोटे उद्योगो को सस्ते भाव पर बिजली उपलब्ध की जाये । लेकिन यह अमेंडमेंट वहा पर नही माना गया । मै नही कह सकता कि वह अमेंडमेंट यहा भी स्वीकार किया जायेगा या नहीं । लेकिन अगर सरकार छोटे उद्योगो को आगे बढाना चाहती है तो उनको बिजली और कच्चा माल सस्ते दामो पर मिलना चाहिए । कच्चे माल के उचित वितरण का यह परिणाम होना है कि एक उद्योगपति तो मुनाफा उठा रहा है और दूसरे को चोर बाजार से माल खरीदना पड़ता है और इस तरह उसे नुकसान होता है ।

बेकारी की समस्या का सवाल आता है । अब तक दूसरे पचवर्षीय आयोजन के तीन साल खत्म हो चुके है लेकिन बेकारी बढती ही चली जा रही है । तृतीय पचवर्षीय आयोजन की रूपरेखा के कुछ सकेत हम को मिलने लगे हैं । उससे भी यह पता नही चलता कि बेकारी की समस्या को हल करने के लिए कोई कारगर कदम उठाये जायेंगे । अभिभाषण में भी यह बात नही है कि सरकार हिन्दुस्तान के हर नागरिक को जिसको काम नही मिलता है और जो काम करने लायक है सरकार काम दिलाने में समर्थ होगी । मैं चाहता हू कि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा हो कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने लायक है उसे काम जरूर दिया जायेगा । जब तक हम यह नही कर सकते तब तक हमारी योजना तो सफल हो ही नही सकती । जब तक हम हिन्दुस्तान की जो जन शक्ति है उसका पूरा उपयोग नही करेंगे तब तक हमारी योजनायें सफल नहीं होंगी । मैं चाहता हू कि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट घोषणा हो जाये कि जो व्यक्ति काम करने लायक है उसे काम देने की जरूर कोशिश की जायेगी ।

और भी बहुत से मसले है । काश्मीर का सवाल है, पूर्व में नेफा का सवाल है । ये दोनो क्षेत्र ऐसे हैं जहा बहुत खतरे है ।

काश्मीर के बारे मे यहा बार बार चर्चा की गयी है कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अग बन चुका है, और काश्मीर के प्रधान मत्री बार बार यह ऐलान कर चुके हैं कि काश्मीर सदा हिन्दुस्तान का अभिन्न अग रहेगा । लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को काश्मीर मे वह अधिकार हासिल नही है जो

कि दूसरे राज्यों में है। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट रूप से यह घोषणा करे कि काश्मीर हिन्दुस्तान का अभिन्न अग है, और इसलिये काश्मीर की भी वही हैसियत होनी चाहिये जो दूसरे राज्यो की है। उसके साथ कोई विशेष व्यवहार नही होना चाहिये। वहा पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का वही अधिकार क्षेत्र होना चाहिये जैसा कि और राज्यो के लिये है। इसका यह तात्पर्य नही है कि मै काश्मीर की सरकार की आलोचना करना चाहता हू। लेकिन मै यह जरूर कहना चाहता हू कि हमे काश्मीर की तरफ से सतर्क रहना चाहिये।

नेफा में डा० राम मनोहर लोहिया को गवर्नर ने यह कह कर नही आने दिया कि आप पहले हमें बताये कि आप यहा आकर क्या करना चाहते हैं। मै सरकार से जानना चाहता हू कि ऐसी कौनसी वजह है कि जिसके कारण लोगो को नेफा एरिया में जाने से मना किया जाता है। यह प्रतिबन्ध क्यो है? क्या पृष्ठभूमि है उनकी कि उनको नही जाने दिया गया? मैं निवेदन करना चाहता हू कि उधर से भी हमको सतर्क रहना चाहिये।

सरविसेज से हमारा क्या सबध है यह भी ठीक तौर से निश्चित हो जाना चाहिये। अभी मथाई काड चल रहा है। सिर्फ इतना ही नही है कि गृह मत्रालय की तरफ से उनके मामले मे सतर्कता नही बरती गयी बल्कि प्रधान मत्री की तरफ से भी सतर्कता नही बरती गयी। श्री मथाई अमरीकन रेडक्रास में ४९८ रुपये मासिक पर काम कर रहे थे। उसके बाद वह प्रधान मत्री के साथ अटैच हो गये और उनको ८०० रुपये मासिक दिये जाने लगे। आज जरूरत इस बात की है कि न सिर्फ इस बात का पता लगाया जाये कि उन्होने इतना रुपया किस तरह इकट्ठा किया बल्कि इस बात की भी जाच की जाये कि हिन्दुस्तान के मत्रिमडल मे कितने लोगो को आने से सिर्फ मथाई साहब की वजह से रोक दिया गया। मथाई साहब का रुतबा इतना हो गया था कि मिनिस्टर लोगो को प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना मुश्किल हो गया था। उन्हें डर होता था कि कही हमें अलग न कर दिया जाये। हम किसी भी व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण नही बनने दे सकते कि जनतत्र को ही उसकी वजह से खतरा पैदा हो जाये। जब कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण बन जाये कि उससे जनतत्र को खतरा हो जाये तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी ही पडेगी, और वह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति के ही बारे में नही होनी चाहिये, बल्कि हमें सारी सरविसेज के बारे में देखना चाहिये कि कहीं और तो ऐसा खतरा नहीं पैदा हो रहा है।

इस लिये मेरा निवेदन है कि हमें इन सब बातो की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये ताकि हम एक अच्छे हिन्दुस्तान का नवनिर्माण कर सकें।

पचवर्षीय योजनाओं को सफल करने के लिये जरूरी है कि जनता का पूरा सहयोग प्राप्त किया जाये लेकिन वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गोली काड होते हैं और व्यक्तियो को जेलो में भेजा जाता है। इस कार्य में सफलता तभी मिल सकती है जब कि सरकार सब का सही रूप में सहयोग ले। हमारे प्रधान मत्री भी कहते हैं और अभिभाषण में भी कहा गया है कि सरकार इस काम मे सब का सहयोग चाहती है। लेकिन मैं यह निवेदन करूगा

Mr. Chairman: The hon Member must look at me when I ring the bell.

Shri Braj Raj Singh: I may submit that nobody has spoken from my party The Speaker was pleased to allot 40 minutes for us I have not taken more than 15 minutes

Mr. Chairman: He has taken more than 15 minutes I request him to conclude now

Shri Braj Raj Singh: No other speaker has been allowed yet to speak from my party. Anyway I am finishing now.

प्रधान मंत्री की तरफ से कहा गया कि वह परियोजना के संबंध में एक सर्वदलीय कमेटी बनायेंगे। कमेटी बनायी गयी लेकिन जिस तरह वह बनी उस पर मुझे आश्चर्य हुआ। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधान मंत्री प्लानिंग करना चाहते हैं उससे हमारा मतभेद है, लेकिन वे हमारी राय भी नहीं लेना चाहते। उस कमेटी में सोशलिस्ट पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं लिया जाता। ऐसी हालत में मैं यह कहना चाहता हूं कि बार बार यह कहना छोड़ देना चाहिये कि हम सब का सहयोग चाहते हैं। सहयोग के मानी यह नहीं है कि सब की आपसे सहमति ही होगी। अगर आप हमारा सहयोग नहीं चाहते तो स्पष्ट रूप से ऐसा कहिये। आपको यह कहना बन्द करना चाहिये कि हम सब का सहयोग चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों का ही सहयोग लेना चाहते हैं जो आपकी नीति का समर्थन करें तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन यह झूठ बात तो न कहें कि हम सब का सहयोग चाहते हैं और साथ ही कुछ को अलग रखें। इसके मानी क्या हैं।

इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करे और हिन्दुस्तान के लिये जो खतरे हो सकते हैं उनकी तरफ मैं उसे आगाह करना चाहता हूं।

Shri Narasimhan (Krishnagiri) Mr. Chairman, Sir, I would like to refer to what my esteemed leader opposite mentioned in the course of the debate yesterday I refer to Acharya Kripalani. I have great respect and regard for him, and we have been knowing one another for a considerable time. But when he referred to the demand for a national Government—he wanted a national Government to take up the country's affairs—I am in the unenviable position of strongly differing from him.

Acharya Kripalani (Sitamarhi): I am afraid this is misrepresentation. I only wanted to tell the House the logic of what the Prime Minister has been saying. I did not bother about a national Government.

Shri Narasimhan: In any case, I think a national Government cannot solve the problems that we are now having before us. It cannot be treated as what, in Ayurveda, we say *Sarva Roga Nivarini*. There is no such *Aushada* and there is no such telisman. Even for political ends, a National Government cannot be a permanent solution and suggested in whatever context, it has to be discouraged. If a national Government has to come in, we have to go to the polls on that issue and without that there is no use resorting to it over the heads of the electorate.

There is a tendency sometimes to take a request from this side for the co-operation of the Opposition side as a sort of invitation to them to the Treasury Benches. I think this is not a good approach and I find . .

The Minister of Agriculture (Dr. P. S. Deshmukh): An invitation should not be misunderstood.

Shri Narasimhan: Yes; invitation should not be misunderstood, as he says Apart from that, since there is a talk about that, I referred to it Acharya Kripalani has explained his position and I do understand now what he really meant when he spoke However, such issues are fairly often posed before the public. Sometimes, whether here or outside, questions do arise whether or not a national Government would solve the present troubles Therefore, there is nothing wrong in my adverting to it as a result of the passing reference which was made.

Acharya Kripalani: But kindly do not bring in my name.

Shri Narasimhan: I have understood his position. I do now understand what he really meant, namely, that he referred to what the Prime

Minister has said, and he developed upon that point. But still, whether now or otherwise, I would like the leaders in this House and the leaders outside the House not to treat the national Government issue as a very good solution. We must learn that in democracy, in the system which we have evolved for overselves, the majority should rule and they have been elected to rule and the Opposition should oppose. That is why they have been elected, and I would not like any of these parties to . . . .

Mr. Chairman: Does the hon. Member expect the Opposition always to oppose?

Shri Narasimhan: I want the Opposition to play its full role of opposition and fulfil the expectations which their electorate have cherished about them. I do not deny that they have a very useful role to play and they have been playing a very useful role also. We have to be told where we are wrong or where we are likely to go wrong. So, the role of the Opposition is very necessary and most welcome even to the ruling party. But any solution which results in some kind of strong invitation from this side or offer from that side in the nature of changing the roles or both identifying together with the governing machinery is not very desirable and I would like that the Constitution and the democratic political set-up which we have set for us should be fully adhered to, unless there is a very rare national crisis. But every time whenever a difficult situation arises, to say that a national government will be a good solution is not good. I would like the leaders both inside and outside this House to remember this; otherwise, it will be a confession on the part of both the parties that they have failed to play their respective roles.

The President has referred to the progress made in the matter of atomic energy. It is very gratifying to note that we are not lagging behind in modern science. Thanks to the great interest which our Prime Minister has taken in the matter of atomic energy and the availability of eminent scientists like Dr. Bhabha, progress is steady and not discouraging.

The President has referred to a quarter million kilowatts of power being produced through nuclear energy. In this context, I would like to remind Government that when these nuclear power plants are located, the eligibility of Madras State should be remembered. Dr. Bhabha was explaining to members yesterday the advantage of utilising nuclear power where hydro-electric or thermal power is not sufficiently available. Madras State has practically exhausted all its hydro-electric power potential. So, it is in the fitness of things that Madras State should be remembered while considering the location of nuclear power plants.

The production of ¼ million kilowatts of power within the period mentioned by the President is rather ambitious. In this context, I would like the Atomic Energy Commission to utilise the services of scientific bodies like the Indian Institute of Science right from now and develop the nuclear research side in as rapid a manner as possible. The Lok Sabha has been kind enough to elect me to the Governing Council of the Indian Institute of Science. From the atmosphere I found there during the Golden Jubilee celebrations, I can say that they are all very eager to serve; they are all very enthusiastic and eminently fitted for it. So, I would like the Government and the Atomic Energy Commission to remember this.

The Indian Institute of Science has been steadily engaged in the investigations about internal combustion engines and they have been progressing fairly well. But suddenly we find that further research on the subject has been transferred to some

[Shri Narasimhan]

centre in Kanpur. I think Government will do well to re-think about it whether or not the Indian Institute of Science itself will be more eligible to continue further research, instead of switching over to some other place. The proximity of Hindustan Aircraft is another advantage.

I really do not know why such sudden changes take place in the location. Suddenly they switch over from extreme south to extreme north and *vice versa*. A few years ago, there was the question of changing the famous Nutrition Research Institute in Coonoor to some other place. Now it comes to our knowledge that in the present location also, they are still finding it difficult to get houses and so on. The other day, there was a reference to the transfer of the Indian Bureau of Mines to Nagpur. The idea in selecting Nagpur was that there were plenty of buildings there. But now they say that construction of buildings in Nagpur is being delayed. I do not know what it really means. If further construction was needed resulting in further delay, we should have discounted that place in the matter of deciding the change. There is almost a kind of mania in the administration to go in for new locations. They are changing many institutions like that.

For instance, there is the Institute of Animal Husbandry in Bangalore; I do not represent Bangalore... ..

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): It is close to your area.

Shri Narasimhan: Suddenly the location of that institute was sought to be changed. When there was some agitation, there was some compromise. Except the big irrigation projects and dams, they want to change the location of everything else. They are not able to change the stone foundations and so dams are not changed. That is the impression which we got when we see attempts being made to change the locations. It all depends on somebody in the Ministry. He is fond of a particular place and he works up towards changing the location to that place.

We are very happy that the big steel projects have come into existence. But there is another kind of disease which I would describe in the Prime Minister's language as 'gigantism'. Every Ministry wants to become like a zamindari with very big projects. Smaller projects are neglected. I am told, in the matter of steel production considerable progress has been achieved in China through small steel plants. The whole country is full of such plants. I was given to understand by an expert that even oil refineries can be set up on the basis of small industries. Such things are said to be found in China. So, I would like Government to pay attention to these small industries.

For instance, the Council of Scientific Research has evolved a suitable type of wind mill. Large number of windmills can be set up in various places where electricity may not be available. All these are forgotten. I would like Government to have a little change of approach to this question. The Prime Minister himself has referred to this and I hope the other Ministries will soon take some sympathetic effort to set up small-scale industries, which will make the entire country feel that something is being done for all of them.

The President has also referred to the fact that the Southern Institute of Technology will also be started soon. It is a very gratifying piece of news. But, in this context it is good to remember the word of caution which Shri C. D. Deshmukh has sounded. As Chairman of the University Grants Commission he has mentioned that the method of admission is not, according to him, quite satisfactory. In the

matter of science there will be a great set-back if the best available talent is not made use of while candidates try to secure admission

In this connection, I would also like to say that though great efforts are being made to create more engineers, a certain amount of unintelligent use of existing personnel is there For instance, engineers are put in positions which are a little below what they are entitled to and what they are capable of. When an ordinary foreign engineer comes here he is put in a very high position You may say that it is due to unavoidable reasons You may say that we get assistance from them, they are in a position to advise us, we have to get their advice, and naturally and necessarily they are put in high positions But there are a large number of such cases where when our own boys have got very nearly equal qualifications they are put below others Thereby a certain amount of inferiority complex is developed Owing to permanancy of jobs in government service engineers seek jobs under Government, but for want of adequate salaries some of them take up private jobs and they get higher salaries This results in an improper and inadequate utilisation of the existing personnel Inferiority complex should not be allowed to set in Everybody must be made to do full work that he is capable of All this will happen only if we really and fully understand the noble roles which our engineering boys have got to play I hope this aspect of the matter will also be attended to

I am very glad that the bauxite project in Salem district has been accepted and finalised Both from announcements and speeches here and in Madras it has now been learnt that things will start quickly After having achieved great success in the matter of steel, the next important mineral is copper Aluminium is a good substitute for copper and the more aluminium we produce the better for our country I am also very glad to learn during today's Question Hour that the Government have accepted the necessity for including the briquetting plant as part of the Neyveli Lignite Project

Shri Nathwani (Sorath) Mr Chairman, Sir, we are grateful to the President for his Address which contains a brief but precise view of our main problems and of our progress in various directions including scientific and technological fields It has been criticised in several respects, but I want to deal mainly with one criticism, and that is the omission of any reference to the bilingual State

But before I deal with this question of Bombay State, I would like to say a few words regarding the main controversy which has raged over this Address It relates to the reference to agrarian reforms Firstly, it has been stated that the reference is rather vague and uncertain But there can be no doubt as regards its true implications That reference has to be studied or read in the light of the Nagpur resolutions passed at the last Congress Session So read, it makes sufficiently clear the Government's intentions regarding these agrarian reforms

Sir, doubts and fears have been expressed and yesterday my hon friend Shri Masani, very eloquently gave expression to some of those fears He said that though there are some points of difference the attempt of the Government is to raise co-operatives which are really collective farms of Chinese type in disguise Again and again it has been stated that there is going to be no compulsion or pressure on the farmers to join these co-operatives Still the charge is being levelled As yesterday my hon friend, Shri Masani, read out a portion of the resolution, I think it would be better to read out further relevant passages from that resolution to show that no sort of compulsion or coercion or pressure is envisaged in this resolution

My hon friend referred to the main part of clause 2 of the resolution dealing with Agrarian Organisational

[Shri Nathwani]

Pattern, but he did not read the last part of the second paragraph. In the second paragraph it is stated that in the first instance service co-operatives should be organised throughout the country. Then it says: "This stage should be completed within a period of three years. Even within this period, however, wherever possible and generally agreed to by the farmers, joint cultivation may be started." Therefore, in this resolution, in this clause in terms, stress or emphasis is laid on agreement by the farmers. In view of this I think there is not much foundation for the apprehensions that have been expressed in this behalf.

Then, there is a reference to the ceilings. I wish to say this, that the ceilings on land-holdings should be at such a level as to attract the energetic, intelligent and hard-working members of the farmers' families; otherwise it may happen that the energetic, intelligent and educated young sons of farmers may leave agriculture leaving to less competent hands their farms.

Criticism has been made, and there is some truth in it, that we should not expect any spectacular results out of this movement because we are suffering from several handicaps The foremost among them is the lack of atmosphere for co-operative farming. Then there is lack of trained personnel and other things, and I do feel that we should not raise high hopes, by way of removing unemployment or otherwise As my hon friend, Shri Masani pointed out, the correct solution would lie ultimately in building up industries, small as well as big, in rural areas.

13 hrs.

There is one more aspect to which I would like to advert and that is this We should safeguard ourselves against the tendency of judging our progress only by comparing it with the achievements made in other countries under totalitarian regimes They have got certain advantages under their system. We have deliberately chosen a different ideology under which we attach great importance to human dignity and human values. Therefore, though it is necessary that we should increase several times our production, both agricultural and industrial, to judge our progress only in terms of progress achieved by a totalitarian regime is not a safe guide.

Having said this, I would like to go to the issue of the State of Bombay. Shri Dange, Shri Indulal Yajnik and Shri Goray pleaded for breaking up the bi-lingual State of Bombay. I will first deal with the speech made by the hon. Member from Ahmedabad. He spoke in the name, and for the people of Gujarat. Let me examine his pretensions, let me show where exactly his party stands, so far as Gujarat is concerned. In my part, in Gujarat, the general elections were fought on the specific issue of bi-lingual State. Here I will cite all the facts. The result was that out of 132 seats reserved for Bombay Legislative Assembly, Congress secured 99 seats. As against that, Shri Indulal Yajnik's party, Janata Parishad, secured only 30 seats, and even these seats were captured by them by exploiting the local sentiments of the people of Ahmedabad where very high hopes were raised about Ahmedabad being made the capital of the unilingual State of Gujarat They also incited the public feelings on the side issue of firing.

In Lok Sabha also out of 22 seats the Congress captured 17 seats. Thereafter, there were District Local board elections, and these are the figures which are very eloquent. Out of 570 seats, the Congress won as many as 507 seats Lastly, after the general elections....

Shri Nath Pai: How many seats were won in another part of Bombay called Maharashtra? Out of 130 seats they lost 110.

Shri Nathwani: I am coming to that. My friend is a good advocate and he knows that I will deal with it item by item. I said I will begin from Gujarat.

Mr. Chairman: The hon. Member has only five more minutes.

Shri Nathwani: I would request you to kindly allow me more time. Because, several hon Members have spoken about breaking up Bombay State I am trying to explain to the House the position as it exists today.

Then, there were as many as six by-elections in Gujarat All these seats were captured by Congress, and three of these seats were held previously by the Janata Parishad This is the position so far as public opinion in Gujarat is concerned.

Now, coming to Maharashtra, even during the general elections the Congress group there also got a comfortable majority as far as seats both in Assembly and in other parts were concerned It may be, my friend only refers to the old Maharashtra. There they did get an overwhelming number of seats; I grant it But you are always emphasising Samyukta Maharashtra. Why don't you take the figures for the whole of Samyukta Maharashtra and see whether during the last general elections. . .

Shri Nath Pai: What about the Marathwada by-election which we have won?

Shri Nathwani: What about the latest Maha Viddharba by-election?

Shri Nath Pai: That was not fought on this issue Let the hon. Member know that.

Shri Nathwani: I will deal with Shri Indulal Yagnik. He has made certain wild statements. He went on to say—I will quote his exact words:

> "The Gujaratis are in a subordinate position. We feel we are, so to say, in an inferior state of citizenship."

Sir, we have no such feelings

Shri P. R. Patel: But what about the words used by the Prime Minister?

Shri Nathwani: In the bi-lingual State the Gujaratis and Maharashtrians are partners. We have accepted gracefully this bi-lingual State when at the behest of prominent Members of the Lok Sabha in 1956 Parliament provided for the bi-lingual State. Our feeling is that of partnership joint venture There is nobody superior or inferior. It is true that Maharashtra is a big partner. That is all that it comes to. That is all that the Prime Minister had said

I now come to the remarks made by Shri Goray. I will quote his own words. Referring to the decision of an overwhelming large number of Members in 1956, he says:

> "every Member who voted for this particular re-organisation of States had given a State for his own language and only denied the State for the two linguistic groups of Maharashtra and Gujarat."

Besides being trumpery, this argument is rather unfair and unjust to the Members of the Lok Sabha in 1956. What were the facts in the year 1956 when those members who voted for the bi-lingual State did not vote for a bi-lingual State for themselves?

Mr. Chairman: The hon. Member is entering into too many details when he is hard up for time He should conclude within three minutes.

Shri Nathwani: I will be very brief But I want to complete the point. I have only briefly adverted to it.

Mr. Chairman: I can give another five minutes, but not more, because there are other Members who are equally interested in taking part.

Shri Nathwani: Again, it was said that there is only one bi-lingual State but they are two—the States of Bombay and Punjab They kept the bi-lingual States, they did not bring about new bi-lingual States That is correct But that was no reason why they should have broken up the bi-lingual States which already existed.

An Hon. Member. What about Karnataka, which was a tri-lingual State?

Shri Nathwani: If I have got the time, I will deal with that aspect also Shri Goray also ignored the vexed question of the city of Bombay It was the real reason why ultimately this bi-lingual State had to be brought about There were several difficulties. Spokesmen of Gujarat and Maharashtra could not agree upon that question There were high-powered commissions and a committee who had held that Bombay could not be a part of any uni-lingual State It was in these circumstances that in 1956 that decision was taken Then, is there any valid reason now to break it up? Has it not functioned well? Even Acharya Kripalani as recently as last month when he visited Ahmedabad paid a tribute to that State and stated that the administration there was the best throughout India If in spite of opposition and agitations which have been kept alive during the last three years Bombay State enjoys the status of being the best administered State, had these hon friends co-operated and tried to harmonise and bring about an atmosphere of goodwill and had they tried to make the administrative machinery more efficient, there would have been no reason left

Shri Nath Pai: How can we make it efficient? Your Party runs the administration

Shri Nathwani: I am saying that in spite of these agitations which have not always been peaceful the State has given the best account of itself under the able and wise leadership of the Chief Minister

Shri Nath Pai: Thanks to the people of Bombay The credit goes to the people

Shri Nathwani: Then think about the serious consequences that will follow if this bi-lingual State has to be broken up This is apart from the tension which may arise between Maharashtrians and Gujeratis It is significant to know that even the leader of the Janata Parishad was not able to say that his party on one hand and the *Samiti*, on the other, have come to any agreed conclusion regarding the city of Bombay, regarding Dang and regarding Nawapur and other parts

I may refer also to the recent election of the veteran leader, Shri Aney, from Nagpur and Vidarbha Whatever else it may mean, it does mean

Shri Jadhav (Malegaon) Out of 9 you lost 8

Shri Nathwani a clear defeat for the *Samiti*, who want the *Marathi* speaking people to be grouped in one State Whether it is a vote for bi-lingual State or not it does mean that the *Samiti* has suffered a singular defeat in the election (*Interruption*)

Mr Chairman: I think the hon Member must conclude now It is better to discuss this in the form of a separate motion During the course of the debate on the President's Address he cannot enter into too many details

Shri Nathwani. I am winding up within two minutes From the national point of view also it would have still wider repercussions It would be something like opening Pandora's box Just as by opening it objects of desires came out and played havoc, here also if you break up the Bombay State many questions of readjustment of boundaries, and of creation of two

separate States in Punjab would arise. Therefore I submit that there is no justification watsoever for reconsidering the entire question."

Mr. Chairman: Shri Vajpayee. He will please take 15 minutes.

Shri Vajpayee (Balrampur): It will not be possible for me to finish in 15 minutes.

Mr. Chairman: There are other occasions also.

Shri Vajpayee:. I am the only speaker from my group.

Mr. Chairman: I will allow him five minutes more.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) It is a one-man group.

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, इस सदन में जब कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, उस समय इस सदन के बाहर देश की जनता जिन दो प्रमुख विषयों पर चर्चा कर रही है वे है अनाज की बढती हुई कीमतें और उनको रोकने मे सरकार की असफलता . .

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : कीमतें गिरनी शुरू हो गई है।

श्री वाजपेयी : और दूसरा है मथाई का मामला । मै दूसरी बात को पहले लूंगा ।

इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए थे कि आफिशल लेवेल पर मथाई के मामले की जाच की जा रही है । मेरा निवेदन है कि यद्यपि श्री मथाई इतने बड़े व्यक्ति नही है जिन के सम्बन्ध मे यह सदन अपना अनमोल समय लगाये लेकिन इस प्रश्न में कुछ सिद्धात निहित हैं जिनका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये । श्री मथाई एक पब्लिक सर्वेंट थे और ऐसी जगह पर थे जहा से वे वह सरकार की नीति और उस नीति से सम्बन्धित व्यक्तियों को बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकते थे । उन्हे प्राइवेट ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी गई । ऐसा क्यों किया गया ? इसके साथ ही उस प्राइवेट ट्रस्ट में एक मिनिस्टर महोदया भी शामिल थीं। गृह मंत्री श्री पन्त ने कल राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया है कि बहुत से मंत्री बहुत से ट्रस्टों में शामिल हैं और उन्होंने गाधी स्मारक निधि और इस जैसे अन्य ट्रस्टों के नामों का उल्लेख किया है । मेरा निवेदन है कि चेचम्मा ट्रस्ट को गाधी स्मारक ट्रस्ट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । यह एक प्राइवेट ट्रस्ट है । इस में केन्द्रीय सरकार की एक मिनिस्टर शामिल हुईं, क्या उन्हें इस की अनुमति दी गई और अगर दी गई तो किस आधार पर दी गई है और क्या सिद्धात की दृष्टि से यह ठीक है कि मिनिस्टर और पब्लिक सर्वेंट प्राइवेट ट्रस्टो मे शामिल हो ? इस प्राइवेट ट्रस्ट ने कौन साबैरिट या चैरिटेबल काम किया है ? अभी तक बताया गया है कि २५,००० रुपये किसी चैरिटी में खर्च किये गये हैं . . .

Shri Subiman Ghose (Burdwan): Charity begins at home.

श्री वाजपेयी . जब कि ट्रस्ट की सम्पत्ति दस लाख रुपये के ऊपर कूती गई है । इस बात की भी जाच होनी चाहिये कि ट्रस्ट को नम्बर ६, ३० जनवरी मार्ग पर बिडला महोदय ने जो ७,२५४ वर्ग गज जमीन उपहार में दी है, उसका वास्तविक मूल्य क्या है । बताया यह गया है कि ७५,००० रुपये मे वह जमीन दे दी गई है । आज दिल्ली में जो जमीन के भाव हैं और जिस भाव पर केन्द्रीय सरकार भी जमीन को बेच रही है, उस के अनुसार उस जमीन की कीमत सात या आठ लाख रुपये होती है । जमीन के अलावा जो उस में भवन बना हुआ है वह अलग है । आखिर ऐसा कौन सा चैरिटी का काम था जिस से प्रेरित हो कर बिडला महोदय ने इतनी बडी धनराशि की जमीन और सम्पत्ति चेचम्मा ट्रस्ट को दे दी ? इस बात की अदालती जाच की जानी चाहिये क्योंकि इस में व्यक्ति का प्रश्न नही, एक सिद्धान्त का प्रश्न है और भविष्य की दृष्टि से पब्लिक सर्वेंट और मिनिस्टर इस तरह के प्राइवेट ट्रस्टो में भाग लें, इसके सम्बन्ध में सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिये । मै तो यहां तक कहने के लिए तैयार

[श्री वाजपेयी]

हूं कि यद्यपि गांधी स्मारक निधि अथवा कस्तूरबा ट्रस्ट जैसे ट्रस्टों के काम अलग हैं लेकिन उन में जो मंत्री सत्तारूढ़ हैं, वे अगर उन से अपने को अलग रखें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। उन में रहने से एक गलत परम्परा का श्रीगणेश होता है, अपने पद के दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है और फिर दूसरे लोगों को उस में से लाभ उठाने का लोभ पैदा होता है। मथाई के मामले से अगर हम इस प्रकार का एक निर्णय ले सकें तो मैं समझता हूं कि वह सही दिशा में निर्णय होगा।

सभापति महोदय, दूसरी बात जो मैं ने कही कि मैं कहना चाहता हूं वह अनाज के दामों के बारे में है। अनाज के दाम बढ़ रहे हैं। अभी रेलवे उपमंत्री महोदय ने कहा है कि अनाज के दाम घट रहे हैं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि किस अनुपात में गिर रहे हैं।

श्री शाहनवाज खां : पैडी १० रुपये मन मध्य प्रदेश में बिक रही है।

श्री वाजपेयी : मध्य प्रदेश की बात मत करिये। आप दिल्ली में बैठे हैं जो कि केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे है, वहां अनाज के क्या भाव है?

गेहूं डेढ़ सेर रुपये का मिल रहा है। अरहर की दाल का भाव रुपये में एक सेर का है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) फेयर प्राइस शाप पर सस्ता बिक रहा है।

श्री वाजपेयी : फेयर प्राइस शाप पर दाल नहीं मिलती है।

श्री राधे लाल व्यास : गेहूं तो मिलता है।

श्री वाजपेयी : राज्य सभा में सरकार से एक प्रश्न पूछा गया कि भाव क्यों बढ़े हैं और उसके उत्तर में हमारे खाद्य मंत्री महोदय ने कहा और प्रधान मंत्री महोदय ने कहा है कि मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों के कारण ये भाव बढ़े हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सदन ने जो सरकार ने मुनाफाखोरों और संग्रहकर्ताओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकार चाहे, वे अधिकार नहीं दिये। अगर दिये, तो अब सरकार किस मुंह से आ कर कहती है कि भाव उन के कारण बढ़ गये? आपने उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? ऐसेंशल कमोडिटीज एक्ट है, नजरबन्दी कानून है और जो समाज विरोधी कार्रवाई करते हैं उन के विरुद्ध आप आगे बढ़िये, यह सदन आपका पूरा समर्थन करेगा, आपको पूरा सहयोग प्रदान करेगा। केवल व्यापारियों पर और संग्रहकर्ताओं पर जिम्मेदारी डाल कर सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती है।

इस सदन में सरकार ने अनाज के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का जो फैसला किया है, उस के बारे में भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि सरकार ने भली प्रकार सोच विचार कर के यह निर्णय ले लिया। अनाज के थोक व्यापार का सरकारीकरण करने के लिए जो फाइनेंसिस चाहियें, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिये और अनाज का संग्रह करने के लिये जिस तरह के गोदाम चाहियें, वे सरकार के पास नहीं हैं और मैं मानता हूं कि वे एक दिन में सरकार पैदा नहीं कर सकती है। जब ऐसी बात है तो फिर अनाज के थोक व्यापार के सरकारीकरण का फैसला क्यों किया गया है और अगर फैसला किया ही गया तो उसकी घोषणा क्यों नहीं रोक दी गई? नवम्बर में घोषणा कर दी गई कि थोक व्यापार का सरकारीकरण किया जाएगा। मगर अभी तक प्लानिंग कमीशन का और फूड मिनिस्ट्री का वर्किंग ग्रुप उसकी डिटेल्स ही तय नहीं कर सका है। क्यों नहीं कर सका है, और अगर उस में कुछ कठिनाइयां हैं तो यह घोषणा करने की इतनी जल्दी नहीं थी। और हमारे प्रधान मंत्री ने एक जिहाद भी शुरू कर दिया और उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री कहते हैं कि क्योंकि सरकार ने थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण का फैसला

किया है, इसलिए अनाज के व्यापारियों ने गल्ला दबा लिया और उस पर बैठ गये। अब इस स्थिति में हमारी सरकार क्या कर रही है? वे गल्ला दबा कर बैठे हैं और हमारी सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठी है? और इस स्थिति में जो उपभोक्ता है और अनाज के उत्पादक हैं, उन दोनो पर सकट आया हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार अनाज सम्बन्धी अपनी नीति के सम्बन्ध मे पुनर्विचार करे।

इस सदन में मै ने यह माग की थी कि जो खाद्य के भिन्न भिन्न क्षेत्र बनाये गये है उन के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार होना चाहिये। मगर खाद्य मत्री ने कहा है कि इसकी कोई आवश्यकता नही है और लोक सभा की बैठक होने से दो दिन पहले जो बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक खाद्य क्षेत्र बनाया गया था, उसको तोड दिया गया। जो तोडा गया, मै समझता हू वह ठीक किया गया। लेकिन अभी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन का पुनर्गठन किया जाना चाहिये। अगर खाद्य मत्रालय उचित समय पर सही नीति अपनाता तो यह सकट पैदा न होने पाता। दिल्ली मे अनाज के भाव क्यो बढे? दिल्ली में सस्ते गल्ले की सरकारी दुकाने चलती थी। मगर उन्हे बन्द कर दिया गया। एक अल्पकालिक प्रश्न इस के बारे मे पूछा गया तो मत्री महोदय ने कहा कि इनकी आवश्यकता नही है। दो महीने बाद इस की आवश्यकता प्रकट हो गई थी जब गेहू के भाव ३२ रु० मन तक बढ गये। इस बात की जाच की जानी चाहिये कि भारत की राजधानी मे अन्न के भावो के लिये कौन उत्तरदायी है। सस्ते गल्ले की सरकारी दूकाने क्यो बन्द हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई नीति नही है और अब सरकार खाद्य के मोर्चे पर अपनी असफलता को छिपाने के लिये दो नारे लगा रही है। मै उन को नारा ही कहता हू। वे सचालित नीति के परिणाम नही हैं। एक नारा है अनाज के व्यापार का सरकारीकरण और दूसरा नारा है सहकारी खेती। कुछ सदस्यो ने कहा है कि नागपुर प्रस्तावो से क्राति हो जायेगी। मैं ने तो कभी इतिहास में नही पढा कि प्रस्तावों से क्राति हुआ करती है। क्राति प्रस्तावो से नहीं होगी, अनाज के भावो को बढने से रोकने में जो सरकार की असफलता है और उस से पैदा होने वाली जो भूख है उससे क्राति हो सकती है। आप ने जो यह कोआपरेटिव फार्मिंग का निर्णय किया है, मै जानना चाहता हू कि उस का उद्देश्य क्या है। क्या आप इस से उत्पादन बढायेंगे? और क्या जिन के पास आज जमीन नही है उन को आप जमीन देंगे? अगर हम उत्पादन की दृष्टि से विचार करे तो हमें स्वीकार करना पडेगा कि जब हमारी कृषि व्यवस्था बदल जायेगी और कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू की जायेगी, तो पहले दो तीन सालो मे एक अस्तव्यस्तता उत्पन्न होगी, जिस मे उत्पादन घटेगा। बाद में जो जाकर वह बढेगा या नही यह कोई निश्चयपूर्वक नही कह सकता। यहा पर दूसरे देशो के उदाहरण दिये जाते है। मै मानता हू कि अन्य देशो में अन्य परिस्थितियो में सहकारी खेती सफल हो सकती है। अगर हम भी लोकतत्र का रास्ता छोड दे और आतकवाद को अपनाये, विरोधी दल समाप्त कर दे, विचारो की स्वतत्रता पर प्रतिबन्ध लगा दे, तो हमारे यहा भी शायद कोआपरेटिव फार्मिंग सफल हो जाय। अगर वह सफल होगी तो लोक तत्र की कीमत पर सफल होगी। यह एक दूसरा रास्ता है। अभी यहा इजराइल के कुछ पार्लियामेंट के मेम्बर आये थे। उन्होंने बताया कि इजराइल मे कोआपरेटिव फार्मिंग सफल हो गई है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इजराइल और भारत की परिस्थितिया अलग है। इजराइल मे तो उन्होने नई समानता लाना शुरू किया। वहा किसानो के पास परम्परा से, पूर्वजो से प्राप्त जमीन और जमीन के साथ उत्पन्न होने वाला प्रेम इजराइल सरकार के मार्ग मे आडे नही आया। भारत की परिस्थिति उससे अलग है और दूसरा सब से बडा कारण यह है कि इजराइल सरकार अपने देश की जनता का विश्वास प्राप्त कर सकी है। नये इजराइल के निर्माण के लिये

[श्री वाजपेयी]

एक नई निष्ठा पैदा कर सकी है। क्या कांग्रेस सरकार पिछले ११ वर्षों में यह निष्ठा पैदा कर सकी है, वह उन प्रवृत्तियों को जगा सकी है जो देश की जनता में एक नये तन्त्र का निर्माण कर सकती है। नागपुर कांग्रेस मे प्रस्ताव पास हुआ, कई गाव मे जुलूस निकले, कई लोगो ने खुशियां मनाई कि एक नई क्राति आ रही है। लेकिन क्या भारत में कही क्राति हो रही है? क्राति ऊपर से नही आती। गावो में क्राति लाने का जो हमारा आज साधन है हमें उस पर विचार करना चाहिये। हमारे प्रधान मत्री स्वप्नदर्शी है, वह सपने देखते हैं। उन की आखो में उज्ज्वल और महान् भारत के बडे गौरवपूर्ण सपने हैं। मगर सपनो को स कार करने के लिये जो सामग्री चाहिये, जो साधन चाहिये, जो कुशल कारीगर चाहिये, जो लगन चाहिये, जो निष्ठा चाहिये, उस का हमारे यहा अभाव है। सरकार में भी अभाव है और जो पार्टी सरकार को चला रही है उस में भी अभाव है। मेरा निवेदन है कि ऐसी परिस्थिति में कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नही होगी। यह कहना कि हम किसानो को जबर्दस्ती शामिल होने क लिये नही कहेगे, यह या तो अपने को धोखा देना है या किसानो को धोखा देना है। अगर आप जबर्दस्ती नही करेगे तो किसान शामिल नही होगे। मैं जानता हू कि आप सीधे सीधे जबर्दस्ती नही करेगे, किसान कोआपरेटिव फार्मिंग में शामिल नही होगे तो आप उस को कर्जा नही देग उसे बीज नही देंगे, पानी की सुविधा नही देग। दिखाने के लिये उस के साथ जबर्दस्ती नही होगी लेकिन उस को झख मार कर कोआपरेटिव सोसायटी मे आना होगा। मिल कर खेती, यह एक बडा खतरनाक प्रयोग है और मेरा निवेदन है है कि देश की खाद्य स्थिति ऐसी नहीं है जिस के साथ प्रयोग किये जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी जो आज तक की परम्परा से चली आई परिस्थिति है और जो नया परिवर्तन हम चाहते है, उन के साथ सगति हो सके। लेकिन मैं यहा पर एक बात स्पष्ट कर दू कि मै लैंड सीलिंग के पक्ष में हूं। भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित होनी चाहिये, लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग नही होनी चाहिये। सुन ने में ही यह बातें परस्पर विरोधी दिखाई देती है।

एक माननीय सदस्य : आधा हां और आधा नही।

श्री वाजपेयी मगर मेरा निवेदन यह है कि जिन कारणो से मैं लैंड सीलिंग का समर्थन कर रहा हू उन्ही कारणो से मैं कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोधी हू। हमारे देश में जमीन कम है, आदमी ज्यादा है और अगर हमे खाद्य का उत्पादन बढ़ाना है तो कम से कम जमीन मे ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहिये, घनी खेती करनी चाहिये। मगर कोआपरेटिव फार्मिंग में खेत बडे होते जायेगे और उन पर किसानों का काम करना उतना ही कम होता जायेगा। घनी खेती के लिये आवश्यक है कि फैमिली फार्मिंग हो चूकि आदमी ज्यादा है इस लिये हम को यत्रीकरण का आश्रय नही लेना चाहिये। अगर हम कृषि का मेकेनाइजेशन करेगे तो हमारे यहा बेकारी बढेगी और उन बेकारो को हम कहा तक काम पर लगायेगे? क्योकि जो उद्योग धधे हम विकसित करना चाहते है वे विकसित नही हो रहे है।

मै इस बात से सहमत हू कि हम कोआपरेटिव्ज का डेवेलप करे, लेकिन वह बीज के लिये, खाद के लिये, कर्जे के लिये, जमीनो को एक साथ मिलाने और किसानो से जमीन को लेने के लिये नही क्योकि इस तरह पर किसानो के ऊपर कोई अमर होने वाला नही है।

एक माननीय सदस्य सर्विस कोआपरेटिव्ज के बारे में रेजोल्यूशन हुआ है नागपुर में।

श्री वाजपेयी : वह तो हुआ है लेकिन उस से तीन साल तक तो कुछ नहीं होगा । इस लिये मेरा निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में और विचार करे ।

एक बात हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे ने नही कही । उन्होने प्रधान मंत्री की प्रशसा की, मगर उन के साथियो की आलोचना की और कहा कि प्रधान मन्त्री की नीति तो सही है मगर उन के साथी उन की नीति का सैवाटेज करते है, गडबड करते है । मैं समझता हू कि यह ऊचे दर्जे की राजनीति नही है । अपने साथियो का चयन प्रधान मत्री ने किया है । लेकिन अगर सभी प्रान्तो मे लैड सीलिंग में देर हो रही है तो क्या हम उस की जिम्मेदारी से प्रधान मत्री को अलग कर सकते है । यह हमारे कम्यूनिस्टो की रणनीति है, स्ट्रेटेजी है कि प्रधान मत्री की तो प्रशसा करेगे और उनके साथियो को भला बुरा कहेंगे । मैं समझता हू कि जो भी नीति निर्धारित होती है वह सयुक्त जिम्मेदारी के आधार पर होती है । जब वह ज्वायेंट रिस्पासिबिलिटी के आधार पर होती है तो उस में से हम किसी को अलग नही कर सकते । अगर मैं प्रधान मत्री से कहू कि वह अपने इस प्रकार के प्रशसको से सावधान रहें तो यह छोटे मुह बडी बात होगी । लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न सफल नही होने दिये जाने चाहियें यह प्रार्थना जरूर करता हू ।

अत में मुझे एक बात और कहनी है । इस सदन मे अनेक सदस्यो न कश्मीर की आन्तरिक स्थिति की चर्चा की है । जो कश्मीर के प्रतिनिधि यहा आये है उन मे से दो ने इस के बारे में कहा है । अगर वह जम्मू कश्मीर की जनता के सीधे प्रतिनिधि होते तो उन की वाणी में अधिक बल होता । मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है और यह दुर्भाग्य है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि ससद् मे चुनाव द्वारा नही चुने जाते, असेम्बली द्वारा चुने जाते है ।

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : असेम्बली भी तो जनता द्वारा चुनी जाती है ।

श्री वाजपेयी . मगर हमारी तरह से और आप की तरह से वह भी सीधे चुन कर आ सकते है । क्या कारण है कि उन का डाइरेक्ट एलेक्शन नही होता । कश्मीर की ऐसी कौन सी विशेष परिस्थिति है। भारतीय सविधान में जब धारा ३७० सम्मिलित की गई थी उस समय श्री गोपालस्वामी आयगर ने सविधान सभा मे यह आश्वासन दिया था कि यह धारा अस्थायी है और शीघ्र ही उस को सविधान में से निकाल दिया जायगा । अब उस धारा का आश्रय लिया जाता है, कहा जाता है कि काश्मीर मे विशेष परिस्थिति है । हमारा चुनाव आयोग सूडान में चुनाव कराने के लिए जा सकता है किन्तु काश्मीर में नही जा सकता । क्यो नही जा सकता जब कि काश्मीर वैसा ही है जैसा कि बम्बई, मद्रास या बगाल ? हमारे सुरक्षा मत्री श्री कृष्ण मैनन और काश्मीर के मुख्य मत्री, मैं उन्हे काश्मीर का प्रधान मत्री नही कह सकता क्योकि देश मे एक ही प्रधानमत्री हो सकता है दो नही, कहते है कि काश्मीर तो वैसे ही मिल गया है जैसे कि बम्बई । अगर ऐसा है तो मै जानना चाहता हू कि हमारा चुनाव आयोग काश्मीर मे क्यो नही जा सकता, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काश्मीर में वह अधिकार क्यो प्राप्त नही है जो कि भारत के अन्य राज्यो मे प्राप्त है ।

अभी काश्मीर के टाउन एरिया कमेटियो के चुनावो मे गडबडिया हुई, धाधलिया हुई । पर का मीर के प्रतिनिधि ने कहा कि धाधली नही हुई । लेकिन मै पूछता हू कि अगर धाधली नही हुई तो बख्शी सरकार ने उनकी जाच के लिए एक मजिस्ट्रेट को क्यो नियुक्त किया । जब मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया तो इसका मतलब है कि धाधलिया हुई और ये धाधलिया तब तक होती रहेगी जब तक की काश्मीर और शेष भारत के बीच भेद बनाये रखा जायेगा। जम्मू काश्मीर का भारत के साथ पूरी तरह सम्बन्ध होना चाहिये। धारा ३७० को भी सविधान से निकाल देना चाहिये और जम्मू काश्मीर की जनता के मन में भारत के विरोधियो को यह

[श्री वाजपेयी]

भाव भेद पैदा करने का मौका नही देना चाहिए कि काश्मीर का भाग्य अधर में लटक रहा है।

Mr. Chairman: The hon Member's time is up. When I ring the bell, the hon. Member should look at the Chair. I would request the hon. Member to conclude.

Shri Vajpayee: I shall conclude within two minutes.

एक बात इस सम्बन्ध में मै स्पष्ट कर दू। जब हम बख्शी सरकार की आलोचना करते है तो पाकिस्तान के अखबार और पाकिस्तान का रेडियो उसे बहुत उछालते है। लेकिन मै पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि बख्शी सरकार से जो हमारे मतभेद है वे घरेलू मतभेद है, आन्तरिक मत भेद है। लेकिन जहा तक जम्मू काश्मीर को भारत में मिलाने का सवाल है या जैसा कि कल काश्मीर की महिला प्रतिनिधि ने कहा काश्मीर का जो तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको पाकिस्तान से छुड़ाने का सवाल है, उस में हमारा कोई मतभेद नही है, देश मे जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे नेशनल कान्फ्रेस हो, चाहे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे काग्रेस पार्टी हो, चाहे जनसघ हो, सब इस बारे मे एक मत है और इस बारे मे आपस मे कोई मत भेद नही है। इस बारे मे पाकिस्तान को किसी मुगालते मे नही रहना चाहिए क्योकि इस बारे में हम सब एक है। हमारे आपस म मतभेद हो सकते है और उनको दूर करने का हम प्रयत्न करेंगे और हम आशा करते है कि हमारी सरकार भी काश्मीर के मामले मे हस्तक्षेप करेगी और बख्शी सरकार भी समय रहते चेतेगी।

इन शब्दो के साथ मे आपको धन्यवाद देता हू।

श्री चुन्नी लाल—(अम्बाला—रक्षित-अनुसूचित जातियां) सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव चल रहा है उसका मै समर्थन करता हूं और राष्ट्रपति जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अपना अभिभाषण दिया है वह देश को प्रोत्साहन देने वाला है और उस से बड़ी आशायें झलकती है।

13 30 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

देश मे जो तरक्की के काम हुए है उस अभिभाषण मे उनका जिक्र किया गया है और उस से देश वासियों को पता चल गया है कि देश भविष्य में बहुत तरक्की के रास्ते पर पहुंच जायेगा और जो देश की बहुत सी समस्यायें है वे सुलझ सकेगी।

प्रस्ताव पर कई प्रकार की बातो का जिक्र हुआ। सब से ज्यादा जिस बात का जिक्र हुआ वह फुड प्राबलम है। मै इस सम्बन्ध मे अर्ज करना चाहता हू कि हकीकत यह है कि देश की फिजा कुछ खराब की गयी। कुछ उलटे सीधे प्रोपेगेंडे किये गये जिस के कारण जो लोग थोडा थोडा खरीदते थे सब ने अपनी ताकत के अनुसार ज्यादा से ज्यादा खरीद खरीद कर अपने घर मे अनाज को भरा, इसके अलावा जो बडे बडे जमीदार थ जिन के पास अनाज था और जो बडे बडे डीलर थे जिन के पास अनाज था, उन्होने मुनाफाखोरी की खातिर उसको अपने पास रखा। जब कोई फिजा खराब हो जाती है तो इस प्रकार की स्थिति का आ जाना एक लाजमी बात होती है। उसको हल करने वाली बात बहुत कम हो रही है। मै यह समझता हू कि फुड के बारे मे जो एजीटेशन चल रहा है उस से यह स्थिति हल होने वाली नही है। यह तो सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए एक ढग निकाला हुआ है।

इस सिलसिले मे मै यह अर्ज करना चाहता हूं कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग है जिन के पास अनाज है और सरकार को चाहिए कि उस अनाज को प्राप्त करके जनता के सामने

जाये ताकि यह जो अनाज की स्थिति है वह ठीक हो सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर की जो स्थिति है उस में तो यह है कि अनाज किसी प्रकार से लिया जा सकता है, लेकिन इस वक्त देहातो में जो हाल त हैं वे बहुत ही निराशाजनक हैं । देहात में जो मजदूर और गरीब लोग हैं उनको अनाज नही मिल पाता । गावो के जमीदारो ने अनाज बेचना या देना बन्द कर दिया है और वे गरीब लोग बडी मुश्किल में हैं । उनकी तरफ खास तौर से सरकार का ध्यान जाना चाहिए ताकि उनके पास भी अनाज पहुच सके ।

इसके साथ साथ ही ज। अनाज की पैदावार मे कमी है उसके कई कारण है । हमारी सरकार काफी अरसे से लैंड रिफार्म की बात कहती आ रही है । लेकिन इस दिशा में अभी तक कुछ नही किया गया है, सिर्फ कागजी कार्रवाई ही हुई है। लैंड सीलिंग की बात भी सरकार काफी अरसे मे कह रही है, लेकिन लैंड सीलिंग भी अभी तक नही हो पायी है । सब लोग आज इस बात को मानते है कि लेड सीलिंग होना जरूरी है और यह देश के हित के लिए है, लेकिन फिर भी वह बात इस तरह से चलती है कि कोई प्रगति नही हो रही है । सरकार के इस बारे मे ढिलमिल इरादे है । मै यह दरख्वास्त करना चाहता हू कि जो भी कोई बात सोची जाय उस पर अमली तौर से और मजबूत इरादे से काम किया जाये ।

दूसरे बहुत सारी वेस्ट लैंड पडी है । मै समझता हू कि देश की पैदावार बढाने के लिए. यह बहुत आवश्यक है कि उस जमीन को जो भूमिहीन खेतिहर है उन मे जल्दी से जल्दी वितरित कर दिया जाये ताकि वे देश की पैदावार बढा सकें ।

इसके अलावा ज्वाइंट कल्टीवेशन की बात हमारे सामने है । मै समझता हूं कि वह एक अच्छा सुझाव है । उस से हमारी पैदावार पर एक अच्छा असर पडेगा । उस से हमको लाभ होगा । हमारे सारे किसान मिल करके खेती कर सकेगे । और उनकी लागत कम आयेगी । तो हमे इस मसले में भी सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये ।

दूसरी बात करप्शन की है । यहा पर उसकी काफी चर्चा चलती है और यह कहा जा सकता है कि करप्शन काफी है । मै भी इस बात को मानता हू कि करप्शन की कमी नही है । आज चारो तरफ करप्शन ही करप्शन नजर आता है । गैर पैसे के, बगैर रिश्वत के काम नही होता । जो जहा बैठा हुआ है वह वहा पर पैसा बनाने में लगा हुआ है । इस सिलसिले मे मै यह अर्ज करना चाहता हू कि इसका इलाज यह है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाए । आज सब तरफ पैसा कमाने और मुनाफाखोरी की तरफ जो दौड-धप हो रही है और लोग नाजायज तरीके से रुपया कमाने की कोशिश कर रहे है, जिसकी वजह से इस देश का नैतिक चरित्र गिर रहा है, वे सब बुरी प्रवृतिया इनकम पर सीलिंग लगाने से दूर हो सकती है । आज देश मे यह धारणा पैदा हो गई है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही इज्जत है । इस धारणा को दूर करने के लिए यह निहायत जरूरी है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाए ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक बात का जिक्र नही हुआ, जिस की तरफ मै सदन का ध्यान दिलाना चाहता हू और वह यह है कि आज इस देश मे करोडो की तादाद मे ऐसे लोग बसते है, जिन की हालत अच्छी नही कही जा सकती है, जो सामाजिक और राजनैतिक तौर पर अभी भी बहुत दबे हुए है और जिन की माली हालत तो बहुत ही खराब है । खाने की बात तो अलग रही, उन को बहुत से गावो में पीने के लिए साफ-सुथरा पानी भी नही मिल पाता है । यही नहीं, कास्टिज्म का जहर

[श्री चुनी लाल]

इतना फैल गया है कि लोगों को वहां पर काम भी नहीं मिल पाता है और रोज़ाना उन पर जुल्म और ज्यादतियां देखने को आती हैं। अब लोगों की दशा अभी तक सुधर नहीं पाई है, हालां कि हमारी सरकार ने उन को बहुत सी सहूलियतें दी है। भारत के करोड़ों लोग अभी तक इस मुसीबत के शिकार है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डिस्प्लेस्ड लोगों के लिये कार्य किया गया है, जब तक इन लोगों के लिए भी उसी तरीके से कार्य नहीं किया जायगा, तब तक वे उन्नति नहीं कर सकेंगे।

जितने कामन वेल्थ हैं, हरिजन अभी भी उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कामन वैल्थ तो सिर्फ़ नाम के लिए हैं। इस मामले में दुगना खर्च हो रहा है। उन के लिए अलग कूएं बनते हैं। जो हरिजनों की अलग अलग जातियां हैं, उन के लिए भी अलग अलग कूएं हैं। इस से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से हमारे देश में भेद-भाव की भावना बढ़ती जा रही है। पहले लोग यह सोचते थे कि हरिजनों को अलग कर दिया जाए और उन के लिए कुछ सहूलियतें मुकर्रर कर दी जायें, ताकि वे कुछ फ़ायदा उठा सकें, लेकिन मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि उन में भी बड़ा भारी मत भेद है और उन में सत्ताधारी जाती दूसरों को उसी दृष्टि से देखती है, जिस प्रकार कि पहले दूसरी सवर्ण जातियां उन को देखती रही है। यह स्पष्ट है कि जात-पांत—कास्टिज्म—देश के लिए हितकारी नहीं है, इस लिए उस का खण्डन होना चाहिए और जात-पांत अब ज्यादा देर तक नहीं चलनी चाहिए, ताकि देश को एकता की लड़ी में पिरोया जा सके। आज जात-पांत बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस को बहुत जल्दी खत्म किया जाना चाहिए, ताकि हमारे आपसी मत-भेद खत्म हो सकें और यहां पर एक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

समाजवाद की भी चर्चा की जाती है और हमारी सरकार ने तृतीय पंच-वर्षीय योजना में यह लक्ष्य स्वीकार किया है कि इस देश में समाजवाद लाना है। यह समझ में नहीं आता कि इस ओर हम कितना आगे बढ़ सके हैं और हम ने कितना रास्ता तय किया है। समाजवाद का ज़िक्र काफ़ी अर्से से किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस तरफ़ हमारा कदम बहुत ही कम उठा है और समाजवाद को लाने की तरफ़ हम कोई मज़बूत कदम नहीं उठा सके हैं, जिस से हम सोच सकें की वास्तव में समाजवाद जल्द आने वाला है। तृतीय पंच-वर्षीय योजना में यह ज़िक्र किया गया है कि समाजवाद लाने के लिए सरकार असमानता *की दूर करने का प्रयत्न करे, लेकिन साथ* हम देखते हैं कि अमीर लोग सब तरफ़ छाए हुए हैं। उन की अमीरी को कम करने का तरीका यही है कि इनकम पर सीलिंग लगा दी जाए।

आखिर में मैं अन-एम्पलायमेंट का ज़िक्र करना चाहता हूं। यहां पर आम तौर पर ज़िक्र उन लोगों की अन-एम्पलायमेंट का होता है, जो कि शहरों में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं और जिन के नाम एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज होते हैं। असल बात यह है कि ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देहात में रहती है, जिन को काम नहीं मिलता है। उन की समस्या बड़ी जटिल है। उन लोगों की तरफ़ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। उन को रोटी तक नसीब नहीं होती है। अगर ऐसे लोगों की तरफ़ हमारी सरकार का ध्यान न जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि उन का क्या हाल हो सकता है। मैं सरकार से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जो करोड़ों की तादाद में बेकार लोग देहात में रह रहे हैं, जो कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज नहीं करा पाते, उनका खास ध्यान रखा जाए। अगर उन बेकार लोगों की कोई यूनियन बन जाए, तो उस को सम्भालना बहुत मुश्किल हो जायगा। इस लिए उनकी बेकारी का खास तौर पर ध्यान रखा जाए।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं ।

श्री अचिंत राम (पटियाला): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे मौका दिया । इस के साथ ही मैं सब को बधाई देता हूं कि आज हम इस सदन में प्रैजिडेंट के एड्रेस पर चर्चा कर रहे हैं--—यहां पर हक में बोलने वाले भी हैं और खिलाफ़ बोलने वाले भी हैं । इस सिलसिले में मैं सोचता हूं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि प्रैजिडेंट का एड्रेस पढ़ा जाय और तमाम लोग उस पर बहस करें, और क्या मिस्र, सूडान और दुनिया के और बहुत से हिस्सों में ऐसा हो रहा है, तो मुझे इसका जवाब नफी में मिलता है । मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी धन्यवाद देता हूं कि उन की हस्ती की वजह से यहां पर ऐसे हालात हैं कि हम सब अपने इख्तिलाफात जाहिर कर रहे हैं । यही नहीं, बल्कि जिन की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं, हम उन पर भी हमला कर सकते हैं । यह बड़ी खुशी की बात है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उस ने हिन्दुस्तान में ऐसे हालात पैदा किए ।

कुछ स्पीचिज को सुन कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि शायद कुछ लोग ग़लतफ़हमी में हैं । वे कहते हैं कि यहां पर सिचुएशन सीरियस नहीं है । कांग्रेस बैंचिज से यह बात कही गई । मैं इस के बारे में अपनी तुच्छ राय प्रकट करना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद कभी सिचुएशन ऐसी सीरियस नहीं हुई, जितनी कि अब है । यह मेरी आजादाना राय है पहले शहरों में स्ट्राइक्स, हड़तालें और जलूस वगैरह होते थे, लेकिन आज गांवों का दबा हुआ आदमी भी, जो कि और दब रहा है, रोता है । वह बंधा हुआ है और उस के लिए कोई रास्ता नहीं है । खाने के लिए उस के पास कुछ नहीं है । वह तबाह हो रहा है । पंजाब पहले एक सरप्लस सूबा था, लेकिन आज वहां गेहूं दस या पंद्रह रुपये मन नहीं, बल्कि पच्चीस, तीस और पैंतीस रुपये मन के हिसाब से बिक रहा है । इस लिए सिचुएशन बहुत ही सीरियस है । कांग्रेस के--गवर्नमेंट के आदमी कहते हैं कि यह मामूली बात है, सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है । मेरी राय यह है कि वे बिल्कुल ग़लत-फ़हमी में हैं । मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूं कि आज आटे के लिए क्यू लगी होती है । एक आदमी जोकि तीन रुपये, ढाई रुपये और दो रुपये रोज के कमाता है वह अपनी सारी दिहाड़ी को खराब करके दस सेर आटा ही खरीद पाता है । कितनी मुसीबत उस पर आती है या कितनी मुसीबत का सामना उसे इस तरह से करना पड़ता है, इसका अंदाजा आप आसानी से ही लगा सकते हैं । तीन रुपये गुम करके वह दस सेर आटा लाता है । दस सेर आटा लेने का वह तीन रुपये आप टैक्स समझ सकते हैं ।

आप यह कहते हैं कि गांव वाले और बाहर के जो स्टाकिस्ट हैं वे अपना स्टाक सरेंडर कर दें । वे लोग कहते हैं कि स्टाक है ही कहां जो हम सरेंडर करें । आन दी फेस आफ इट यह कितनी गलत बात है । कल मैं पटियाला में था । वहां अनाज २४ रुपये और २५ रुपये मन बिक रहा था । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर स्टाक नहीं है तो यह अनाज आ कहां से रहा है और कैसे यह बिक रहा है ? एक आदमी ने मुझे कहा कि यह स्टाक एक दिन में निकल कर बाहर आ सकता है । उसने कहा कि जितने भी पाडी हैं, जितने भी गेहूं को ढोते हैं, उनको एक दिन इकट्ठा आप कर दें और उनसे पूछें कि स्टाक कहां है और वे आपको सब कुछ बता देंगे और जितना भी स्टाक है वह दस मिनट के अंदर बाहर निकल आयेगा । लाखों मन गेहूं इस तरह से खुले बाजार में बिक रहा है और वे लोग कहते हैं कि स्टाक नहीं है । अगर स्टाक नहीं है तो कहां से यह गेहूं आता है । इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यह गलत बात है अगर यह कहा जाये कि गन्दम नहीं

[श्री अर्जुन राम]

है । मेरी नाकिस राय यह है और लोग भी यह समझते है कि इट इज नाट ओनली ए फैमिन आफ फूड बट इट इज ए फैमिन आफ फोरसाइट एंड ए फैमिन आफ फेथ इन दी गवर्नमेंट ।

It is not only a famine of food, but it is a famine of foresight, and a famine of faith in the Government.

आज आपने डिपू खोले है । मै पूछना चाहता हू कि इनको छ. महीने पहले क्यों नही खोला गया ? आज आपने इनको क्यो खोला है और क्यों इसकी आज ही आपको सोच आई है ? यह किसी से गिला करने की बात नही है । हमारे जैन साहब रिहैबिलिटेशन के मिनिस्टर भी रह चुके है और मेरा उनसे वास्ता पडा है और मैंने उनसे मुखालिफ राय भी रखी है, लेकिन इतना होने पर भी मैंने उनकी हमेशा प्रशसा की है । लेकिन आज दुनिया का यह आम खयाल है कि फूड मिनिस्ट्री हैज फेल्ड, फेल्ड, एंड फेल्ड । लेकिन इस बात को कोई सुनता ही नही है । मै तो कहूगा कि सारी पालिसी जा चल रही है वह इसी तरह से चल रही है । पहले क्यो नही इन सब बातो को सोचा गया था और क्या इस तरफ आज ही आपका ध्यान आया है ? मै अर्ज करना चाहता हू कि आप गलतफहमी मे न रहे और जो मरे हुए आदमी आज है और जिनके दाये बाये कोई दोस्त नही है, वे भी एक दिन उठ सकते है, वे भी फूट पड सकते है और बहुत बुरी हालत में पागल हो सकते हैं । यह तो मै गेहू के बारे मे कहना चाहता हूं ।

अब मै कोआपरेटिव्ज के बारे मे कुछ कहना चाहता हूं । बहुत सोच विचार के बाद आपने एक हल निकाला है और वह भी बहुत देरी के बाद । दस साल के बाद तो यह हल निकाला ही गया है । इस चीज के बारे में मै जो कुछ विनोबा भावे जी ने कहा है वही मैं निवेदन करना चाहता हूं । उन्होंने कहा है :—

> "मै अगर सरकार में होता तो कहता कि सरकार ऐसी सहकारी मंडली को मान्यता दे कि जो दाखिल होने से पहले अपनी जमीन की मालिकी गाव के हित में विसर्जित करे ।"

लेकिन आपकी स्कीम के मुताबिक तो जो इनइक्वैलिटी है वह बनी रहेगी । एक आदमी होगा जिसकी दा ए ड, एक एकड या इससे कम जमीन होगी और दूसरा होगा जिसकी एक हजार और पाच सौ एकड जमीन होगी । अब जिसके पास कम जमीन है वह गरीब है लेकिन इस स्कीम से तो वह गुलाम भी बन जायेगा, स्लेव भी हो जायेगा जो कि वह पहले नही था । ऐसी सूरत मे सहकारी खेती कैसे चलेगी, यह इमपोसिबल है । जब तक इक्वैलिटी की भावना नही आयेगी और जब तक एक हजार और पाच सौ और दो सौ एकड वाले रहेगे तब तक शान्ति कैसे स्थापित होगी और उस गरीब आदमी को देगा कौन । यह बात मैंने अपनी नही विनोबा भावे जी की आपको सुनाई है । इसको आप जितनी वैल्यू अटैच करना चाहते है करे । मै तो समझता हू कि आज वही एक आदमी है जो कि लोगो की पल्स को टच करता है । और भी बडे बडे आदमी हो सकते है जो जनता को समझते हो और इसमे कोई शक वाली बात भी नही है लेकिन जनता की पल्स को वह बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और उसी का यह स्टेटमेंट है कि यह सहकारी खेती कामयाब होने वाली नही है । इससे हो सकता है कि शोषण का एक और जरिया निकल आये । आप तजुर्बा करना चाहते हैं और आप कर

भी सकते हैं, लेकिन यह उनकी राय है। मैं कोई बहुत तजुर्बेकार नहीं हूं। आपको चाहिये कि आप सोच समझ कर चलें और देखें कि गरीब आदमियों का एक्सप्लायटेशन न हो। अब तो वे लोग दम तो ले पा रहे हैं और बाद में कहीं ऐसा न हो कि वे दम ही तोड़ दें।

तीसरी बात मैं आप जो फौजों पर रुपया खर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कहना चाहता हूं। एक तो आप एक डेढ़ अरब रुपये का गेहूं बाहर से मंगा रहे हैं और दूसरे आप कोई तीन सौ करोड़ रुपये फौज पर खर्च कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत क्या है, क्यों यह किया जा रहा है? ये फौजें किसके हमले से बचाव के लिये रखी जा रही हैं? क्या अमरीका की तरफ से हमला हो, तो बचाव के लिये है? अमरीका बहुत शक्तिशाली देश है और उसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से इंगलैंड के हमले का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर इनको मुकाबला किस तरफ से हुये हमले का करना है। यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से हुये हमले का इनको मुकाबला करना है। पाकिस्तान का हमला और इतना अधिक खर्च? आज पाकिस्तान कितना अपनी फौजों पर खर्च कर रहा है? वह तो सौ करोड़ के करीब कर रहा है और आप तीन सौ करोड़ रुपया, यह क्या बात हुई? पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है और हिन्दुस्तान बड़ा। पाकिस्तान की फौजें तो बहुत ही जबर निकलीं। उसको वहां पर मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए रखा गया था और उसने अपने ही मुल्क पर हमला कर दिया। ऐसा मालूम होता है कि उसकी अपनी फौज नहीं है। इसके मुकाबले में आपकी जो फौज है वह देशभक्त है, लायल है और यह खुशी की बात है। क्लाइव और मीर जाफर की फौज में भी लड़ाई हुई थी और आप जानते ही हैं कि जीत किसकी हुई। फौज ज्यादा हो तभी मुकाबला किया जा सकता है, यह धारणा गलत है। यह मनजुम होनी चाहिये, डिसिप्लिंड होनी चाहिये और इसी को देखना हमारा फर्ज है। थोड़ी सी फौज का मुकाबला करने के लिये इतनी बड़ी फौज और वह भी उस फौज के खिलाफ जो खुद-गर्ज है, समझ में नहीं आता है। आप अमरीका का, इंग्लैंड का, रूस का, फ्रांस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिये ही आपने फौज रखी है ले दे कर और पाकिस्तान जब कि सौ करोड़ रुपया खर्च करता है, वहां आप तीन सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं। आपकी फौज बेटर आर्गेनाइज्ड है, ज्यादा लायल है, ज्यादा देशभक्त है और इतना होने पर भी इतना ज्यादा खर्च करना, यह बात कतई समझ में नहीं आती है। यह चीज तो यह साबित करती है कि आपको पाकिस्तान से तीन गुना डर है। यह तो डर को बढ़ाने वाली बात हुई, घटाने वाली बात नहीं। आज आप एक तरफ इतना अधिक रुपया अनाज मंगाने पर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ इतना रुपया फौजों पर कर रहे हैं। ऐसी सूरत में सोचने वाली बात यह है कि आया हमें इतना फौज पर खर्च करना है या नहीं करना है और अगर नहीं करना है तो कितना कम खर्च करना है या बिल्कुल नहीं करना है। आपको यह भी ख्याल करना होगा कि इसका असर क्या पड़ता है देश के ऊपर और साथ ही साथ आज हमारे देश की हालत क्या है। ये सब बातें हैं जिन पर अच्छी तरह से सोच विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी सूरत में अगर और कुछ नहीं तो आप फौज पर दो तिहाई खर्च कम कर ही सकते हैं।

14 hrs.

अब मैं फाइव यीअर प्लान के बारे में दो एक शब्द कहना चाहता हूं। इस प्लान के

[श्री अचित राम]

बारे में जो कुछ विनोबा जी ने कहा है वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वह कहते हैं :—

"It is generally said that the First Five Year Plan is completed. But what is completed is in fact the plan-period and not the plan-target. People's cooperation was lacking in the execution of the plan".

बैनिफिट की बात उन्होंने आगे चल कर की है। वह कहते हैं कि प्लान का पीरियड तो खत्म हो गया लेकिन टारगेट्स अचीव नहीं किये गये। ये उनके शब्द हैं जो कि निष्पक्ष आदमी हैं, जो कि पंडित जी से बहुत मुहब्बत करता है और जिनको मिलते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आज गांव गांव में घूमता फिरता है और सभी चीजों को देखता फिरता है। वह कहता है कि लोगों की कोआपरेशन नहीं है, पीरियड तो खत्म हो गया है। उनकी बात का यह असर हुआ है कि अब सरकार यह महसूस करने लग गई है कि प्लान ऊपर से बन रहा है, लोगों की राय से नहीं बनता है, इसलिये इसको लोगों की राय से बनना चाहिये। यह लोगों की राय की जो बात है, इसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। बसी में अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी और मैं भी उसमें गया था। उसमें अफसरों ने कहा कि उनकी मर्जी से ही प्लान बनेगा और उनकी मर्जी से खर्चा होगा। यह सुन कर मुझे बड़ी खुशी हुई। डेढ़ सौ या दो सौ गांवों से आदमी आ कर वहां बैठे हुये थे। जो आदमी मीटिंग एटेंड करने के लिये आये वे बहुत कम तादाद में आये। दस दस मील से वही आदमी मीटिंग एटेंड करने आ सकता है, जिसके घर में खाने के लिये हो और जिसके घर में खाने को आटा न हो वह कैसे आ सकता है। जो व्यक्ति हर रोज कमाता है और हर रोज ही खर्च कर देता है, हाऊ कैन ही एफोर्ड टू वेस्ट ए डे फार दी मीटिंग; इट इज इम्पासिबल। [How can be afford to waste a day for the meeting; it is impossible.]

जिसके पास अच्छे कपड़े पहनने को हैं, जिसके पास अच्छे पैसे हैं वही वहां आ सकता है और जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, वह कैसे आ सकता है, यह पासिबल नहीं है। फटे हुये कपड़ों में कैसे कोई आयेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग है यह ऊपर से ही, दस गज ऊपर से ही, होता है, नीचे वाले लोगों तक नहीं आ पाता है। इस वास्ते मैं कहूंगा कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। साथ ही आप जो कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं, इसका क्या असर होगा, इस पर भी आपको विचार करना होगा। यह रुपया उसी तरह से लोगों को टच नहीं करता है जैसे कि आप एक बरतन में जिसके नीचे छेद हो, पानी डालते जायें और वह पानी उस बरतन में रह ही नहीं पाता है। ऐसे रुपये को आप लेकर क्या करेंगे जब कि यह लाखों और करोड़ों लोगों को ही कोई लाभ नहीं पहुंचायेगा? पेवमेंट हो रहे हैं गलियों के। लेकिन गांव के रहने वालों का इन पेवमेंट्स से क्या भला होगा। किसके लिये गलियां बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं? मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि असल बात यह है कि जब तक आप प्लैन गांवों के लिये नहीं बनायेंगे तब तक आपकी प्लैन कामयाब नहीं हो सकती। हर गांव के निवासी प्लान करें—जिस गांव में बगैर जमीन वालों और बगैर मकान वालों का सहयोग नहीं है वह प्लैन मंजूर न किया जाया करे, हर गांव के अन्दर जो भी जमीन और जितने मकान हैं सब आप उनके सुपुर्द कर दें। तभी आपकी प्लैनिंग चल सकती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि नेगोशिएसन्स हो रहे हैं, सहायता ली जा रही है। जापान हमारी मदद को आयेगा, बड़ी खुशी की बात है। इंग्लैंड भी दे देगा। लेकिन आखिर यह कर्जा वापस कैसे करेंगे? कहते हैं कि उनके पास कोई रिट्रेंच नहीं है। हो

सकता है कि कोई स्ट्रिंग न हो, लेकिन फिर भी इस रुपये को अदा तो करना होगा। आखिर कौन इस रुपये को अदा करेगा, किसके सिर पर यह बोझ है। दे हैव नो स्ट्रिंग्स फार दि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया। लेकिन फर्ज कीजिये कि वे लोग आपसे रुपया मांगते हैं तो यह कह देंगे कि फसल नहीं हुई, बारिश हो गई, ओला पड़ गया इस वास्ते अनाज नहीं हुआ। आप आज कहते हैं कि दस वर्षों से ओला पड़ रहा है या बाढ़ आ रही है और इसलिये अनाज बाहर से आ रहा है। अगर कहीं दस बीस बरस और भी ओला पड़ने लगे तो क्या होगा? अगर अमरीका कहने लगे कि जो कुछ तुम्हारे पास हो हमको दो, हमने तुमको रुपया दिया है, तो आप क्या करेंगे? हम इन्तजाम करेंगे दस सालों में, वे कह सकते हैं कि हम आपके मुल्क का इन्तजाम करेंगे, जरा इसको भी तो सोचिये। इस-लिये मैं कहता हूं कि आप जरा सोच समझ कर कर्जा लीजिये। कहीं ऐसा न हो कि वह हम पर और ज्यादा मुसीबतें ले आये। आप तो चले जायेंगे लेकिन आने वाली नस्लें हमको कोसेंगी कि हम लोग कर्जा लेते रहे और उनकी मुसीबत बढ़ाते रहे। इसलिये जरा समझ से काम लीजिये। मैं समझता हूं कि कंडिशन इज वैरी सीरियस। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वह पंडित नेहरू की है। गांवों के लोगों से माल लेने में आज गवर्नमट नाकामयाब हुई है, यह बिल्कुल साफ है। आज चाहे गांवों के रहने वाले हों या शहरों के, वह आपको अनाज देने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि इससे हमारी मुसीबत बढ़ेगी और हम गरीब हो जायेंगे इसलिये यह चीज हमें फायदा पहुंचाने वाली नहीं है। इसलिये आई ऐम नाट प्रिपेअर्ड टु सरेन्डर माई स्टाक। अगर उसने ऐसा न किया तो फिर रास्ता क्या है? मैं कहूंगा कि कैबिनेट आज ठीक चल रही है लेकिन फिर भी आज मुल्क के अन्दर एक नेशनल ऐसिस्टेंस कैबिनेट बननी चाहिये। हो सकता है कि कृपलानी साहब ने इसलिये कहा हो कि उन को लालच हो कि वह ट्रेजरी बेंचेज पर जा कर बैठ जायें, लेकिन जो लोग कांग्रेस के भी नहीं हैं, और जिनको लालच भी नहीं है, जिन्होंने इसकी कभी परवाह भी नहीं की पार्लियामेंट में जा कर बैठें, आप उन लोगों को यहां रखें और उनकी एसिस्टेंस कैबिनेट बनायें। हो सकता है कि जो लोग कांग्रेस के बाहर है वे आपको बदनाम करना चाहते हों लेकिन जो लोग कांग्रेस में हैं और इस वजह से आपकी मुखालिफत नहीं करते, वह भी इस मामले में आपके साथ नहीं हैं तो फिर आपको चाहिये कि आप एक ऐसी नेशनल एसिस्टेंस कैबिनेट बनायें जिससे आपको जनता का विश्वास मिल सके और आप ठीक से काम कर सकें। उस कैबिनेट में इन लोगों को रखा जाना चाहिये: विनोबा जी, श्री जय प्रकाश नारायण, राजा जी, मास्टर तारा सिंह, श्री जेड० ए० अहमद, डा० जाकिर हुसैन, आशा देवी, गोलवलकर जी और टंडन जी। ये सब लोग हों या और निष्पक्ष लोग हों।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने तो कैबिनेट बना कर अपना इलाज दे दिया अब।

श्री ऑंकार राम: मैं अब इतना ही बताना चाहता हूं कि उस कैबिनेट का काम क्या होगा। उसके सुपुर्द छः सब्जेक्टस होने चाहियें। एक तो फूड का मसला, दूसरे डिफेन्स का मसला, तीसरे एजुकेशन का मसला, चौथे इंडो-पाकिस्तान रिलेशन्स का मसला, पांचवें स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन का मसला और छठवें लैंग्वेज का मसला। इन छः चीजों को नेशनल ऐसिस्टेंस कैबिनेट के सुपुर्द किया जाय। प्राइम मिनिस्टर का वोट उसी वक्त काम में आये जब उनका डिफरेंस हो आपस में। जो चीज वह यूनैनि-मसली पास करें उसमें प्राइम मिनिस्टर का दखल नहीं होना चाहिये। लेकिन उस फैसले को अगर बदलना हो तो दोनों हाउसेज की मैजारिटी से उसको बदला जा सके।

[श्री अचित राम]

दरअस्ल मेरा यही सजेशन था जो मैं देना चाहता था। मैं चाहता हू कि इस तरह की कैबिनेट बने और जिन लोगो का मैंने नाम रखा है, उनको उसमे मुनासिब हो तो जगह दी जाये।

Shri Mohammed Imam (Chitaldrug) We have listened with great care and respect to the Address of the President The debate on the Address affords us an opportunity to hold an inquest on the commissions and omissions of the Government But the Address which in itself is not only insipid but is uninspiring and contains only routine matters On going through the Address we cannot but realize that our national difficulties are on the increase and that there is an ever increasing gravity of the economic malaise

Of late, the President's Address always commences with profuse apologies for the failure of the Government to implement the Plan as was originally contemplated That robust optimism that prevailed and that characterized the commencement of the Plan is now lacking, and it has given room to an air of pessimism and an air of uncertainty We do not know where we are in the midst of the plans

The Address of 1957 was emphatic that there was no question of slowing down the progress or retarding the Plan But the Address of 1958 disclosed that the country's economy was in considerable stress and strain and that some revision was necessary The present Address comes forth with the sad admission that the Plan had to be revised and has to be reconsidered and pruned

Why I am referring to it is because of this The Plan as prepared is built on shaky ground and it is not realistic and it is not practicable, and the country's resources were not properly assessed by the framers of the Plan These are the difficulties in the midst of the Plan I cannot predict what the future will be during the next two years, as we depend mostly on foreign countries for our assistance It does not mean that I am against the Plan. We want the Plan to be implemented in its entirety, but I do not want that false hopes should be given to the nation and subsequently those hopes falsified

I am aware that mighty projects are under construction I am glad that three gigantic steel plants are put into operation I know that gigantic reservoirs are under construction though they have not yielded any substantial results I am also aware that the Community Projects to which the President has referred and the National Extension centres have been extended to a large number of villages But I am also aware that in these projects, especially in the Community Projects, a lot of money is wasted away rather than usefully spent

In spite of all this I may say that the plight of the common man, the plight of the poor, still remains the same or is becoming worse The poor man is in the grip of inflation in the midst of scarcity His cost of living has gone up and I may say without hesitation that every poor man, every man who lives in the villages, is underfed under-nourished, underclothed and has little or no room to live in That is his plight His condition or position has not improved to any appreciable extent Perhaps some of those who have been living through the pre-independence days are thinking as to whether these are the fruits of Independence or the fruits of democracy

I may refer to the food crisis which is a burning problem of the day All the hon Members have referred to this crisis with great sorrow and

great pain. It is true that the Government has been striving its best or has been attempting to solve this thorny problem Hundreds of crores of rupees have been spent on the 'Grow More Food' campaign, not only by the Centre but by the States It was proclaimed during the first Plan period that the food position would be solved, the problem would be solved and that the country would attain self sufficiency before the end of this Plan But the hope and the expectation has not materialized The food position remains the same Not only the food position is bad, but I may say that the prices are soaring high What is more, the position has become worse in the midst of this inflation and the action of the Government the policies of the Government to over spend and to over-tax have led to inflation On account of this inflation everywhere there is much less of goods for what we are paying That is the position

It was observed by Acharya Kripalani that though there may not be acute scarcity and even though there was a certain amount of scarcity, it can be tolerated provided the prices are reasonable But the Government have not taken any measures to bring down the prices not only of foodgrains but of such essential commodities as are of daily need for human existence

Having failed in all their measures having failed to resolve the food crisis, the Government propose to switch on to controls state trading land reforms and co operative farming The experiments especially land reforms and co operative farming which are introduced for the first time in our land and in the history of India So far as controls are concerned I may state that I always hate controls for from past experience we find that controls always create scarcity They not only create scarcity but black market and black market always destroys the free market From the administration of these controls it is our experience that what little food is available now may not be available hereafter I am afraid that by the imposition of these controls the prices may go up still higher

I am not going to allude to land reforms, but about co-operative farming I would like to say a few words The Prime Minister has observed that the country's food problem will be solved and that there will be more production if co-operative farming is introduced I wish him every success but I must suggest that we do proceed with caution and care before implementing it This is the result of the Congress resolution at Nagpur and I know that in pursuance of the resolution many hundreds of Congress workers are being trained to work this But what I am afraid of is this This is a party idea or a party manoeuvre which is going to be imposed on the nation

It was stated that this co-operative farming has been successful or has proved successful in Soviet Russia and in China The conditions here are quite different In Russia and China, no private property or no private land is recognised It is a dictatorial form of government there Here we are under a democracy Is it possible to work up this co operative farming in a country where conditions are quite different? Of course in China and Russia where people do not own land, they are forced to work on the land and it might have been successful, but we do not know the conditions there But here if we introduce this experiment throughout all at once I am afraid there would be confusion and chaos So, I submit that the Government must proceed with care and caution Of late there is a feeling that the country is being drawn more and more towards communism and communist doctrines and ideologies and being nursed by the Government and by the Prime Minister Whatever may be the result I submit that care should be taken to see that our economic crisis is not accentuated There are other methods also to see that food production goes up by proper and judicious administration

[Shri Mohammed Imam]

I may be permitted to deal here with the boundary dispute between Mysore and Bombay, which has been referred to by some friends Mysore is surrounded on all sides by five States—Madras, old Hyderabad, Kerala, Andhra and Bombay So far as the other States are concerned, we have no dispute We have resolved our dispute with Andhra We have got disputes with Kerala and other States, but we have reconciled ourselves It is unfortunate that our Maharashtrian brethren have taken a militant attitude and they have commenced onslaughts on the State of Mysore This is very unfortunate I may submit that the question of Belgaum and North Kanara was settled by a competent body consisting of eminent persons One of the members of the Commission was a Mysorian—a High Court Judge—and two members were eminent judges

Dr. P. S. Deshmukh: This has already been modified so far as Andhra—Mysore border is concerned

Shri Mohammed Imam: We have reconciled ourselves to that and we do not have disputes with any other State If there is any dispute, it must be resolved by mutual negotiation and not through satyagraha or any other violent method Belgaum and other places were handed over to us according to the opinions expressed by the Re organisation Commission and also the Parliament They did not hand over these areas arbitrarily The population may he evenly divided there When population is evenly divided, other circumstances are taken into consideration, such as historical aspects, administrative convenience, economic viability and so on Taking all these factors into consideration, they have decided rightly that these areas should go to Mysore Now this attempt by our Maharashtrian brethren to create disturbances dislodge and unsettle what has been settled is very unfortunate I am sure they will devote their attention to more important things and not trouble themselves on these minor issues.

When I was in the Chair, Mr Narasimhan referred to the speech made by my leader yesterday regarding the formation of a national government and he also made some adverse remarks regarding the role of the Opposition He seems to think that the PSP is very anxious to shoulder the responsibilities or to aspire for any office I am afraid he has not understood the speech of Acharya Kripalani properly You know him very well and you find very few patriots like him You also know the reason why he resigned from the Congress He is the last man to aspire for any office If I understood him correctly, yesterday what he meant to say was that the Prime Minister's offer or invitation for co-operation must be logical He said that the Prime Minister should not invite the Members of the Opposition for mere consultation, they must be invited for execution also I can tell you that we in the PSP or in the Opposition are not at all anxious to come into office nor do we care for office There seems to be a certain amount of uneasiness or nervousness among the Congress people Perhaps most of them seem to feel that by the formation of a national government, which has been wrongly understood they might lose their own advantages

Acharya Kripalani only pointed out the gravity of the situation and the need to resolve the food crisis I may make it clear that the Opposition will play its role I know that opposition is needed for the sake of the country It has been said, no matter what the form of government is, that government is best which is best administered Monarchy is good provided there is a benevolent monarch Similarly, if democracy is carried on properly, certainly it will bring benefit to the

peole But if democracy is misused or if it is not properly administered, then democracy will become mobocracy So, it all depends on the persons So far as this aspect is concerned, I can make it clear that neither the PSP nor the Opposition is at all anxious to get into office We are only anxious to see that the Government is run properly You may pass any number of laws Legislation can be passed in any number, but I submit there are eternal laws, divine laws, which can never be changed This must always be remembered by those who are in charge of the administration It is only then that the country will prosper and the people will be happy

Shri Brajeshwar Prasad (Gaya) Only an Indo-Russian settlement can safeguard our territorial integrity in Kashmir No amount of American help can guard it if there is a Pak-Russian settlement The alternative to an Indo Russian settlement is a Pak-Russian settlement because the Baghdad Pact is dissolving fast There is no third alternative, for the integration of the heartland and the rimland into one political unit is both desirable and inevitable This integration will be on a democratic basis if there is a political settlement between India and Russia Russia will enter into a political settlement with India if China is on our side and we support the Russian foreign policy pertaining to Europe and the New World

If there is a war between India and Pakistan, America will remain neutral and Russia will help either India or Pakistan whoever happens to be her ally

If India does not enter into a political settlement with Russia, as surely as the Sun rises in the East, Pakistan in sack cloth and ashes and with a beggar's bowl in its hands will knock at the gates of the Kremlin and implore forgiveness for its sins Pakistan will offer to withdraw from the Baghdad Pact if Russia changes her stand on the question of Kashmir.

By supporting Pakistan on the question of Kashmir Russia will be supporting not Pakistan but herself alone, for the integration of Kashmir with Pakistan means the integration of both Pakistan and Kashmir with the Soviet Union If Russia has to choose between Pakistan which is prepared to join hands with her, and India which is determined to remain non-aligned, she is bound to choose the former and not the latter

Nation States are motivated by considerations of power politics and national interests Russia supported India on the question of Kashmir because Pakistan joined the Baghdad Pact A re-affirmation by M Voroshilov of the old pledge given to India on the question of Kashmir will safeguard our position and pave the way for a full-fledged political settlement between Russia and India

Now I come to the problems of Europe The unification of Germany as a result of an agreement between Russia and America may imply three things It may mean the division of the Afro-Asian land mass into two spheres of influence It may mean that America is of the view that if Germany is united on the basis of disengagement in central Europe, Germany will develop into an autonomous centre of power It may mean that Russia is of the view that if Germany is united on that basis the whole of Europe will be integrated with her

But if the SEATO is liquidated before Germany is united, neither Russia can integrate Europe nor the bi-polar world will be broken up into a large number of autonomous centres of power If there is a political settlement between Russia and America, East Asia will pass within the American sphere of influence and Africa and West Asia will pass within the Russian sphere of influence

An Hon. Member: There are too many "ifs"

Shri Brajeshwar Prasad: Both India and China will be encircled. It is only on the basis of give and take that a political settlement can be arrived at in a world of sovereign Nation States The lessons of Yalta, Tehran Cairo and Potsdam can be ignored only at our own peril

The nuclear age places us in a disadvantageous position *vis-a-vis* the white races By no stretch of imagination a political settlement between Russia and America can prove to be beneficial to India But if the Russian calculation proves to be correct and Europe is integrated with her, Africa and West Asia will pass within the Russian sphere of influence and East Asia will pass within the Chinese sphere of influence But if the American calculation proves to be correct the bi-polar world will be shattered to pieces and once again united Germany mav become a menace to Europe Africa and Asia

America will stand to gain b the political disintegration of the old world Her hegemony over the new world will be strengthened The NATO the SEATO and the Baghdad Pact have become an encumbrance to America America will gain greater freedom of action f a large number of autonomous centres of power are created m the old world

If India and China ome togethei there cannot be either a Russio-American or a Russo-Chinese settlement and Russia will have to join hands with India and China The pull of the Afro Asian land mass over Russia will become greater than that of the United States of America If India China and Russia come together, America will have to walk out of the old world in general and East Asia in particular if America walks out of the old world and India China and Russia come together, the bi-polar world will yield place not to a large number of autonomous centres of power but to one world within the frame-work of the United Nations Organisation

China will become an autonomous centre of power if America withdraws from East Asia, and there is no political settlement either between India and China or between India and Russia or between Russia and China If both Germany and China develop into autonomous centres of power, hell will be let loose on earth

श्री प्र० सिंह दौलता (झज्जर) *जनाब डिप्टी स्पीकर पेश्तर इसके कि मैं* उन की तरफ जाऊं जो कि पंजाब के मसले है और जोकि राष्ट्रपति के एड्रेस में दर्ज नही है, मैं एक बात का ज़िक्र कर देना चाहता हू और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने अपनी स्पीच मे मेरे लीडर के बारे मे कहा कि श्री डागे ने अपनी स्पीच मे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू की तो बडाई की लेकिन बाकी मिनिस्टरो की निन्दा की । अब जहा तक श्री डागे की स्पीच का ताल्लुक है मैंने उसको बहुत गौर से सुना और वह तहरीर मे है और मुझे तो उसमे कोई ऐसी चीज नज़र नही आई जिस पर कि उन्होने यह एतराज किया । चीज असल मे यह है कि कांग्रेस की जो एग्रेरियन पालिसी है उसको श्री नेहरू और उनके हम ख्याल अमल मे लाना चाहते है लेकिन कांग्रेसमैन मे ही कुछ अनसर ऐसे है जो कि उस पालिसी को एग्जीक्यूट नही करना चाहते । हम अपोजीशन वाले और खास कर जिस वार ग्रुपवाले इस बात की फिक्र रखते है कि किसी को खामख्वाह क्रिटिसाइज न किया जाय । स्पीच मे सिर्फ यही कहा गया था कि जब कि पंडित जी और उनके ख्याल के लोग कांग्रेस की इस एग्रेरियन पालिसी को एग्ज़ीक्यूट करने का इंटेंशन रखते हैं तो उन्ही के कांग्रेस के कुछ

साथी उस पालिसी को अमल में नहीं लाना चाहते हैं। अब इसमें किसी को भला बुरा कहने की बात कहा है ? अब यह भी बात है कि अच्छे और बुरे आदमी सब जगह और हर पार्टी में होते है . . . .

एक माननीय सदस्य : आप किस में आते है ?

श्री प्र० सिं० दौलता मै तो अच्छे आदमियो मे मे हू ।

अब मै आपकी इजाजत से पजाब के बारे में कुछ अर्ज करूगा । मै पजाब के बारे मे ऐसा एक लफ्ज भी नही कहूगा जोकि इस हाउस में पिछले तीन दिनो के दौरान मे कहा गया है और मै उस बारे में कोई रिपीटीशन नही करूगा ।

बाइलिगुअल ईश्यु सिर्फ गुजरात और बम्बई का ही नही है। पजाब का बाइलिगुअल ईश्यु बदस्तूर मौजूद है और उसे कोई कनफ्यूज नही कर सकता । किसी एक लीडर के व्हिम से कि उसे एलेक्शन मे काग्रेस की कुछ टिकटे वगैरह पर राजी कर लिया और उसमे यह समझ लिया जाय कि पजाब की जनता ने अपनी पजाबी सूबे की माग छोड दी है, ऐसी बात नही है । मै तो मानता हू कि पजाब के लोगो का और पजाबी बोलने वालो का अपने एक सूबे का वैसा ही हक है जैसे कि दूसरे सूबे के लोगो का है और उनको उनका सूबा मिलना चाहिये । आज वह लीडर फिर बेचैन है और वह पजाबी सूबे की माग कर रहा है और उसने पजाबी सूबे की माग छोड नही दी है। अब इस सूबे की माग करने के लिए यह कह देना कि यह फिरकेदाराना माग है, ठीक नही है । मुझे यह रिमार्क सुन कर बडा बुरा मालूम होता है । मै पूछना चाहता हू कि यह फिरकेदाराना माग कसी है ? यह उन लोगो की आवाज है जो करोडों की तादाद में आबाद है, हालांकि एक अकलियत है लेकिन वह एक बड़ी जिम्मेदार अकलियत कहलाती है क्योंकि वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बार्डर पर बसती है और जोकि पैरासाइट अक्सरियत नहीं है। अमन के दिनो में वह हल चलाती है और लडाई के दिनो में मुल्क को सिपाही देती है और उसका जजबाती तौर पर यह मतालबा रहा है कि उनका एक अलहदा सूबा सेंट्रल गवर्नमेंट के मातहत बनना चाहिए और मैं पूछना चाहता हू कि आखिर इसमे ऐसी कौन सी बात है जिसके कि लिए हम उस अकलियत की पर्वाह न करें और उसी तरह जिस तरह हमने शुरू मे मुस्लिम लीग के जजबात की पर्वाह नही की और आगे चल कर जिसके कि लिए हमने काफी नुकसान उठाया, हम आज उनकी इस डिमाड की पर्वाह न करे । आखिर इससे आपको क्या हासिल होगा । एक अकलियत के जजबात को यह कह कर कि वह फिरकेदाराना माग है, ठेस पहुचाते चले जाना, यह गलत बात है । कोई अकलियत अगर पजाबी सूबे की माग करती है तो जबान तो उसकी मजूरी देने के लिए एक ऐडिशनल ग्राउन्ड होनी चाहिये और उसकी मजूरी की राह मे कोई रुकावट नही आनी चाहिये । मै तो समझता हू कि प्योरली ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजस हरियाने के और पजाबी स्पीकिंग एरिया के अगर बना दिये जाते हैं तो वह किसी कदर पोलिटिकल बीमारियो का इलाज साबित होगा । मै चाहता था कि काश यहा पर होम मिनिस्टर साहब या दूसरे जिम्मेदार मिनिस्टर्स होते क्योंकि मैं यह अर्ज करने चला हू कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के लोगो की यह ख्वाहिश है कि पहाडियों का एक सूबा बने और क्यो न बने ? पजाबी लोगो की अगर यह ख्वाहिश है कि उनका एक पजाबी स्पीकिंग सूबा बने तो मैं पूछना चाहता हू कि क्यो न बने ? अब हरियाना प्रदेश दिल्ली के चारो तरफ फैला हुआ है। सन् १८५७ मे अग्रेजो ने इसे तोडा था । मेरठ डिवीजन की इलाहाबाद जाते हुए रोहतक की १७ मील की कास्टीट्यूएसी शुरू

[श्री प्र० सिं० दौलता]

होती है जो कि अलवर और भरतपुर की तरफ जाती है जब कि उनका हिस्टोरिक कप्टिल दिल्ली है और जिसको कि अंग्रेजों ने तोडा था तो कोई वजह नही कि इन लोगो को क्यो न इकट्ठा कर दिया जाय और साथ ही यह भी मानना पडेगा और मेरे बुजुर्ग होम मिनिस्टर पडित पत होते तो मैं उनको बतलाता कि उत्तर प्रदेश का साइज ऐसा है और इतना बडा है जो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन के प्वाइंट आफ व्यु से एक अच्छा साइज नही माना जा सकता। अब उत्तर प्रदेश के साइज को घटाने के खिलाफ उस सूबे के बुजुर्गों की तरफ से यह दलील दी जाती है कि अगर कोई आदमी बडा हो तो क्या उसके हाथ पैर काट डाले जायें ? हाथ पैर तो अलबत्ता नही काटे जा सकते लेकिन पेट जरूर काटा जा सकता है और उत्तर प्रदेश का पेट बहुत बड़ा है और उसको छोटा करना चाहिये। मेरी तजवीज यह है कि उत्तर प्रदेश के पेट को छोटा करने के लिए मेरठ डिवीजन उधर दे दिया जाय। पजाबी स्पीकिंग सूबा बनने से यह जो आपकी दिल्ली को असेम्बली नही मिल रही है वह मिल सकेगी। हरियाना प्रान्त के लोग, दिल्ली के लोग और हिमाचल प्रदेश के लोग और उत्तर प्रदेश के मेरठ डिवीजन के लोग अगर अपनी डिमाड के लिए होहल्ला नही करते और शोर नही मचाते तो उससे गवर्नमेंट को यह नही समझ लेना चाहिये कि उनका मनालबा दब गया है या वह कमजोर है।

अब मैं इसके बारे मे दूसरी चीज अर्ज करने चला हू और मै चाहता था कि इस मौके पर हमारे आनरेबुल स्पीकर चेअर मे होते ताकि वह मेरी बात सुन सकते। यह बेटरमेंट लेवी के लिए इस वक्त पजाब मे किसान लोग जेलो मे जा रहे है, उनके स्वेशी नीलाम हो रहे है, उन पर वारट जारी किये जा रहे है और उनका दूसरा सामान कुर्क हो रहा है। अब उस बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का नुक्तेनिगाह क्या है और किसान सभा की यह डिमाड क्या है ? अब इसके बारे में कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब की गवर्मनेंट को बहुत मदद देती है। अब मैं जानना चाहूगा कि व्हाट इज अवर ऐचीवमेंट ? मैं अर्ज करता हूं कि भाखरा डैम पर जो खर्चा आया है २२० करोड मय सूद उस क २२० करोड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैसा कंट्रिब्यूट नही किया, प्राविशिएल गवर्नमेंट ने एक पैसा कंट्रोल नही किया। उस २२० मे से बिजली का राजस्थान का हिस्सा निकलने के बाद ९८ करोड हमारे हिसाब मे और १०१ करोड रुपया गवर्नमेंट के हिसाब मे वाजिबुलअदा आता है। ज्योंही बेटरमेंट लेवी और कौंसिल उठी, एक आर्डिनेंस पास किया गया जिसकी कि रू से बेटरमेंट लेवी के जरिए यह सारा रुपया १५ किश्तो मे किसानो से वसूल किया जायगा। सूद तीन परसेंट के बजाय किसान पाच परसेंट देता है। यह प्रोडक्टिव है, यह घाटे की स्कीम नही है फिर इस लेवी का क्या सवाल ? अब बेटरमेंट टैक्स का तो यह है कि ज्योही बेटरमेंट टैक्स लाग किया जाता है त्योही उसके साथ ही जैसे कि पजाब का है, उसका आधा जितना लैंड रवेन्यू होता है उतना आटोमैटिकली लोकल रेट बढ जाता है, इनहेंस हो जाता है और आबियाना १९५० से डेढ गुना कर दिया है। लैंड रेवेन्यु तो अलग और आबियाना बढा हुआ। बेटरमेंट टैक्स के साथ जो लोकल रेट बनता है उससे उसकी आमदनी मे काफी इजाफा होता है। जिस समय बेटरमेंट लेवी ऐक्ट पास हुआ उस वक्त मिनिस्टर प्रोफेसर शेर सिह थे। उनके हिसाब से वह तमाम टैक्स पूरा कर देता है और सूद के अलावा दो परसेंट ज्यादा होता है, तीन परसेंट हो जाता है और पाच परसेंट देते है।

अर्ज यह है कि जब यह प्रोडक्टिव है तो इसमें लेवी लगाने के क्या मानी ? तो मेरी पहली अर्ज तो यह है कि यह सेंट्रल

गवर्नमेंट का पैसा है । फिर मैं यह अर्ज करू कि मैं ५०० रुपये देकर अपने डिप्टी स्पीकर साहब से एक भैंस खरीदू ।

उपाध्यक्ष महोदय मेरे पास तो है नही ।

श्री प्र० सि० बौलता जब आप मांटगुमरी में थे तब तो आपके पास बहुत भैंसे थी । तो मैं कहता हू कि अगर मैं डिप्टी स्पीकर साहब से ५०० रुपये देकर भैंस खरीदू और जब मैं दूसरे दिन उसका दूध निकालने लगू तो यह कहें कि इस दूध के दाम और दो । तुमने तो भैंस *के दाम ही दिये है दूध के नही दिये । अगर दूध* निकालना है तो दूध के दाम और दो तब दूध निकालना। मैं कहता हू कि आप किसान को मदद न दें जैसी कि आप सरमायेदारो को देते हैं या जैसी कि आप शुगर केन के मामले में कारखाने वालो को एड देते है वह भी न दे । किसान से जो वाजिब है वही लें । लेकिन आप तो उससे भेस का भी दाम चाहते है और जो दूध वह निकालेगा रोज रोज उसका भी दाम चाहते है। किसान कहता है कि हमसे कीमत ले लो और एन्युअल मेनटिनेन्स की कास्ट भी ले लो मगर फिर उसके बाद आबियाना मत मागना। वह कहता है कि भैंस का दाम ले लो लेकिन दूध का दाम न मागना । लेकिन आप कहते हैं कि नही भैंस का दाम लिया जायेगा और जो रोज–रोज उसका दूध निकालोगे उसका भी दाम लिया जायेगा । ऐ सोशलिज्म का नारा लगाने वालो, क्या यही सोशलिज्म है । यह किसान का भोलापन है, उसकी बैकवर्डनेस है कि जिसको आज एक्सप्लाइट किया जा रहा है ।

एक भाई ने मुझ से सेंट्रल हाल में कहा और आज मैं ने अखबारों में भी पढा है कि किसानों की जमीनों की हैसियत बढ जायेगी, तो क्यों न उनसे कुछ ज्यादा चार्ज कर लिया जाये । मैं कहता हूं कि जमीन की हैसियत बढ़ने का हैसियत टैक्स पहले ही लगाया जा चुका है । फिर किसान कोई ट्रेडर नही है कि वह जमीन को बेचेगा । इसलिए वह जमीन की वेल्यू बढने से फायदा नही उठाने वाला । कहा जाता है कि उसकी जमीन की पैदावार बढ जायेगी । इस भाखरा डैम के बनने के पहले २१ साल तक तो सर छोटूराम यह चिल्लाते रहे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब पोस्टरो वगैरह मे यह जाहिर करती रही है कि यह डैम किसानो का स्टैंडर्ड बढाने के लिए बनाया जा रहा है । अगर यह बात है तो फिर किसान का स्टेडर्ड बढने दीजिये, उससे उसके लिए टैक्स क्यो मागा जाता है। यह तमाम पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पजाब के एक जिम्मेवार मिनिस्टर ने कहा कि हमने तीन बार सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि कम से कम सूद माफ कर दीजिये क्योकि खेती भी एक इडस्ट्री है लेकिन तीनों बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सूद माफ करने से इन्कार कर दिया । जाने दीजिये इसको ।

सोशलिज्म का यह बेसिक उसूल है कि जिनके उठाने के लिए पैसा खर्च किया जाये उनसे वह पैसा वसूल न किया जाये । यह सोशलिज्म का बुनियादी असूल है । अब आप देखें कि चडीगढ बसा है । मैं भी चडीगढ मे रहता हू। वहा पर बडे–बडे अस्पताल और कालिज वगैरह बनाये गये है। लेकिन मैं देखता हू कि चंडीगढ़ के लोगो से तो उसके लिए पैसा नही मागा जाता कि इन चीजो से तुमको फायदा होगा इसलिए तुम इनकी कीमत अदा करो । तो फिर किसान से ही क्यो इस तरह पैसा मागा जाता है कि तुम्हारा स्टेडर्ड बढता है इसलिए तुम पैसा दो । आप देखें कि जो ९८ करोड रुपया मागा जाता है उसमें वह ३३ करोड़ भी शामिल है जिसका कि करप्शन हुआ था । उस सिलसिले में एक चीफ इंजिनियर और १३ दूसरे इंजीनियर

[श्री प्र० सि० दौलता]

पकड़े गये थे। आज किसानों से कहा जाता है कि वह करप्शन का पैसा भी तुम दो चाहे उसके लिए जिम्मेवार कोई भी क्यों न रहा हो।

कहा जाता है कि इस डैम का बैनिफिशियरी पंजाब का किसान है इसलिए उसे पैसा देना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहब आप और मैं जिस इलाके में गजीबार और नीलीबार में रहते थे वह एक जमाने में रेगिस्तान था। लेकिन जब किसान ने उस इलाके में खेती की और वहां गेहूं पैदा हुआ तो बड़ी बड़ी मंडियां वहां कायम हुईं। और कितने लोगों ने फायदा उठाया। इसी तरह मैं कहता हूं कि इस भाखड़ा डैम से सबसे बड़ी बैनिफिशियरी तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसका बहुत सा फारिन एक्सचेंज बचेगा। अगर यह उसूल मान लिया जाता है कि जो बैनिफिशियरी हो वह पैसा दे, तो भी अकेला किसान पैसा देने का जिम्मेवार नहीं है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, दे प्राविंशियल गवर्नमेंट दे और दूसरे लोग जो फायदा उठाये वे दें। मैं रियायत नहीं मांगता। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने बैनिफिशियरी हैं सभी दें, जो भी फायदा उठाये वह दे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी से क्यों बचती है। उसका भी फारिन एक्सचेंज बचेगा, प्राविंशियल गवर्नमेंट का भी बचेगा।

मेरे दोस्त श्री अजित प्रसाद जैन आज यहां नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब एक किसान एक मन गल्ला पैदा करता है तो सिर्फ किसान ही उसका बैनिफिशियरी नहीं होता। जब पंजाब के किसान ने गेहूं पैदा किया तो फस्ल पर उसका भाव रखा गया १४ रुपये सात आने मन और प्रो० ब्रजनारायण ने बतलाया है कि पंजाब के १८ ९ परसेंट किसान को अपना अनाज बेचने पर मजबूर होना पड़ा, मैं तो कहूंगा कि फेंकने पर मजबूर होना पड़ा। क्योंकि भाव तो मुकर्रर किया गया था, १४ रुपये सात आने मन और उनको देना पड़ा १२ रुपये ८ आने, १३ रुपये ८ आने, १३ रुपये १० आने मन। इस तरह से किसान तो मुकर्रर की हुई कीमत भी नहीं पा सका, लेकिन जब वह गेहूं जैन साहब की बिरादरी के पास गया तो वह १२ और साढ़े १२ रुपये का लिया हुआ गेहूं २५ रुपये मन पर बिका। किसान को तो जो कीमत सरकार ने मुकर्रर की थी वह भी नहीं मिली उसके बूढ़े मां बाप और बच्चे भूख से तड़पते ही रह गये और पैसे कमाये दूसरे लोगों ने और सरकार चिल्लाती है ग्रो मोर फूड, ग्रो मोर फूड। आप कहते हैं कि बैनिफिशियरी अकेला किसान है। आप जानते हैं कि जब किसान गल्ला पैदा करता है तो कितने लोगों को फायदा होता है। जब लायलपुर और मंटगोमरी बसाया किस तरह से मिडिल क्लास के तबके को फायदा हुआ। वह भी बैनिफिशियरी हुए। तो मैं यह कहता हूं कि अगर इस उसूल को माना जाता कि जो बैनिफिशियरी है वह दे तो यह चार्ज सब बैनिफिशियरीज पर लागू होना चाहिए। अकेले किसान पर लागू नहीं होनी चाहिए। इसका एक परसेंटेज मिडिल क्लास दे, एक परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट दे और प्राविंशियल गवर्नमेंट दे। अकेला किसान ही सारा कंट्रीब्यूशन क्यों दे। मुझे इसके बारे में और भी बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन वक्त कम है।

अब मैं दूसरी बात फूड की कहना चाहता हूं। अरे भाइयो, मुझे बड़ी शर्म आती है यह देखकर कि आज पंजाब में फूड का यह हाल है। अगर मैं फूड मिनिस्टर होता तो मैं इस हालत में यह आफिस छोड़ देता। आप देखें कि पंजाब में जो कि सरप्लस था फूड के मामले में आज यह हालत है कि औरतें और बच्चे बाजारों में हाय रोटी, हाय आटा चिल्लाते फिरते हैं। आज पंजाब का गेहूं कहां है। उसकी सारी जिम्मेवारी हमारे फूड मिनिस्टर साहब पर है। हमने कहा था कि फूड जोन को इकट्ठा कर दीजिये लेकिन ऐसा नहीं किया

गया । नतीजा यह होता है कि जहां मेरी कांस्टीट्यूएंसी में १६ रुपये मन गेहूं बिकता है वहां जैन साहब की कांस्टीट्यूएंसी में २२ रुपये मन बिकता है, एक मन पर ६ रुपये का फायदा होता है । नतीजा हुआ स्मगलिंग । और इस तरह पंजाब का सारा गेहूं बाहर चला गया । अब पंजाब में गेहूं नहीं है । जब ६ रुपये मन का फायदा स्मगलिंग के होगा तो कोई होड नहीं करेगा । तमाम गल्ला राजस्थान और यू० पी० में चला गया । हमारे दोस्त फूड मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पंजाब के किसान गेहूं होर्ड किए हुये हैं । जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं पंजाब की फूड कमेटी का मम्बर हूं । मैं बतलाना चाहता हूं कि हमें बतलाया गया है कि किसी किसान के पास गेहूं जमा नहीं है । न मालूम सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर कहां से यह इनफारमेशन लाये हैं कि वहां पर किसान के पास गेहू होर्ड किया हुआ है । मुझे यह बात मालूम है कि आज पंजाब में गेहूं नहीं है । हो यह रहा है कि जैसे जब चोरी होती है और चोर के पीछे लोग भागते हैं तो चोर भी भीड़ में शामिल हो जाता है वह भी कहने लगता है कि चोर यह गया वह गया । यही आज हो रहा है कि व्यापारी तो होर्ड कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि किसान होर्ड कर रहा है ।

तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यह अर्ज करूंगा कि जरूरत तो यह थी कि सारी गवर्नमेंट की तबदीली होती, लेकिन अगर यह न हो तो कम से कम फूड मिनिस्टर की तबदीली की तो सख्त जरूरत है । जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है वह बहुत अच्छे आदमी हैं, और बहुत अच्छे होस्ट हैं, जब हम उनके साथ जाते हैं तो अच्छी तरह खिलाते पिलाते हैं । लेकिन फूड के मामले में जैन साहब बिल्कुल नावाकिफ हैं ।उनको इंटेलेक्चुअल वाकफियत भी नहीं है जैसी कि प्रोफेसर अजनारायण को है जो कि एक बड़े इकानामिस्ट हैं और करल एकानमी के बारे में अच्छा तजुर्बा रखते हैं। न जैन साहब को जमीदारी का तजुर्बा है। वह कभी हल लेकर खेत पर नहीं गये हैं। आप जानते हैं कि मुल्क में हर रोज सुबह करीब २३, २४ करोड़ किसान हल लेकर खेतों पर जाते हैं । मैं पूछता हूं कि क्या उनमें से कोई एक भी जैन होता है । कोई एक जन भी ऐसा नहीं होगा जो खेती करता हो । तो मैं अर्ज करता हूं कि जिस आदमी को खेती का और फूड का किसी भी तरह का तजुर्बा नहीं है उसको इतने सालों से क्यों मुल्क के सिर पर थोपा हुआ है । उसे जल्द अज जल्द जवाब देना चाहिए ।

अब मैं काश्मीर के बारे में अपनी पार्टी की पोजीशन साफ करना चाहता हूं । काश्मीर वह स्टेट है, जो कि पंजाब से लगती है । काश्मीर के बारे में हमारे लीडर हमेशा कहते हैं कि काश्मीर हमारे मुल्क का पार्ट एण्ड पार्सल है, लेकिन जब मैं ला रिपोर्ट्स को देखता हूं, तो पाता हूं कि हर एक ला के बारे में यह लिखा होता है कि It will apply to the whole of India except Jammu and Kashmir इस का मतलब यह है कि रोज बताया तो यह जाता है कि काश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है, लेकिन कई तरीकों से यह महसूस कराया जाता है कि वह हिन्दुस्तान से बाहर है । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इलैक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन जल्द से जल्द वहां जानी चाहिए । जितनी जल्दी ऐसा किया जायेगा, उतना ही बेहतर है ।

सिर्फ एक प्वाइंट का जिक्र कर के मैं बैठ जाना चाहता हूं । इस हाउस के एक आनरेबल मेम्बर ने—एक लीडर ने—कहा कि करप्शन नीचे के लैवल पर है और ऊपर वाले उसको कंट्रोल नहीं करते हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल गलत है । करप्शन नीचे के लैवल में—पटवारियों, क्लर्कों, नाजिरों और अहलमदों में—नहीं है । वहां तो एक गरीब आदमी सिर्फ दुनिया में सरवाइव करने की अटेम्प्ट में है

[श्री प्र० सिं० दौलता]

और करप्शन तो टाप वालों में है, जिनका रबर का पेट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मिस्टर मथाई के बारे में जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिए। उसके साथ किसी जाती इन्तकाम का सवाल नही है। सवाल तो यह है कि जब हमारे महबूब प्राइम मिनिस्टर श्री नेहरू, जिनकी इन्टेगरिटी पर कोई शक नही कर सकता है, का प्राइवेट सैक्रेटरी इस तरह के इन्ट्रेस्ट्स के साथ इनवाल्व्ड है, तो फिर उन मिनिस्टिरों का क्या हाल होगा, जिनकी इन्टेगरिटी को हम वह दर्जा नही देते, जो कि नेहरू की इन्टेगरिटी को देते हैं। मैं यह कहना चाहता हू कि मिस्टर मथाई का मामला इस बात की मिसाल है कि टापमोस्ट कैबिनेट के दफ्तरों में, फाइलो में बिग बिजिनेस के इशारों पर काम हो रहा है और बिग बिजनेस को सब हालात का पता होता है। जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू की इन्टेगरिटी के आदमी तक ऐसा आदमी रख सकते हैं, तो दूसरों के दफ्तरों में भी यही हालत होगी, यह हम नेशन को बताना चाहते हैं। टाप की करप्शन को रिवील करने के लिए इस मामले की एन्क्वायरी की माग की जा रही है।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझ से पहले जो मेम्बर साहब बोले है, अगर्चे जितनी बातें उन्होंने कही है, मैं उन सब के साथ तो सहमत नही हो सकता खास तौर पर उन पर्सनल रिमार्क्स के साथ, जो कि उन्होंने किए हैं, लेकिन जिस ढग से उन्होंने पजाब की रेफरेंस से किसान की वकालत की है, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद देता हू। राष्ट्रपति जी के भाषण में कुल ५४ पैराग्राफ हैं, जिन में से २९ पहले पैराग्राफ्स मे उन्होंने उन तामीर के कामो का जिक्र किया है, जो कि हमारे देश में हो रहे हैं। इस से इस बात की अहमियत का अच्छी तरह से पता लग जाता है कि आज-कल हमारे सामने सब से ज्यादा जिन्दा सवाल यह है कि गरीब को उठाना है और देश से गरीबी को दूर करना है। इस वक्त हमारे देश में अनाज के सम्बन्ध में जो संकट आ रहा है, वह बड़ा संजीदा तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह बहुत जल्दी टल जाने वाला है। जो बुनियादी बातें हैं, उन की तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं एक किसान का लड़का हूं और वह भी एक थोड़ी सी जमीन रखने वाले किसान का जिस ने अपनी जिन्दगी भर जमीन के बगैर और काम नहीं किया। आज जब कि को-आपरेटिव फार्मिंग और ज्वायंट फार्मिंग के बारे में यहा चर्चा हुई है—खिलाफ भी और हक में भी तो मुझ खुशी हुई है कि इस की चर्चा हो गई है, वर्ना किसान बेचारे की चर्चा बहुत कम होती है। एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है—

नजरे गजब से देखते है, देखते तो हैं।
मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में।

श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्): फिर कहिए।

ज्ञानी गु० सिं० मुसाफिर: इस चर्चा का शुरू हो जाना एक अच्छी मिसाल है। लेकिन हमेशा हर एक चीज का बैलैन्स्ड व्यू लेना चाहिए। मिस्टर मसानी बड़े अच्छे राइटर है। मैं उन का मद्दाह हू और उन की राइटिंग्ज को पसन्द करता हूं। लेकिन उन्होंने अपने पक्ष को ब्यान करते हुए सिविल वार और ब्लडशैड तक का जिक्र किया। यह बात मेरी समझ में नही आई। मगर ब्लड है कहा ? जहा यह है, वही बहेगा। बेचारे किसान को चूसा जा रहा था। अब कोशिश की जा रही है कि उस के जिस्म में खून सीचा जाए ताकि वह जरा अच्छा हो जाय और अच्छा काम कर सके। मेरी समझ में नहीं आता कि ज्वायंट फार्मिंग का नफ्त कई कानों को बुरा क्यों लग रहा है।

15 hrs.

मैंने अपनी आखो से गाव में रहते हुए ये नजारे देखे हैं कि गाव का एक मरासी एक ढोल ले कर मकान के ऊपर चढ़ जाता था और ढोल को बजा कर एलान करता था कि आज फला शख्स के खेत की बिजाई होगी या कटाई होगी और गाव के तमाम लोग वहा जमा हो जाते थे और दर्जा-ब-दर्जा एक दिन एक का काम और दूसरे दिन दूसरे का काम किया जाता था । इस तरह का वातावरण गावो में होता था । वह दिन गुजर गए है और आज ज्वायट फार्मिंग के तरीके से गावो में एक नया जीवन पैदा किया जा रहा है । मै उस की कई बातो से इत्तिफाक करता हू । अभी एक मेम्बर साहब ने कहा था कि इस से अनाज की पैदावार बढ़ेगी या घटेगी । मै समझता हू कि यह एक आरजी सवाल है, जिस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है । यह तो एक तरीके से एक तजुर्बा है, जो कि हम करने जा रहे है । इस में हमें मददगार होना चाहिए इस ख्याल से कि पहले तो किसान में यह भावना पैदा करनी है कि यह सब कुछ तेरे लिए हो रहा है । जब तक यह भावना न होगी, उस वक्त तक काम ठीक तरीके से नही चल सकता है । थोडे दिनो की बात है कि हम राउरकेला मे थे । वहा एक अस्पताल बन रहा है । हमे बताया गया कि यह अस्पताल तीस लाख की लागत से बन रहा है । जो मजदूर वहा काम कर रहे है, उनमे से एक मजदूर से हम ने पूछा कि यह क्या बन रहा है । उसने कहा कि यह अस्पताल बन रहा है । हमने पूछा कि यह किस के लिए बन रहा है, तो वह कहने लगा कि यह बाबू लागो के लिए बन रहा है । हमन कहा कि यह तुम्हारे लिए ही बन रहा है । शायद उस ने सोचा कि लम्बी दाढी वाले झूठ नही बोलते है और यह सुन कर उस के चेहरे पर एक तरह से लाली आ गई कि सचमुच यह अस्पताल मेरे लिए बन रहा है । इस लिए यह भावना पैदा करने की जरूरत है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे है, वह बडी सजीदगी के साथ गरीबो को उठाने लिए करन जा रहे है । जहा तक को-आपरेटिव फार्मिंग या ज्वायंट फार्मिंग का ताल्लुक है, उस को कामयाब करने के लिए इस बात पर गौर करना चाहिए कि वह किस ढग से और किस तरीके से कामयाब हो सकता है । इस लिहाज से मै सोचता हू कि पहले हमें सर्विस को-आपरेटिव सोसायटीज को मजबूत करना चाहिए । वहा को आपरेटिव सोसाइटिया अगर मजबूत होगी तो इसमे काफी सहूलियत मिल सकती है इस ज्वायट फार्मिंग के काम को । गवर्नमेंट की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं जैसे स्माल सेविंग्स स्कीम है जिसमें सरकार उसको कमीशन भी देती है जो रुपया जमा करवाने में सरकार की मदद करता है और जो रुपय जमा करवाता है उसको सूद भी देती है । मगर यहा जो सर्विस को-आपरेटिव सोसाइटिया बनेंगी, इनमें तो वे लोग खुद फीस देकर इसके मेम्बर बनेंगे और उसका कोई ब्याज वगैरह भी नही है । इस तरह से रुपया जो जमा होगा वह ज्यादा मुफीद और ज्यादा फायदेमन्द किसानो के लिये हो सकता है अगर जो बातें मैंने बताई है उनको ध्यान में रखा जाये । यह बात तो मानी हुई है कि हमें इसको कामयाब करना है ।

यहा पर एक सवाल मिलकियत के बारे मे भी उठाया गया है और कहा गया है कि मिलकियत खत्म हो जायेगी । लेकिन मै समझता हू कि इसमे मिलकियत खत्म होने का सवाल ही नही है और न ही यह सवाल उठना चाहिये और इसका कारण यह है कि मिलकियत से ही, अपनत्व से ही आदमी मे काम करने के लिये उत्साह पैदा होता है । रशिया मे हमने देखा है कि वहा कोलेक्टिव फार्मिंग है कोलेक्टिव फार्म्स बने हुये है और मिल कर किसान खेती करते है, काम करते है लेकिन रशियन गवर्नमेंट भी इस बात पर आखिर आई है कि कुछ न कुछ जमीन किसान

[ज्ञानी गु० सि० बूलाफिर]

के पास होनी चाहिये जोकि उसकी मिलकियत हो। इसका एक तजुर्बा भी उसने किया है। हमने उन किसानों के घरों में जाकर देखा है कि जिनको रशिया की सरकार ने दो दो और ढाई ढाई एकड़ तक जमीन दे दी है ताकि उसमें वे लोग खुद ही बाग लगा लें, बागीचा लगा लें, गाये रख लें या मुर्गी पाल लें या किसी और तरह का काम कर लें। हमें मालूम करने पर यह बताया गया कि कालेक्टिव फार्म्स के जरिये किसान जितनी आमदनी करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आमदनी वे अपने दो दो और ढाई ढाई एकड़ में से कर लेते है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मिलकियत कर खत्म पूरे तौर पर रहे तो इससे उसको एहसास होता है कि यह सब कुछ मेरे लिये हो रहा है और मैं इस काम को कर रहा हू।

यहा पर देहाती और शहरी का सवाल उठाया गया है' लेकिन मैं कोई ऐसा सवाल उठाना नही चाहता हू और इस चीज को मैंने कभी भी पसन्द नही किया है। मैं तो समझता हूं कि अगर शहरी ज्यादा वोकल होंगे, ज्यादा समझदार होंगे तो उनकी मदद से देहात वालो को भी काफी फायदा पहुच सकता है। इसलिये देहाती और शहरी का सवाल उठाने से कोई फायदा नही है। मगर यह बात साफ है कि जो को-ओप्रेटिव सोसाइटिया वगैरह बनाई जाये उनमे जितने भी मुलाजिम रखे जाये, वे चाहे किसी भी को-ओप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर हो, उनमे से ही रखे जाये और देहाती ही रखे जाये। बल्कि मैं तो यहा तक कहूगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जब भी मुकाबले के इम्तहान ले या रखे तो इसके दो हिस्से बना दे, एक देहातियो के लिये, और एक उन लोगो के लिये जो बडे एडवान्स्ड है। देहातियों के देहातियो मे मुकाबले हो तो फिर उनको ज्यादा चीज मिल सकती है। अपनी चीज हासिल करने का, खुशहाल होने का और नौकरी हासिल करने का ही यह उसूल वहीं बल्कि ऐसा करके ही यह चीज जो है यह अधिक से अधिक फायदेमन्द साबित हो सकती है। मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मेरे मन में कोई देहाती या शहरी का सवाल नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंच सकता है, यही सवाल मेरे मन में है।

एक बात मैं और भी इस सबध में कहना चाहता हू। जो वेस्ट लैंड्स हमारे देश मे पड़ी हुई हैं, उनको काबिले काश्त बना कर, कल्टीवेबल बना कर, इन सोसाइटियो को दे दिया जाये तो बहुत जल्दी हमको अपने मकसद में कामयाबी मिल सकती है बहुत जल्दी अच्छे नतीजे निकलने की आशा की जा सकती है।

एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं और मैं चाहता हू कि उस पर बडी सजीदगी के साथ गौर किया जाये और यह अनाज के सकट से सबध रखती है और भावो के कट्रोल के बारे मे है। मैं समझता हू कि अशोक मेहता साहब की अध्यक्षता मे जो कमेटी बनी थी, उसने एक तजवीज पेश की थी और वह तजवीज प्राइस स्टेबेलाइजेशन बोर्ड के बारे में थी। उस तजवीज को मैं समझता हू जरूर अमल मे लाया जाना चाहिये। इसको मान लेने से अन्न सकट पर काबू पाने मे काफी मदद मिल सकती है। मैं आपको बतलाना चाहता हू कि पजाब एक बोर्डर स्टेट होने हुये भी और वहा पर कोई कुदरती हदूद न होने हुये भी इधर हिन्दुस्तान की हदूद के अन्दर सरहद पर एक एक इच भूमि में खेती की जाती है जहा पर बोर्डर बना हुआ है, वहा पर एक तार सी लगी हुई है, और उसी से यह पता चलता है कि यह हिन्दुस्तान है और वह पाकिस्तान। पजाब के किसान एक इच जमीन भी बोर्डर के साथ साथ जोतने से नही छोडते और वहा पर बहुत अच्छी किस्म की कपास पैदा होती है। बोर्डर पर चोरी छिपे या किसी दूसरी तरह

से डाका कोई डाल ले तो डाल ले या हमला कर दे तो कर दे मगर किसान जो है वह इतनी हिम्मत से काम लेता है कि वह आखिरी हद तक बड़े जोर से खेती करता है। इतना होने पर भी पंजाब की यह हालत है, जैसा कि श्री अचिंत राम जी ने कहा है कि वहा भी अनाज के भाव बहुत ऊचे चले गये हैं। इसका कारण यही है कि वक्त पर गवर्नमेंट भावों पर कंट्रोल नहीं करती है और वक्त पर अगर सिचुएशन को सम्भाल लिया जाये तो मैं समझता हू किसी किस्म का कोई सकट पैदा नही हो सकता है।

इस मामले को छोड कर अब मैं एक और बात की तरफ आता हूं। काश्मीर का मसला भी यहा उठाया गया है। जो भाई बड़े जोर के साथ इस बात का दावा करते है कि काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहिये मैं उन से कोई विरोध नही रखता हू। यह ठीक है कि काश्मीर जरूर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है। मगर मैं यह भी कहना चाहता हू कि अगर हमारे देश मे फिरकादाराना वातावरण पैदा हो गया तो फिर काश्मीर का मामला हर वक्त सशय मे और शुभे मे ही रहेगा। यह सीधी सादी सी बात है। आज काश्मीर के लोगो मे यह बात घर कर चुकी है कि हिन्दुस्तान मे फिरकादारी की बिना पर कोई हकूमत नही चल रही है और इसमे उन दिनों मे बडा एंथ्यूज्याज्म है। इसीलिये हमारे विधान ने सब से पहली बात रखी गई है कि फिरकादाराना कोई चीज हिन्दुस्तान मे नही होगी और इसी को ध्यान मे रखते हुए सैपेरेट इलैक्टोरेट की बात को उड़ाया गया। मगर फिर भी हमारे देश मे कुछ भाईयों ने किसी न किसी ढग से कोई न कोई बात ऐसे ढग से शुरू कर दी है कि जब इलैक्शन होते है तो इलैक्शन को फिरकादाराना बना कर, उनको लड़ा जाता है। इलैक्शन मे खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और वाहेगुरु के नाम पर वोट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातों की रोकथाम करने के लिये सरकार को एक जबर्दस्त कानून बनाना चाहिये जिससे फिरकादारी की बिना पर कोई भी अपील जारी न की जा सके खास तौर पर इलैक्शन के दिनो मे। जितनी बाते ईश्वर के नाम पर होती हैं या ईश्वर भक्ति के नाम पर होती है, वे सब बेसलेस होती हैं। मुझे एक खूबसूरत-सा शेर याद आता है जिसको सुनाये बिना मै नही रह सकता हू :—

खुदा के नाम पर दस्तो गरेबा हू खुदा वाले,
बहुत है जिस कद्र जिक्रे खुदा खौफे खुदा कम है।

खुदा का कोई खौफ नही है लेकिन फिर भी ऐसी बुनियादे बाधी जाती हैं जिससे फिरकादारी और झगडे और हमारे जितने काम हैं, तामीरी काम हैं, उनको नुकसान पहुचे। तो मेरी जो तजवीज है वह यह है कि कोई न कोई ऐसा कानून बनना चाहिये जिससे कि ऐसी सूरतो का मुकाबला किया जा सके और एक दम से किया जा सके।

आज बेशक यह कहा जाता है कि यहा किसी न किसी तरीके से काश्मीर के जो रिप्रिजेंटेटिव हैं वे ठीक ढग से चुन कर नही आते हैं। मैं समझता हू कि अगर हम अपने ठीक मकसद की तरफ आगे बढ़ते गये तो यह काश्मीर का सवाल भी खुद-ब-खुद हल हो जायेगा। अब तक जो काश्मीर के रिप्रिजेंटेटिव थे वे और ढंग से चुन कर आते थे। इसके बाद असैम्बली बनी तो असैम्बली द्वारा चुन कर वे आने लगे। कुछ दिनो के बाद यह सारी चीज हल हो सकती है। मैं खुद इस बात को महसूस करता हू कि जब हम जम्मू मे आगे काश्मीर की तरफ बढते हैं तो हमे थोड़ा सा अहसास होने लगता है जब हमे परमिट इत्यादि दिखाना पडता है कि जम्मू और काश्मीर कोई अलहदा चीज हैं। वे चीजे डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए ठीक भी हो सकती हैं या कोई और चीजे इसको करने के

[ज्ञानी गु० सि० मुसाफिर]

पीछे हो सकती है या कोई रुकावटें हो सकती हैं लेकिन मैं समझता हूं कि दरअसल फिरकापराना बातों के हट जाने से यह सारी चीज दूर हो सकती है।

अगली चीज जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि राष्ट्रपति जी ने शरणार्थियों के लिये भी एक पैराग्राफ लिखा है जिस के अन्दर दंडकारण्य का जिक्र आता है। मैं समझता हूं कि वहां पर जो जमीनें आबाद की जा रही हैं उन के सिलसिले में पंजाब के शरणार्थियों का भी ख्याल किया जाना चाहिये। आज वेस्ट पंजाब से आये हुए शरणार्थियों के लिये काफी कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अभी लोग ऐसे हैं जो जमीन जमीन करते हैं। अगर उन के पास जमीन हो तो उन के अन्दर शक्ति है ताकत है और वह काफी पैदावार कर सकते हैं तो उन को क्यों न फायदा उठाने दिया जाये। पंजाब के किसानों को भी जितना ज्यादा तादाद में वहां बसाया जा सके वहां पर उन को आबाद किया जाना चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं अपनी कांस्टिटुएन्सी के मुताल्लिक क्योंकि मैं अमृतसर से आता हूं जो कि एक मिली जुली कांस्टिटुएन्सी है। उस में आधा हिस्सा शहर का है और आधा देहात का।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) एक हल्का गुरदासपुर का भी है।

ज्ञानी गु० सि० मुसाफिर: राष्ट्रपति जी ने अपनी स्पीच के पैराग्राफ १४ में इस बात को माना है कि सूती कपड़े का जो उद्योग है उस को बड़ी ठेस पहुंची है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बतला सकूं कि कहां कहां पर उन को ठेस पहुंची है। हालांकि मैं उन को अच्छी तरह से जानता हूं, फिर किसी वक्त कहूंगा अगर मौका मिला। मगर इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये कि सूती कपड़े को जो नुक्सान पहुंचा है उस का बहुत सा हिस्सा अमृतसर के जिम्मे आया है। अमृतसर एक ऐसी जगह है जो कि पंजाब का एक दरवाजा है जिसमें सारे पंजाब को सहूलियतें मिलती हैं। अमृतसर ही आजादी की लहर में भी शरीक रहा है। सारी ऐक्टिविटीज जो देश की आजादी के लिये की गईं, उस में उस का हिस्सा रहा है।

एक बात मैं मि० दौलता के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। मुझे पंजाबी सूबे की बात कहनी है क्योंकि उन्होंने बड़े जोर से पंजाबी सूबे की वकालत की है। उन की मरजी है, वह करें। मगर मैं तो समझता हूं कि पंजाबी सूबा बना ही हुआ है। उन को उसी को पंजाबी सूबा मान लेना चाहिये। अगर कोई और हिस्सा उस में आता है तो जरूर आ जाये, हिमाचल भी आ जाये, मेरठ भी आ जाये, और भी बड़ा सूबा बन जायेगा। वह सारा ही पंजाबी सूबा है। हम लोग जबान के झगड़े में न पड़ें। वहां जो लोग रहते हैं उन सब की जबान पंजाबी और हिन्दी है। हिन्दी तो सब को पढ़नी ही है भले ही वह पंजाब के रहने वाले हों। अब उन को चाहिये कि वह पंजाबी पढ़ना शुरू कर दें। बस पंजाबी सूबा बना बनाया हुआ है। इसमें फर्क क्या है। उस में कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है नये सिरे से उन्होंने इस चीज का इस लिये कहा हो कि शायद पंजाबी सूबा बनने से हरियाना का सूबा भी अलग बन जाये। नहीं तो मैं समझता हूं कि पंजाबी सूबा बना हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहिब आप को पता है कि पार्लियामेंट की लैंग्वेज कमेटी बनाई गई थी मैं भी उस का एक मेम्बर था। मेरा यकीन है कि अगर उस कमेटी के चेअरमैन पंडित पंत न होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। उन के लिये लोगों के दिल में जो मान है उस

की वजह से या जो उन का काम करने का ढंग है उस की वजह से, सारा मामला ठीक हो गया वरना हर एक फिकरे के लिये झगड़ा होता। अक्सर ऐसा हुआ कि एक एक फिकरे के लिये झगड़ा हुआ लेकिन वह तय भी हुआ। अब भी एक भाई ने राज्य सभा में बड़े जोर से यह कहा, बंगाल, आसाम और साउथ के यह जो प्राविसेंज हैं उन पर अगर हिन्दी ठौंसी गई तो वे यह सोचेंगे कि यूनियन से ही अलग हो जायें। पार्लियामेंट के मेम्बर तक ऐसी बातें कहते हैं। इस लिये इस लैंग्वेज के सवाल को जितना ही कम उठाया जाये उतना ही बेहतर है। हम लोग स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन के सिलसिले में काफी तजुर्बा कर चुके हैं और बार बार इन बातों को पार्लियामेंट में कहने से कोई फायदा नहीं है।

इन अल्फाज के साथ राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो थैंक्स का मोशन पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, in the year 1958 we felt that the problems that the country was facing were such that 1958 was going to be a year of crisis, but 1959 has inherited such gigantic problems that we are again wondering whether this will not be a year of destiny for our nation.

It is perhaps natural that the question of food should have occupied much of the time of this House. The hon. Food Minister said that 68·7 million tons of foodgrains had been produced, and in the coming forecast, the production is expected to reach 70 million tons. And rightly, people have asked 'Then, how is it that this production is side by side with increasing prices, and in fact, prices so high that they are absolutely beyond the reach of the masses?'

In the first place, it appears to me that the figures which are quoted are not correct. Our statistics have been in a deplorable position, and statistics relating to food are the least reliable. And the Government is proceeding on a certain revolutionary plans for increasing food production. In the first place, with regard to State trading in foodgrains, I think on principle the project is sound. Apart from the fact that it will enable the agriculturist to have a better price for his produce, it is conceivable that State trading in foodgrains will largely do away with smuggling of foodgrains, hoarding of foodgrains and other antisocial activities with which food in particular is associated. But I am not unmindful of the dangers by which wholesale trade by State in foodgrains is going to be accompanied. In the first place, we have got no machinery all over the country, and in a large measure, we have to rely upon those very dealers whom we desire to oust. It is conceivable, therefore, that those reluctant parties who may carry out the projects may themselves be very keen in sabotaging them. We have got too few co-operatives which can undertake distribution of foodgrains in the remotest corners.

There is also a huge problem of financing the trade which at a very modest estimate would cost about Rs. 800 crores in investment. There is also the grave problem of storage of foodgrains. The hon. Food Minister once said that if storage could be satisfactorily managed, a great deal of deficit would be diminished. Storage is one problem where this Government is likely to fail. But in spite of that, I feel the time has come when the State must try that experiment, and I think the wishes of the people will go with the State for its success in this attempt.

The other experiment which the Government is bent upon trying, namely, collective farming or co-operative farming or joint farming—by various names it has been called—is an experiment on which I keep an open mind. I am not prepared one way or the other to pronounce right now that it is going to help increase

[Shri Naushir Bharucha]

production or that such an enterprise is bound to fail. In fact, we have been told that there are over 2000 farms where joint cultivation is being undertaken But I was surprised when yesterday or the day before the hon Minister, in reply to a question in the Lok Sabha, said that he was not even aware of the fact whether production in these joint cultivation experiments showed an increase in comparison over production in other private-owned fields It is rather surprising that when the Government talks of a revolutionary measure of such magnitude, which might affect the living conditions of one-seventh of the population of the world, there has not gone enough thinking into this project, and we are talking without having facts and statistics with us I should have thought that if we had in India 2000 experiments going on in joint cultivation, surely the Minister should have looked into this matter in greater detail and found out whether they are capable of fulfilling the purposes which they have in view But it is a matter of surprise that so little thinking has gone into the project that today even the vocabulary we use, the phrases we use—joint cultivation or joint farming or co-operative farming—are used as if they are interchangeable terms which they are not

I, therefore feel that in a revolutionary experiment of this character which will completely alter our problem of food supply—one way or the other, one does not know—the Government should have laid down a code for joint farming which would describe how our co-operatives are to function, which would describe in terms of a common denominator the lands and other implements of cultivation brought in by integrating farmers—the common denominator on which they would proceed What I mean is this Suppose a farmer brings in 10 acres of land which is rocky and not fertile and another person brings in 10 acres of land which is extremely fertile with a well and everything, suppose a farmer brings in a pair of bullocks which are rotten and another brings in another pair of bullocks which are certainly healthy and capable of doing work How are these things to be reduced to a common denominator in order to enable the production to be ultimately distributed amongst them on basis of equity and fairness? We do not have anything of this kind We are not even aware of how the various problems arising out of joint cultivation or joint farming would be solved

In fact, the hon Prime Minister was frank enough to admit that he could be asked a hundred questions on joint farming very awkward questions which he would not be able to answer I ask in a matter like cultivation, when we are experimenting with the destiny of one seventh of the population of the world, should the Government devote so little thinking into the making of that project into the formulation of that project? Nobody seems to have thought about it seriously

I am, therefore, of the opinion that if the experiment is to be tried out, it should be tried out with surplus land which would be available when a ceiling is introduced on existing lands There would be available a lot of surplus land This experiment should, in the first place be tried out in a dozen talukas in each of the States The experiment should have guidance from Government There should be a code informing people—there should be a manual prepared—as to how joint cultivation can be successful, what are the principles on which the produce would be divided what are the bases on which integration of various lands and farming implements would take place All these things should be publicised, and popularised and then it should be tried out in other talukas Subsequently,

the experiment may be extended in the light of the experience we gain

Connected with the question of food, there is another important problem, namely, unemployment It is a tragedy that as our Five Year Plans have progressed, there has been more and more unemployment The Second Five Year Plan is expected to produce 8 million jobs—which it will not produce—and the Third Five Year Plan, to make up the deficit of the Second, will have to produce between 15-16 million new jobs Any Plan which produces 15-16 million jobs would have to be of an order, of much higher than an investment of Rs 10,000 crores Obviously, we cannot do that But the tragedy of the thing is deepened by the fact that even while we have got industries in this country which are closing day after day, the Government does not take steps to take over those industries and run them In my own constituency, there are three industrial concerns—a textile mill in Jalgaon, another textile mill in Chalisgaon and a factory at Pachora which produces vanaspati ghee All these have been closed—one is partially closed Yet the Government does not take up the matter in hand Why? Because it says that the Industries (Development and Regulation) Act does not permit it, does not give it power enough We are here day after day passing amending legislation Why cannot we take power for this purpose? Take, for instance, the case where vanaspati ghee is manufactured at Pachora The factory the machinery, everything is absolutely in order Of course, the machinery and everything has been mortgaged The question would be what is to happen to the mortgagee? In that case, my suggestion has always been that the mortgagee can be paid off in transferable bonds bearing 4 per cent interest repayable at the end of 20 years out of the profits of the concern and the concern must go unencumbered to the Government and the Government must run it

It is tragic that while we are hunting and trying to create new industries, to create more employment, old industries are closing down for want of good management, due to quarrels among partners and so forth, and the State looks on helplessly saying that they have not got the power, when day in and day out we can take power and see that these industries do not close down

One word about taxation and the magnitude of our Plan I am convinced that the coming Budget is likely to impose on us at least Rs 20 crores of new taxation I doubt, even if it imposes that, whether it can make both ends meet so far as the Plan is concerned Within the next two years—after the third year which is practically over—we have still to spend Rs 2200 crores if we want to reach the target of Rs 4800 crores or, even for the matter of that, Rs 4500 crores Wherefrom are we getting these Rs 2200 crores? Nobody knows I doubt whether the Finance Minister himself knows In this House, we have repeatedly asked, 'At least let us know broadly what are your internal resources How do you propose to get over the next two years Rs 2200 crores out of which $700 million will be the foreign exchange content?' Where are we getting this amount from? Still we are talking airily of a Third Five Year Plan running into an investment of Rs 10 000 crores I submit it is up to the Government to reply to this

In conection with our foreign policy, I submit by and large, our foreign policy is appropriate and the only one which we could have adopted in the circumstances in which we are situated A policy of non-alignment is the only policy which a country like India situated in a dangerous world can adopt

Today, in South East Asia, I was told by a British M P that India is looked upon as the leader of South

[Shri Naushir Bharucha]

East Asia Why? Because of our foreign policy of non-involvement and efforts to relieve world tension I am not satisfied that in the matter of reinforcing world peace we have done enough We have done practically nothing And, if smaller nations are brought together and if a sort of what we may call a Third Force is created, it will be definitely a force in favour of peace, then, I am of the opinion that we shall have contributed something substantial to the stabilising of world peace

It may be argued, what can a coalition of cripples, smaller nations who are attached either to one Bloc or the other, do in the existing circumstances? These small nations are also aware of the fact that if a world war breaks out, then, they will also be the victims And, if they are attached to one Bloc or the other, they are more attached to their own instinct of self-preservation And, I think, some effort should be made in this direction

Mr Deputy-Speaker, I do not desire to take much of your time But I do feel that unless in the year 1959 the food question is solved and solved satisfactorily, there may be no Third Five Year Plan in 1961

श्री रा० क० वर्मा (निमाड) उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रक्खा गया है उस के पक्ष और विपक्ष मे बहुत से माननीय सदस्यो ने अपने विचार रक्खे है । मैं भी अपने कुछ विचार इस सम्बन्ध मे रखने का प्रयत्न कर रहा हू ।

जहा तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सवाल है, उस अभिभाषण के अन्तिम के दो पैराग्राफो अर्थात् ५३ और ५४ के अन्दर जो बातें कही गई है, उनके ऊपर हमारे देश की तरक्की और हमारे देश का विकास आधारित है । अब यहा पर यह विचार करने की जरूरत है कि जो बातें अन्तिम पैरो में कही गई है, वे हमारे देश के अन्दर मौजूदा स्थिति मे कहा पर देखने को मिल रही है ? उन पैरो के अन्दर शान्ति, सगठन और हमारे माननीय सदस्यो का और देश का सहयोग चाहा गया है । जो देश के विकास के लिये निहायत जरूरी है , और किसी भी देश ने दुनिया के अन्दर जो तरक्की की है वह सगठन, सहयोग और शान्ति के आधार पर ही की है । जहा पर सगठन, सहयोग और शान्ति है वह देश सभी प्रकार से अपना विकास कर सकता है । हम रशिया की बात करते है । रशिया में भले ही सगठन न हो, शान्ति न हो, सहयोग न हो, लेकिन उन्होने इस एक तरह से नही दूसरे तरीके से, जबरदस्ती से, बल से, शान्ति, सहयोग और सगठन बनाने का प्रयत्न किया । इसलिये आज रशिया इतना आगे बढा है । अमरीका मे पैसे या सत्ता के जरिये या दूसरी तरह से उन्होने शान्ति, सहयोग और सगठन बनाया है । आज चीन का उदाहरण हमारे विरोधी मित्र देते है । लेकिन चीन में सगठन नही था, सहयोग नही था, और शान्ति नही थी । यही कारण था कि चीन की इतनी बुरी हालत रही । लेकिन जब सत्ता के द्वारा, बल के द्वारा, शक्ति के द्वारा सगठित करने की कोशिश की गई सहयोग मिला, शान्ति पैदा हुई तो आज वह आगे बढ रहा है । हमारे देश की स्थिति भिन्न प्रकार की है । हमार देश ने प्रजातन्त्र को अपनाया है । सभी को आजादी और स्वतन्त्रता मिली हुई है । लेकिन बडे दुख के साथ कहना पडता है कि कुछ करने के बजाय हमारी एक यह आदत पड गई है और यह एक हमारा फैशन बन गया है कि करप्शन को हटाने के लिये, विकास के लिये, और दूसरे कामो के लिये केवल हम गाधी जी और विनोबा जी का नाम लेते है । और उनका नाम ले कर हर काम उनके विपरीत

कर रहे हैं । हमारे हाथ पैर नही चलते । हमारा दिमाग नही चलता । लेकिन हमारी जबान बहुत ज्यादा चलने लग गई है । आप देश की किसी भी राजनैतिक पार्टी को देख लीजिये, उसके अन्दर फूट है, असहयोग है, अशान्ति है । और यही कारण है कि जो कि राष्ट्रपति जी ने कहा है, आज हम उस दिशा से विपरीत दिशा मै काम कर रहे है । मै यह निवेदन करना चाहता हू कि राष्ट्रपति जी ने इन दो पैराग्राफ मे हमारा बहुत कुछ मार्गदर्शन किया है । अगर हम उस चीज को लेकर चलते है तो हम अपनी तरक्की कर सकते है । हम अपना विकास कर सकते है ।

विरोधी पक्ष के सदस्यो ने करप्शन की बात कही । दरअस्ल यह सही बात है । मै कहता हू कि उन्होने जो सही बाते कही हैं उनका हमे स्वागत करना चाहिये और हमारे ही पक्ष के लोगो ने जो गलत बाते कही है हमें उनका विरोध करना चाहिये । इतनी हिम्मत, इतना साहस और इतनी नैतिकता जब तक हमारे अन्दर नही होगी, तब तक हम तरक्की नही कर सकते यह मानी हुई बात है । लेकिन मै एक निवेदन करना चाहता हू । कोई कहता है कि करप्शन नीचे से है, कोई कहता है कि ऊपर से है, श्रीमान, हर जगह करप्शन मौजूद है । हमारे विरोधी पार्टी के कम्युनिस्ट मित्रो ने करप्शन की बात कही है । श्रीमान, अभी हल्दी भी नही सूखी है । आप देखे केरल के अन्दर क्या हुआ । मै यह निवेदन करना चाहता हू कि केरल के अन्दर गवर्नमेंट बने ज्यादा दिन नही हुये, हमे पढने को मिला कि केरल गवर्नमेंट ने आन्ध्र से बहुत सा चावल खरीदा और वह अपनी पार्टी के एक सदस्य द्वारा । उन्होने महगे भाव से केरल के लिये आन्ध्र से चावल खरीदा और उनकी पार्टी के सदस्य द्वारा जिस सदस्य को ऊपर से ५० हजार का फायदा हुआ । यह सब हमको पढ़ने को मिला है । यह एन्क्वायरी मे भी आया है । मै उन माननीय सदस्यो से कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरो पर कीचड उछालते है, तो अपना मुह भी आइने मे देखिये । जब आप अपना मुह आइने मे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहा है । आज हर एक दूसरे पर आरोप लगाता है । लेकिन अपनी खुद की तो बात करिये । हमने देखा कि केरल मे कम्युनिस्ट सरकार बनने के पहले जहा भी गोली चली या लाठी चली तो कम्युनिस्टो द्वारा यह कहा जाता था और आन्दोलन किया जाता था कि लाठी गोली की सरकार नही चलेगी, नही चाहिये। श्रीमन्, केरल मे कम्युनिस्ट सरकार बने जब १५ महीने भी नही हुये थे, वहा कितनी बार गोली और लाठिया चल चुकी, कितने मरे और घायल हुये ? पर वह सरकार वहा क्यो चल रही है ? इसलिये मै यहा यह निवेदन करना चाहता हू कि हमारे विरोधियो को यह समझ लेना चाहिये कि दूसरे के ऊपर तो कीचड उछालना आसान है । लेकिन हम क्या कर रहे है? हर एक व्यक्ति, हर एक सस्था स्वय अपने पैरो को देखे कि वे कहा खडे है । मोर कितनी अच्छी बोली बोलता है, लेकिन जब वह अपने पैरो को देखता है तो उसकी भी आख मे आसू आ जाते है । तो मै विरोधी पार्टियो के सदस्यो से यह निवेदन करूगा कि आप ऐसी बाते करते है, लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे मे भी कुछ विचार करिये । श्रीमन्, यहा पर कई विरोधी पार्टी के सदस्यो ने और कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री डागे जी ने मथाई और मूदडा की बात कही । मैं यह मानता हू कि काग्रेस पार्टी हो, या गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, ऐसे एलीमेंट को खत्म कर देना चाहिये । जरा भी रियायत नही करनी चाहिये । लेकिन हो क्या रहा है ? लेकिन हो यह रहा है कि ऐसे एलीमेंट को सहयोग और सम्मान दिया जाता है । फिर उस अवस्था मैं देश मे क्या होने वाला है । मूदड़ा का किस्सा पिछली साल पार्लियामेंट में

[श्री रा० कृ० वर्मा]

काफी चला । लेकिन हमने सुना कि मूदड़ा ने कलकत्ते में पूजा के दिनों में खाने पीने का कोई आयोजन किया उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य जो यहा उनकी पार्टी के डिप्टी लीडर हैं मुख्य अतिथि के तौर पर उसमे शामिल हुये । यहा तो कम्युनिस्ट मित्र सारी बाते करते हैं—कभी मूदड़ा की और कभी मथाई की—और दूसरी तरफ उनको ही सहयोग भी देते है । इस हालत मे मूदड़ा क्या नही कर सकते । हमने पार्लियामेंट मे बड़ी बड़ी चर्चा सुनी और सुना कि छागला कमीशन के सामने एवीडेंस के लिये जब कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडरो से कहा गया कि आपको भी इस सम्बन्ध मे कुछ कहना है तो कहिये, उन्होने कहा कि हमें कुछ नही कहना और उसके सामने गये तक नही । लेकिन यहा पर वह गवर्नमेंट पर हमला बोलते हैं । यह हमारी नैतिकता है । यही हमारे अन्दर राष्ट्र धर्म है । हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं ।

हमारे विरोधी पार्टी के सदस्यो द्वारा अक्सर यह कहा जाता है कि यह पूजीवादी सरकार है । इस सरकार पर पूजीपति लदे हुये हैं । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हू कि केरल मे जो केरल सरकार का बिडला जी के साथ समझौता हुआ है वह यह मेरे पास मेरे सामने है । इस एग्रीमेंट में जो कि श्री बिडला और केरल सरकार में हुआ है बहुत सी बाते है, वह बहुत लम्बा चौडा है । माननीय अध्यक्ष, आप कहे और आज्ञा हो तो सदन की टेबल पर रख दू ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा नम्बर २७ में यह जिक्र किया है कि उद्योगपति, मजदूरो और सरकार मे एक समझौता हुआ है । वह अनुशासन के सम्बन्ध मे समझौता हुआ है कि कोई भी एक पक्षीय कार्रवाई न करे । किन्तु, श्रीमान्, केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने जो बिडला जी के साथ समझौता किया है वह एक पक्षीय ही नहीं है बल्कि संविधान के भी खिलाफ है । एक बोर्ड ने या अदालत ने यह फैसला कर दिया है कि प्राफिट के अन्दर अमुक डिप्रिसियेशन निकाला जायेगा, अमुक डिवीडेंड निकाला जायेगा, मशीनरी को बदलने के लिये अमुक रकम निकाली जायेगी, रिजर्व के ब्याज का इतना परसेंटेज रखा जायेगा, और बाकी रकम जो बचेगी यह मजदूरो को बोनस के तौर पर बाटी जायेगी । पर केरल गवर्नमेंट ने जो बिडला जी के साथ एग्रीमेंट किया है उसमे यह कहा है कि प्राफिट के ऊपर मजदूरो को बोनस नही दिया जायेगा, हम प्रोडक्शन बोनस देगे । श्रीमान्, यह तो सदा से पूजीपतियो का कहना और पक्ष रहा है, आज से नही वर्षों से है कि प्रोडक्शन बोनस दिया जाये प्राफिट पर नही किन्तु हमने इस बात को स्वीकार नही किया और न अदालत ने ही । लेकिन प्रोडक्शन बोनस अलग चीज है और प्राफिट बोनस का एक अलग फारमूला है और प्रोफिट शेयरिंग के सिद्धान्त को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जा चुका है । प्राफिट के अन्दर गवर्नमेंट भी शरीक है, प्राफिट के अन्दर मजदूर भी शरीक हैं, और इन्डस्ट्री भी शरीक है । मै निवेदन करना चाहता हु कि विरोधियो की सारी बाते कहने के लिये ही है, करने के लिये नही । करनी और कथनी अलग अलग है । किन्तु यह चीज ज्यादा चल नही सकती ।

उस एग्रीमेंट मे यही एक बात नही है । कितनी ही बाते हैं । डिसिप्लिन की बात है । कारखाने मे डिसिप्लिन नियम किसका होगा और ग्रीवास प्रोसीज्योर क्या होगा ? वहा उस कारखाने मे बिडला जी का होगा । नैनीताल कानफ्रेंस में और दिल्ली के अन्दर जो सन् १९५७ मे इंडियन लेबर कांफ्रेंस हुई थी उसके अन्दर यह तै हुआ था कि इंडस्ट्री मे डिसिप्लिन जो नियम गवर्नमेंट, उद्योगपति और श्रमिक इन तीनो द्वारा तैयार

किये जायेंगे वे होंगे । जब उस कान्फ्रेंस के अन्दर यह तय हो गया कि डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री इस तरह से रहेगा, ग्रीवेंस प्रोसीजर यह होगा, तो क्या कारण है कि केरल की सरकार ने बिड़ला जी के साथ बैठ कर यह तय कर दिया कि नहीं केरल के इस कारखाने में तो केवल बिड़ला जी द्वारा तैयार किये गये नियम डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री होगा और उन्हीं द्वारा तै किया गया ग्रीवेंस प्रोसीजर भी होगा । इस सब का क्या मतलब है ? हम पार्लियामेंट में बैठ कर कोई नीति निर्धारित करते हैं और कहते हैं कि भविष्य में यह होगा लेकिन केरल के अन्दर हम देखते हैं कि उल्टी गंगा ही बह रही है ।

इस पार्लियामेंट के अन्दर हमारे विरोधी दल के कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने का विरोध किया है किन्तु वहां केरल की सरकार का बिड़ला जी ने यह साफ साफ बता दिया है कि यहां जो कारखाना डाला जायेगा और चलेगा वह अमरीकी पूंजी से ही चलेगा और इस पर केरल सरकार कहती है कि यह एग्रीमेंट बड़ा भारी और प्रगतिशील हमारा कदम है । मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों के लिये यह समझ लेना आवश्यक है कि वे क्या कहने आ रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट केरल में क्या कर रही है ।

अब मैं जो असली चीज है और जिसको लेकर जनता में हाहाकार मचा हुआ है उस पर आना चाहता हूं और वह अनाज की महंगाई के बारे में है । सन् १९५७ में मैंने इसी पार्लियामेंट के अन्दर अनाज समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किये थे और काफी मैटर इस सदन के सामने तथा माननीय मंत्री महोदय के सामने रखा था । लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को एक आदत सी पड़ गई है और इन्हीं मंत्री महोदय को नहीं बल्कि सभी मंत्रियों को पड़ गई है कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ आयेगा उस पर तो वे गौर करेंगे और जो अंग्रेजी में बात की जायेगी, उसे तो वे सुनेंगे लेकिन जो हिन्दी में लिखा हुआ आयेगा या जो हिन्दी में बात की जायेगी, उसको न वे पढ़ेंगे और न ही उस पर कोई ध्यान देंगे । जो लोग राष्ट्रभाषा में बात करते हैं, उनकी कोई सुनता ही नहीं । इस तरह की बातों में क्या आप राष्ट्रभाषा की कद्र कर रहे हैं यह मैं पूछना चाहूंगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरे १९५७ के भाषण के प्रोसीडिंग्स जो अनाज समस्या पर दिया गया था को निकाल कर मंत्री महोदय देखेंगे तो उन को पता चल जायगा कि जिस बात के लिये वह आज पश्चाताप कर रहे हैं उस का आज उन को पश्चाताप न करना पड़ता अगर उन्हों ने मेरी बात पर उस समय ध्यान दिया होता । मैं आज फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ भी कहे या कुछ भी करे लेकिन हमारे देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है और अनाज का काफी उत्पादन हमारे देश के अन्दर होता है और सच बात तो यह है कि उत्पादक किसान तो पैदा करता है और जो कन्ज्यूमर उपभोक्ता है उस को उत्पादित चीज प्राप्त नहीं हो पाती है होती है तो बहुत मंहगी । सच्चे मानें में आज क्या गवर्नमेंट के ऊपर और क्या राजनैतिक पार्टियों के ऊपर वितरक का असर है और जो वितरण करने वाले हैं उन का असर होने से ही आज यह सब हालत और हाहाकार है । जो वितरक लोग हैं वे शासन को कहिये या राज व्यवस्था को कहिये, या जनता को कहिये, उस को कभी भी खतरे में धकेल सकते हैं और धकेल रहे हैं । इसवास्ते यदि सारी चीज पर विचार किया जाये तो पता चलेगा कि जितना हमारा उत्पादन है चाहे वह गल्ले का हो या किसी दूसरी चीज का, उस का वितरण सही ढंग से जिस ढंग से होना चाहिये, नहीं हो पाता है । आज जो पैदा होता है उस को सही तरीके से जरूरतमन्द लोगों तक, उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की आवश्यकता

[श्री रा० क० वर्मा]

है जो कि आज नही पहुच पा रहा है। आज केवल अनाज के ही भाव नही बढे है बल्कि लकडी कोयले के भाव भी बहुत ऊचे चले गये हैं, केरोसीन के बहुत ऊचे चले गये है। सभी चीजो के भाव बहुत ऊचे चले गये है क्यो क्या इन का भी उत्पाद घटा है या नही। मै आप को बतलाना चाहता हू कि मेरे प्रदेश के अन्दर जहा अनाज बहुत ज्यादा पैदा होता है वहा पर बाहर के व्यापारियो ने उसी गेहू को जिसे उन्हो ने किसानो से १२ रुपये और १३ रुपये मन खरीदा आज ३६ रुपये मन बेच रहे है। इस खरीद और बेचान की बात का अभी ज्यादा देर भी नही होने पाई है, यह सब चीज केवल आठ महीनो के अन्दर अन्दर ही हुई है। मान लीजिये थोडी देर के लिये कि आप ने भाव बाध दिये

उपाध्यक्ष महोदय आप जल्दी से खत्म कीजिये, कुछ और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते है।

श्री रा० क० वर्मा मै निवेदन करना चाहता हू कि किसी भी माननीय सदस्य ने इस विषय पर सविस्तार नही कहा है और इस सम्बन्ध मे कुछ विशेष कहने के लिये मुझे आप थोडा ज्यादा समय दे।

उपाध्यक्ष महोदय दो तीन मिनट मे आप अपनी बात कह लीजिये क्योकि और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते है।

श्री रा० क० वर्मा मै कहना चाहता हू कि खाद्य पदार्थों के अधिक भाव बढने से जो गरीब लोग है उन की सारी की सारी आमदनी खाद्य पदार्थों की खरीद के अन्दर ही खर्च हो जाती है और इन के ही अन्दर पूरी आमदनी के खर्च हो जाने से दूसरी जरूरत की चीजे है उन को वे खरीद नही पाते है। अगर इस का कोई हल नही निकाला गया और कुछ समय ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश मे भयकर बेकारी पैदा होने का खतरा पैदा हो सकता है। इस का कारण यह है कि लोगो की खरीदने की शक्ति घट रही है और इस का नतीजा यह हो रहा है कि खाद्य पदार्थों को खरीदने के बाद उन के पास पैसा नही बच पाता है और जब पैसा नही बच पाता है तो दूसरी जो वस्तुये तैयार होती हैं उन को कौन कैसे खरीदेगा और अगर कोई नही खरीदेगा तो स्टाक जमा हो जायेगा और जो लोग उन्हे तैयार करने में लगे हुए है वे बेकार हो जायेंगे। इस तरह से एक दूसरी ही समस्या बेकारी की हमारे देश में पैदा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी का तो था वैसे ही भयकर हाल है फिर गवर्नमेंट की भी यह मान्यता हो गई है कि कोई भी समस्या हो उसे हल करने के बजाय टालने की गरज से उस की जाच के लिये बोर्ड स्थापित कर दिये जाते है, कमेटिया बिठा दी जाती है। कमेटिया बना कर के लोगो को घपले मे डाल दिया जाता है और जब अरसे के बाद कमेटिया अपनी रिपोर्ट दे भी देती है तो उन की राय को शासन द्वारा कोई वजन नही दिया जाता है। मै टैक्सटाइल इन्क्वायरी कमेटी की ही बात को लेता हू। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ६० और ६१ मे इस बात पर जोर दिया था कि जो कपडा मिले बन्द है या बन्द होने वाली है या बन्द होने लायक है उन के चलाने के लिये एक आटोनामस कारपोरेशन बना दी जाय और उस कारपोरेशन के अन्दर गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो, मिल मालिको के हो, और साथ ही साथ मजदूरो के हो। इस चीज को तीनो ने एक राय मे तय किया। अब गवर्नमेंट यह कहती है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को तो हम स्वीकार करते है लेकिन ये जो दो पैराग्राफ है जिन मे कारपोरेशन का जिक्र है, इस को स्वीकार करने के लिये हम तैयार नही है।

श्रीमन, एक तरफ कारखाने चालू करने की बात की जाती है, इम्पोर्ट की बात की

जाती है दूसरी तरफ एक्सपोर्ट की बात भी की जाती है। लेकिन जो कारखाने चल रहे हैं जिन्हें चलते रहने दिया जा सकता है और जिन के बारे में तीनों की एक राय है, उसे स्वीकार करने के लिये और उन को चलाये रखने के लिये गवर्नमेंट तैयार नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी तरफ यह हाल है कि अनाज महंगा हो रहा है और उसे हमें विदेशों से बड़ी मात्रा में मंगवाना पड़ रहा है। साथ ही साथ सस्ते अनाज की दुकानें खोली जा रही हैं लेकिन उन दुकानों से गरीब आदमियों को अनाज नहीं मिल रहा है और इस अनाज को ले कर मुनाफाखोरी की जा रही है। जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट लोग हैं सस्ते अनाज में से वह आधा अनाज तो पहले ही गुप्त रूप से गायब कर के रख लेते हैं, अपने नौकरों चाकरों को कहते हैं कि तुम्हें प्रति व्यक्ति चार चार आने देंगे और उनकी औरत बच्चों को ले कर अपनी उस दूकान के सामने बिठा देते हैं और वे क्यू में लग कर अनाज वापिस ले जाते हैं। इस तरह से जो अनाज उन के पास वापिस आजाता है उस को देशी अनाज में मिला कर वे लोग अपनी दूकान से बेच देते हैं। सस्ती दूकानें चालू करने का तो यह मतलब था कि अनाज के भाव गिरेंगे, लेकिन भाव गिरे नहीं हैं। बल्कि बेहद बढ़े हैं और आज यह हालत हो गई है कि जहां पहले हम वर्ष में २८ करोड़ का अनाज बाहर से मंगाते थे वहां आज डेढ़ अरब का अनाज हम ने मंगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो आप फौरन एक्सचेंज की बात करते हैं और दूसरी तरफ यह हो रहा है कि हमारे देश में

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय खत्म हो गया है। श्री अजेश।

पंडित अजनारायण "अजेश" (शिवपुरी) : कृष्णं वन्दे जगतगुरुम्

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और जो बातें कह दी गयी हैं उन का पृष्ठ पोषण करना मैं व्यर्थ समझता हूं। सम्पूर्ण अभिभाषण को पढ़ने के पश्चात् मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने, देश में जो अर्थ संकट आया है, उस पर चिन्ता व्यक्त की है और हमारे मनों में उत्साह उत्पन्न हो, इस के लिये उन्हों ने एक लम्बी तालिका उन योजनाओं की दे डाली है जो कि देश के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये चलाई जा रही हैं और जो कि सम्पूर्ण योजनाओं से सम्बन्ध रखती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री डांगे साहब ने कहा है कि यह अभिभाषण स्फूर्तिदायक नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है। अब स्फूर्ति कहां से लाई जाय, कहां से उधार मांगी जाये या किसी से प्रार्थना की जाय कि आप स्फूर्ति पैदा कर दीजिये ? ऐसी दशा में जो वस्तुस्थिति है, उसी का दिग्दर्शन कराया जा सकता है। स्फूर्ति के लिये आवश्यक तौर पर सब्ज बाग दिखाने से भी काम नहीं चल सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ते लड़ते बहुत से सब्ज बाग दिखाये लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। वैसे ही सब्ज बाग सत्तारूढ़ होने के बाद भी दिखायें, मैं समझता हूं कि इस से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

जो कार्य चल रहा है उस की एक तालिका उन्होंने हमारे सामने रखी है। इस में कोई सन्देह नहीं है कि देश में अर्थ संकट आया है और मैं ने अनेक बार इस सम्बन्ध में निवेदन किया है कि हमारे देश को जो स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है वह बड़े भयानक शोषण के पश्चात् प्राप्त हुई है। करीब करीब एक हजार वर्ष तक इस देश का शोषण होता रहा, लूट पाट होती रही, कुछ तो तलवार के बल पर शोषण हुआ और कुछ छल के द्वारा शोषण हुआ। छल और बल दोनों के द्वारा शोषण होने के पश्चात् देश को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। अब उस प्राप्त स्वतन्त्रता में जो हो सकता है, वही किया जा सकता है और वह हो रहा है। इस में सब से बड़ा दोष जो मुझे दिखाई पड़ता है वह एक

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

ही है कि अब हमारे शासन के पास देश में आकर्षण पैदा करने के लिये सिवा योजना के और दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया है। प्रथम योजना समाप्त हो गई, द्वितीय पंच-वर्षीय योजना का तीसरा वर्ष समाप्त होने जा रहा है।

इस तृतीय वर्ष में ही तृतीय योजना के सम्बन्ध में रूपरेखा का निर्माण करने की भूमिका का निर्माण होने लगा है। योजना क्या बनती है माना लोग समझते हैं कि सोने पीने के लिये एक नया रास्ता ही निकलने वाला है। जब तक योजना को पूर्ण करने का वायु-मंडल उचित रूप में निर्मित नहीं होगा तब तक योजना केवल कागजों में ही रहेगी जैसा कि हम को दीख रहा है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना के समाप्त होने के पश्चात् भी देश में भयानक अन्न संकट आ गया। उस अन्न संकट के लिये कहा जाने लगा कि कुदरत ने साथ नहीं दिया, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, इस लिये आ गया। मगर उस का कारण यह नहीं है। उस का मुख्य कारण यह है कि जिन के लिये हम लाभ लाना चाहते हैं उन के संकटों को दूर करने के लिये योजना में कुछ नहीं था। इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक किसान को डाइरेक्ट लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक अन्न का संकट देश से नहीं जायगा। जो पैदा करने वाले हैं वे नर-कंकाल हैं। वह लोग ठोकर खाते हैं, फिर उठ कर दौड़ते हैं और फिर ठहर जाते हैं। इस वास्ते अगर उन पर ही नवीन योजनाओं का भार लाद दिया जाता है तो चाहे जितनी भी योजनायें बनें वे सफल नहीं होंगी। योजना को सफल करने के लिये एक नये आधार को पेश किया गया। और वह यह है कि कोआपरेटिव बेसिस पर खेती चलाई जायगी।

'ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते,
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवम् नष्टमेवहि।"

जो पास में हो उस को तो छोड़ देते हैं और जो नहीं है उस को पकड़ते हैं। नहीं को तो नहीं ही किया और जो है उस को भी वह भूल जाते हैं। इस तरह देश के लोगों का फायदा कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं कि शासन जो भी कार्य करता है, उस में उस को देश का सहयोग मिलना चाहिये। इस में कोई दो मत नहीं है, लेकिन अगर शासन सहयोग मांगे और लोग कहें कि हम असहयोग करेंगे तो काम कैसे चलेगा? आज देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो सामने आ कर सत्ता को हाथ में ले कर चल सके। एक कांग्रेस दल ही बाकी बचा है, वही एक पार्टी है जो कि देश व्यापी है और कदम आगे बढ़ा कर चल सकती है। यों तो दलगत नीति के कारण कोई खड़ा हो कर बोल सकता है कि यह दोष है, वह दोष है, वह खराबी है लेकिन क्या वे लोग देश की बागडोर सम्भालने में समर्थ हैं? वह केवल आलोचना करने में ही समर्थ हैं। ठीक है आलोचना होनी चाहिये लेकिन कम से कम लोक सभा में आलोचना शासन को भला बनाने के लिये होनी चाहिये, न कि पार्टी के प्रोपेगैन्डा के लिये होनी चाहिये। शासन का यह पता लग जाय कि हमारी कमजोरी कहां है, वह लोग भी जनसम्पर्क रखते हैं लेकिन हो सकता है कि भय के कारण कोई पार्टी के सदस्य विरोध न करते हों। जो विभिन्न विचारों के व्यक्ति हैं वे लोग जनता से सम्पर्क स्थापित कर के शासन के सामने इस बात को रक्खें कि देश में एक यह भी प्रतिक्रिया है आप के विचारों की तरफ। शासन को भी गम्भीरता से सोचना चाहिये कि दूसरे लोग भी देश के नागरिक हैं और उन के सामने जो देश की परिस्थिति है वह भी कुछ महत्व रखती है। उन को इस से ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये कि उन्होंने यह पास कर लिया, वह पास कर लिया। ऐसा विचार शासन का नहीं होना चाहिये, लेकिन शासन हटधर्मी करने तो शासन का भी दुर्भाग्य होगा और देश का भी।

सहकारिता के आधार पर खेती करने की जो बात आप सोच रहे है उस के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जहा जहा भी सरकार ने को-आपरेटिव बेसिस पर व्यापार किया वहा उस को असफलता ही मिली । मध्य प्रदेश मे जो ग्वालियर का राज्य था उस समय एक जी० एन० आई० टी० कम्पनी चलती थी, चूंकि वह राज्य की थी इसलिये लाभ मे चलती थी । उस समय उस को सरकार नही चलाती थी। जब से वह को-आपरेटिव बेसिस पर चलने लगी है उस का घाटा ही घाटा हो रहा है । ड्राइवर क्लीनर, कन्डक्टर तक ही सारा पैसा रह जाता है और कम्पनी मे घाटा आता जा रहा है । नई मोटरो को पुरानी करके वे बेचते है और दूसरी नई मगवाते है, दोनो मे ही नफा कमाते है । जब इस पद्धति मे काम चलेगा तो लाभ कहा से हो ? अगर चार आदमियो को पकड कर जबरदस्ती खेत पर लगा दिया जाय को आपरेटिव सिस्टम मे काम करने का, तो एक सोचेगा कि दूसरा करे और दूसरा सोचेगा कि तीसरा करे । और इस तरह से काम कोई होगा नही । जब तक कम्पिटीशन नही होगा, जब तक लाभ उठाने की भावना नही होगी तब तक जबरदस्ती मे कोई काम नही करेगा । यह तो एक निश्चित मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है । हा कुछ बन्धन लगा कर काम कराये उन मे कह दे कि तुम को काम करना पडेगा अगर नही करोगे तो गोली मे मार देगे या जेलखाने मे डाल देगे तो भय मान कर भले ही वे कुछ काम कर दे लेकिन भय नही रहा, आदर्श भी नही रहा और राजी भी नही कर सके तो काम कैसे चलेगा ? इस का परिणाम यह होगा कि शासन को भी इस का फल भोगना होगा और देश को भी । कई एक सज्जन खडे होगे । वह कहेगे हम ने ससार के बहुत से स्थानो मे देखा कि को-आपरेटिव सिस्टम फेल हो गया । लोग भी अनुभव करने लगेगे कि अब इस सिस्टम को बदल देना चाहिये और नया लाना चाहिये । तब तक कही ऐसा न हो कि सरकार ही बदल जाये ।

"बुभुक्षित किं न करोति पापम् ।"

भूखा क्या पाप नही करता ?

"कष्टात् कष्ट परम् क्षुधा"

मै ने अखबारो मे पढा कि एक जगह नौकर ने किसी होटल मे से तीन रोटिया चुरा कर खा ली । इस पर मैनेजर ने उस को इतना पिटवाया कि वह हास्पिटल जा कर ही मर गया । तीन रोटियो की चोरी के लिये बेचारे की जान ही चली गई । अगर इस तरह से होता रहा तो कैसे काम चलेगा ? भूखमरी चीज ही ऐसी खराब है और आप उस को अपनी दृष्टि से ओझल नही कर सकते । यह समझना चाहिये ।

16 hrs

यह निश्चित बात है कि भ्रष्टाचार बढ रहा है । हर जगह पर बढ रहा है । ऐसा नही है कि शासन मे ही बढ रहा है, हम मे भी बढ रहा है, मै सोचता हू कि शायद मुझ को मिनिस्ट्री ही मिल जाये और जैसे दूसरे मिनिस्टर खा रहे है उस का आधा मै भी खा लू । यह शोचनीय बात आज देश में आ गई है । लेकिन हम को यह समझ लेना चाहिये कि इस भावना का निर्माण हुआ है शासन सत्ता के कारण, क्योकि शासन सत्ता मे जो लोग थे उन मे यह बल था कि वे लोग जनता को प्रभावित कर सके । कुछ भी हो, चाहे यह चीज हमे पसन्द हो या न हो लेकिन एक चीज माननी पडेगी कि कांग्रेस ने देश की स्वतन्त्रता के लिये त्याग किया, जेलो मे गये कष्ट उठाये, अंग्रेजो से लडे । जब तक उन मे त्याग की भावना थी लोगो ने उन को देवता के रूप मे देखा । अब यह लोग कुर्सियो पर बैठ कर खाने लगे तो लोगो ने भी सोचा कि आज खाने की हवा चली है, खाओ । सारे देश मे इस समय लोग खाने की तरफ लगे हुये है । जिसे देखो वह खाने की तरफ ही भागता है ।

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

"अखंड लक्ष्मी आहे, कुणाची मार्ग पाहे।"

रास्ता कोई भी हो, किसी तरह से भी आये। मैं भी समाचार-पत्र पढता हूं, मैं देखता हूं कि मिनिस्टर साहब लोग जब ऐसा करते हैं तो हम भी करने लगे।

अभी हमारे नन्दा जी ने एक और को-आपरेटिव कम्पनी बना दी है जो जा कर ठेके लेती है। क्या हुआ कि अब कट्रेक्टर को कट्रेक्ट नही मिलता। जो आदमी ठीक ढंग से काम करने की योग्यता रखता था उस को तो सीधे काम मिलता नही है। कम्पनी को मिलता है, वह जा कर कट्रेक्टर्स को काम देती है इस तरह से काम भी ठीक नही होता और पैसा भी लोग खा जाते है। वह खुद खाती है कट्रेक्टर्स भी खाते है और उस का फल भोगना पडता है देश को क्योंकि जो कुछ निर्माण होता है वह भव्य नही होता, उच्च कोटि का नही होता। आज मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति को हम समाप्त नही कर सके। जब तक हम उस को समाप्त नही कर सकेंगे तब तक हमारा काम नही चलेगा और यह मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति एक ऐसा रोग है जो कि पार्टियो में भी उत्तरोत्तर आ रहा है। मुद्दत से यह चीज चली आ रही है। जिस तरफ भी राजनीतिक दलो की तरफ दृष्टि फैको, कोई चमकदार आदमी दिखाई नही देता, कोई नया आदमी आता नही। किसी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नही दिखाई देता जो कि कार्य को अपने हाथ मे लेने को तैयार हों। हम बुड्ढो को तो मरना ही है उस के बाद लगेगा कि क्या किया जाय। देश के दुर्भाग्य से जितने भी बूढे है वह खलास होते जायेंगे, तो उन की जगह कौन लेगा? आज देश मे इस प्रश्न का निर्माण हो रहा है। यह भी एक भल भुलैया है कि लोग हमारे प्रधान मंत्री की तारीफ भी करते है। लेकिन कांग्रेस दल में भी एक दोष सब से बडा यह आ गया है कि आखिर जवाहरलाल जी के बाद कौन होगा, जवाहरलाल जी के बाद कौन होगा? यह क्या कोई अच्छी बात है कि पिता ऐसा हो जाय कि वह संतान को इस योग्य ही न बनावे कि उसके मरने के बाद वह उस की जगह ले सके? किसी भी ऐसे पिता को अच्छा पिता नहीं कहा जा सकता। अच्छा पिता वही है जो ऐसे चार पुत्र पैदा कर दे जो कि उस के मरने के बाद घर को आगे ले जा सकें। वह पिता किस काम कि उस के समय तो जय-जयकार हो और उस के बाद हाहाकार हो। आज जो देश में वायुमंडल बन रहा है वह कोई एक अच्छा और स्वस्थ वायुमंडल निर्मित नही हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश मे कोई ऐसा नेता है जो कि देश के अन्दर यह आवाज उठाये कि अब से बारातो में ५० से ज्यादा आदमी नही ले जाये जायेंगे और क्या आपको यह उम्मीद है कि अगर ऐसी आवाज उठाई जायेगी तो क्या लोग उसको मान लेंगे? आज जैसी देश मे हवा बह रही है उसमे कोई किसी की नही सुनता। आज देश मे कितनी आर्थिक विषमता है कि एक तरफ तो दीवारो मे झाड फानूस लगे दिखाई देते हैं तो दूसरी तरफ उन गरीब मजदूरो के हाथ दिखाई देते हैं जो कि उन भैंसो के हडो को थामे हुए हैं। जहा आपको एक झोपडी में अन्धेरे मे भूख से पीड़ित एक अस्थि पंजर पडा हुआ दिखाई देगा वही दूसरी ओर आपको आलीशान कोठियो मे हो-हल्ला और लोगो के सिर पर विद्युत् प्रकाश चमकता दिखाई देगा। आखिर हमारे देश के अन्दर इतनी आर्थिक विषमता आज क्यो विद्यमान है? आज हमको अपने देश मे भ्रातृत्व का सर्वथा अभाव देखने को मिलेगा। एक ओर तो एक ग़रीब आदमी का नौजवान लडका भूख और बीमारी का शिकार होकर मर रहा होगा और आखरी दम ले रहा होगा तो दूसरी ओर एक धनी मानी व्यक्ति अपने लड़के की बारात धूमधाम से सजाये होगा और सामग्री और पैसा लुटा रहा होगा और बर्बाद

कर रहा होगा । याद रखिये कि जब तक हम अपने देश और समाज में भाईचारे, भ्रातृत्व, और आपसी सहयोग की भावना पैदा नही करेंगे हमारी कोई भी योजना सफल होने वाली नही है । आज देश की सबसे बडी आवश्यकता इस आर्थिक विषमता को दूर करने की है ।

अब मैं किस को कहू और किस को न कहू । देश मे चारों ओर एक लूट सी मची हुई है और सब चाहते है कि बहती गंगा मे हाथ धो लिया जाय । हर एक व्यक्ति की चाहे वह सरकार मे हो अथवा बाहर यह भावना रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्थिति मे फायदा उठाया जाय और अपना घर भर लिया जाय । अब मैं किस मुह से मत्री लोगो से कहूं कि वे अपने पेटो को ही न भरते चले जब कि मैं स्वयं भी उसी रोग मे मुब्तिला हू । अब जब कि दोनो ही ओर यह लूट खसोट और अपना अपना पेट भरने की बात चल रही हो तो फिर कौन किस को मना करे और किस मुह से करे । अब मैं तो सोचता हू कि शासन के अन्दर जो मत्री वगैरह है वे पहले इस बुरी प्रवृत्ति का त्याग करे और मत्री महोदय शायद अपनी जगह पर यह साचते होंगे कि पहले जो गवर्नमेंट मे बाहर है वे इसको बद करे तो हम भी बद कर देंगे । देश के सामने जो योजनाए है और खाद्य समस्या गम्भीर रूप धारण किये हुए है वे सब जब तक कि हम अपने बीच मे से इस बुराई को बिलकुल निकाल नही देंगे तब तक सफलता हमसे कोसो दूर रहेगी । इसके लिये हमे कोई न कोई एक निश्चित योजना बनानी पडेगी, हमे सारी स्थिति का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करना होगा और अपनी शिक्षा का सारा आधार बदलना पडेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय अब माननीय सदस्य का समय खत्म हो चला है ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" . उपाध्यक्ष महोदय, अन्य माननीय सदस्य तो यहा पर आध आध घटा बोले है जब कि मैं तो शायद अभी ५, ७ मिनिट ही बोला हूगा । मेरे साथ तो पार्लियामेंट मे ऐसा अन्याय नही होना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग आध घटा बोले है उनके पीछे काफी ब्लाक है, उनके ग्रुप काफी बडे है ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : मेरे पीछे यह पूरा का पूरा हाउस है और मैं इस पूरे हाउस को ही अपना ब्लाक समझता हू ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अंग्रेजो ने चूकि वे इस देश पर हुकूमत करना चाहते थे, उन्होंने अपने स्वार्थ को देखते हुए और चूकि वे एक बडी पैनी राजनैतिक दृष्टि रखते थे, उन्होंने भारतवासियो को सदा बुद्धू बनाये रखने के लिये शिक्षा पद्धति कुछ इस तरीके की रखी जिसमे कि भारतवासी शिक्षित होकर केवल क्लर्क और चपरासी बनने के ही योग्य रह सके और उनमे गुलामी की मनोवृत्ति जड जमा ले और यह सब कोई जानते है कि वे अपने इस उद्देश्य मे पूरी तरह सफल भी हुए । मुझे यह बडे दुःख और खेद के साथ इस सदन मे कहना पडता है कि उस दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति मे आज भारत को आजाद हुए ११ साल व्यतीत हो गये, लेकिन उसमे कोई परिवर्तन नही किया गया । अब आप ही मुझे बताइये कि आज की प्रथा के मुताबिक अगर किसी विद्यार्थी को १०० नम्बर मे से ३३ नम्बर मिल जाते है तो वह पास गिना जाता है जिसका कि यह अर्थ हुआ कि वह केवल ३३ प्रतिशत अकलमद रहा बाकी ६७ प्रतिशत मूर्ख रहा । अब अगर उसको ५० प्रतिशत नम्बर प्राप्त होते है अर्थात् १०० मे से ५० नम्बर मिल जाते है तब तो वह जितना अकलमद है उतना ही मूर्ख भी हुआ और जिम्मेदारी व पद पर पहुचने पर जितना वह नुकसान करेगा उतनी ही वह आमदनी करके हिसाब पूरा कर देगा अर्थात् जितना बनायेगा उतना ही बिगाडेगा लेकिन उस ३३ नम्बर

[पंडित ब्रजेश नारायण "ब्रजेश"]

पाने वाले महाशय का क्या हाल होगा ? वह तो ३३ प्रतिशत ही बुद्धिमान है और ६७ प्रतिशत मूर्ख है और उसका परिणाम तो यह होगा कि वह पैदा करना तो दूर रहा उल्टे बाप की कमाई को ही बत्ती लगा देगा। मैं जानता हूं कि यह बात किसी से छिपी नहीं होगी कि आज के हमारे ग्रेजुएट लोग ठीक से अपने आवेदनपत्र तक नहीं लिख पाते हैं। आज देश की शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है और होता यह है कि विद्यार्थी लोग साल भर तो मौज उड़ाते हैं और इम्तिहान शुरू होने के दो, तीन महीने पहले चाय पी पीकर गैस पेपर्स वगैरह तैयार कर लेते हैं और किसी तरह उल्टे सीधे इम्तिहान पास कर लेते हैं। यहां पर जो प्रोफेसर्स लोग होंगे मैं समझता हूं कि वे मेरे इस कथन से सहमत होंगे। यह तो हमारे देश के नौजवानों की हालत हुई

अब देश की हालत क्या हो रही है। देश में अनाज की कमी है, लोगों का भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है, दूध, घी और दही आदि अन्य वस्तुओं की बात का कहे कौन। अब देश में दूध और घी का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर मैं और मेरे सरीखे अन्य लोग इस सदन और इस सदन के बाहर गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं और आवाज उठाते हैं तो शासकदल की ओर से यह कह दिया जाता है कि यह तो पुरानी और दकियानूसी बातें करने वाले लोग हैं जमाने से पिछड़ गये लोगों की आवाज है और शासकदल उन की बात की पर्वाह नहीं करता है। अब यह दृष्टिकोण कि हर चीज जोकि पुरानी है वह अवश्य ही अच्छी होगी और कोई एक नयी चीज भले ही वह चाहे अच्छी क्यों न हो लेकिन यह मान कर उस को अस्वीकार कर देना कि चूंकि वह नई है इसलिये अच्छी न होगी, मेरी समझ में यह दृष्टिकोण भी जो कुछ लोगों का है, मुझे क्षमा किया जाये, ठीक नहीं है। इसी तरह मैं यह कहूंगा कि हर पुरानी चीज को चाहे वह कितनी ही अच्छी क्यों न हो उस का तिरस्कार करना और नई चीजों के पीछे दौड़ना और उन में से चाहे कोई नई वस्तु हानिकारक क्यों न हो लेकिन उस को स्वीकार करना, यह जो आज देश में कुछ लोगों की आदत हो गई है और माडर्न होने का जो एक फैशन सा हो चला है, यह भी चीज ठीक नहीं है और देश के हित के लिये अनुकूल नहीं है।

देश के हर देशवासी और कर्णधारों पर इस बात की बड़ी जिम्मेदारी आती है कि वे शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन कर ताकि हमारे नौजवान लोग देश की जिम्मेदारियों का यथायोग्य वहन कर सकें। आज देश में जो अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है उस का भी हमें अन्त करना होगा। इन सब कामों के लिये हमारे मंत्री महोदयों का जिन पर कि जिम्मेदारी है उन को सचमुच में एक त्याग और तपस्या का स्वरूप अपनाना होगा और उन्हें देश में खड़े हो कर यह घोषणा करनी पड़ेगी कि अब हम उतने पैसों में अधिक अपने लिये नहीं लेंगे और अपने खर्च में यह कटौती करेंगे और ऐसा होने पर ही हम देश में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ होंगे जिस में कि हर देशवासी के मन में भी त्याग करने की भावना आयेगी। और वह राष्ट्र के हित-चिन्तन में लगेगा और उस के अनुरूप आचरण करेगा। मुझे आशा है कि अगर ऐसे दस, पांच आदमी भी देश में निकल आयें तो हमारे देश की तस्वीर बदल सकती है और वह अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो सकता है जिस को हम सब पैदा होते देखना चाहते हैं। लेकिन आज होता यह है कि बातें तो बहुत की जाती हैं और बाहर ही नहीं यहां लोक-सभा में भी सब ओर से अच्छी अच्छी बातें और उपदेश किये जाते हैं लेकिन खाली बातों से अब आप समझ लीजिये कि हमारा कल्याण होने वाला नहीं है और न ही इस से जनता

के मन मे हम विश्वास पैदा कर सकेगे । लोक-सभा मे मुझे यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि माननीय सदस्य केवल अपना भाषण दे कर ही सतुष्ट हो जाते है और यदि कही अगले दिन अखबार मे उन का भाषण उन के फोटो सहित छप गया तब तो उन की खुशी का कोई ठिकाना ही नही रहता है और वे ऐसा समझने है कि मानो उन के पुरखे तर गये ।

अब जहा तक कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का सम्बन्ध है यह हमारा दुर्भाग्य है कि रशियन और अमरीकन दोनो हमे अपने हुए है और पकडे हुए है दानो हम का अपने गुट्ट मे सम्मिलित देखना चाहते है । अमरीका वाले पाकिस्तान का भारी मात्रा मे शस्त्रास्त्र आदि म मदद दे रहे है और जब यहा कुछ लाग यह पूछते है कि क्यो साहब वह टिफेम पर ३०० करोड रुपये क्या खर्च किये जा रहे है तो मुझे उन की बुद्धि पर तरस आता है । आज अमरीका पाकिस्तान का बहुत अधिक मैनिक सामग्री आदि की सहायता कर रहा है और अब तो वहा ऐटम बम और हाइड्रोजन बम भी बनाने के लिये भूमि निश्चित कर ली गई है और बनना आरम्भ हो गया है तब हमे भी चेतना होगा और अपनी सैन्य शक्ति को बढाना होगा और मजबूत करना होगा और यह देखना होगा कि कही हम गफलत मे मारे न जाये । मै पूछना चाहता हू कि अमरीका जोकि अपने को प्रजातत्र होने का दावा करता है जब पाकिस्तान मे लोकतत्र खत्म हुआ और तानाशाही स्थापित हुई तो उस ने क्यो नही उस मे दखल दी और वहा पर दुबारा प्रजातात्रिक शासनप्रणाली क्यो नही कायम की । हमारे उन विदेशी मित्रो को अर्थात् अमरीका, इग्लैण्ड और फ्रास को यह समझना चाहिये कि आखिर हम ने अपने सविधान को उन के सविधानो के आधार पर तैयार किया है क्योकि इस से पहले हमारे यहा पर प्रजातत्र नही था । मै इस लोक-सभा में यह घोषणा करना चाहता हू और मै चाहता हू कि यहा इस देश मे जो अमरीका आदि देशो के राजदूत रहते है वे मेरी इस आवाज को कान धर कर सुने और अपनी अपनी सरकारो तक पहुचा दे कि उन्हो ने पाकिस्तान के बारे मे जो रुख अपनाया और वहा पर प्रजातत्र की हत्या और तानाशाही को स्वीकार किया, यह प्रजातत्री सिद्धान्तो मे विश्वास करने वालो के लिये उचित नही था । उन्हे यह समझ लेना चाहिये कि अगर कही पर बर्मा, पाकिस्तान या अन्य मित्रराष्ट्र मे प्रजातत्र की हत्या होती है और तानाशाही स्थापित होती है तो हमारे सब के लिये यह कलक की बात है । साथी रूस और चीन का साम्राज्यवादी और तानाशाही देश घोषित कर के ही वे अपने को सच्चा प्रजातत्री सिद्ध नही कर सकते ।

बस मै और अधिक न कहूगा क्योकि उपाध्यक्ष महोदय बारबार घटी बजाते जा रहे है और मेरी अभी और इच्छा के रहते हुए भी मुझे उन की आज्ञा का पालन करना पडगा ।

आज देश मे उत्पादन बढाने की बात की जाती है लेकिन मै पूछना चाहता हू कि इस देश मे उत्पादन कैसे बढाया जा सकता है जबकि हमारे देशवासियो मे यह मनोवृत्ति काम कर रही हा कि कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा दाम । जाहिर है कि जब हमारा उत्पादन नही बढेगा तो हमारा एक्सपोर्ट भी नही बढ पायेगा । हमारी सरकार को और तो कोई चीज बाहर एक्सचेज के लिये भजने के लिये मिल नही रही है । अलबत्ता वह गायो के मास और हाड का दूसरे देशो म व्यापार कर रही है और उन को बाहर भेजती है । अब इसी सदन मे आकडो द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि ट्रैक्टर्स की अपेक्षा बैलो से अधिक खेती होती है और उत्पादन अधिक बढता है तो फिर हमारी सरकार बैलो,

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

कुओ, नहर और गायो की ओर क्यो नही ध्यान देती । इस देश में घी और दूध का उत्पादन बढाने के लिये यह बडी जरूरी बात है कि गोवश की रक्षा की जाय । जब भी गाय के वध पर प्रतिबन्ध की आवाज हमारे द्वारा उठाई जाती है तो सरकार की ओर से गोलमोल जवाब दे दिया जाता है और यह भी कहा जाता है कि उस से मुसलमानो की धार्मिक भावना को ठेस पहुचेगी । लेकिन मेरा कहना है कि अगर वे ऐसा समझते हो कि मुसलमानो के कारण इस देश मे गाये कटती हो तो यह बात सही नही है । कोई भी मुसलमान यह नही कहेगा कि नही हमारा धर्म इसी मे है कि इस देश मे गाये काटी जाये । हमारे स्वर्गीय किदवाई साहब ने तो कहा भी था कि इस देश मे गोहत्या बन्द की जानी चाहिये और मेरा कहना है कि गोहत्या बन्द करने के विरुद्ध यह दलील देना कि इस से मुसलमानो की भावना को ठेस पहुचेगी और हिन्दू मुसलमानो में लडाई झगडे की नौबत आ जायेगी सही नही है और यह उसी विदेशी शासकीय शासक की मनोवृत्ति का परिचायक है जिस का कि स्वार्थ इसी मे था कि हिन्दू मुसलमान कभी एक न हो सके ।

आज हमारे देश मे पाकिस्तान से बराबर जासूस चले आ रहे है जोकि हिन्दुस्तान के मुसलमानो के दिमागो मे जहर पैदा कर रहे है और यह बड खेद का विषय है कि सरकार की तरफ से उस की कोई चैकिंग न हो और रोकथाम न हो ।

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य बिलकुल मेरी घटियो की पर्वाह नही कर रहे है । उन्हे अब अपना स्थान ग्रहण करना चाहिये ।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" मै समाप्त किये दे रहा हू । मेरी यह प्रार्थना है कि शासन को सारी स्थिति पर बैठ कर गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये, और समयानुकूल कार्य पद्धति अपनानी चाहिये । देश मे पवित्रता, भाईचारे और भ्रातृत्व के वायुमडल का निर्माण हो । जितनी भी विरोधी पार्टिया है उन का सहयोग लेने के लिये केवल शब्दो तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये बल्कि उन का सक्रिय सहयोग हासिल करने के लिये शासन को जरूरी कदम उठाने चाहिये । अब मै अपनी बात बताऊ कि मुझे तो किसी कमेटी में बुलाया नही गया । अब इस के लिये यह कहा जायेगा कि आप का ग्रुप बहुत छोटा है तो उस के लिये मेरा कहना यह है कि ग्रुप छोटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे वजन को तो देखा जाय । कहने का तात्पर्य यह है कि सक्रिय सहयोग सभी राजनीतिक पार्टियो का हासिल करने की चेष्टा करनी चाहिये और यह सहयोग की आवाज केवल शाब्दिक दिखावे मात्र के लिए नही होनी चाहिये ।

मुझ आशा है कि मै ने जो कुछ निवदन किया है सरकार उस पर ध्यान देगी और राष्ट्रपति महादय ने अपने अभिभाषण में जो यह बतलाया है कि इतने कार्य हो रहे है और योजनाओ पर अमल हो रहा है तो उस के लिये मै सरकार को धन्यवाद देना चाहता हू और जो काय अभी नही हो रहे है अथवा करने शेष है उन की ओर मै सरकार का ध्यान दिलाते हुए और उपाध्यक्ष महादय आप का धन्यवाद करते हुए कि आप ने मुझे इतना समय बोलने का दिया, मै अपना भाषण समाप्त करता हू ।

श्री श० च० गोडसोरा (सिंहभूमि पश्चिम—अनुसूचित आदिम जातिया) उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस एक ऐसा मौका होता है जब हम देश के पिछले वर्ष के कामो को देखते है और अगले वर्ष के लिये नये-नये तरीको पर सोच विचार करते है ।

राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पिछले वर्ष के कामो के लिहाज से ठीक ही है । मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पडता है कि उस अभिभाषण में एक ऐसी आबादी का जिक्र नही किया गया है जिसने राष्ट्र के विकास के लिए कुछ छोड दिया है ।

हमारे राष्ट्र की पाच साला योजनाओ के मातहत बहुत सी सिंचाई योजनायें बनायी गयी और उन योजनाओ को कार्य रूप मे परिणत करने के लिए जब काम शुरू किया गया तो बहुत से लोगो की जमीनो को ले लिया गया । हमारे प्रान्त बिहार मे कोनार, पचेत तिलैया और माईथान चार डैम डी० वी० सी० के अन्तर्गत बनाये गये और इन डैमो के बनने के कारण हजारो परिवार विस्थापित हो गये । कुछ को कम्पेन्सेशन मिला पर कुछ को ता मिला ही नही और वे वहा से भाग कर खदानो में नौकरी करने चले गये जो कि अस्थायी थी । और इस अस्थायी नौकरी करते हुए उनको जो एडवान्स मिला था वह उन्होने अपने जीवन निर्वाह पर खर्च कर दिया । उनकी यह माग थी कि उन्हें कही भी जमीन के बदले जमीन मिलनी चाहिए । आज बिहार मे एक जमीन है कि जिसका बुल डोजर चला कर साफ किया गया है मगर आज तक उसका सैटिलमेंट उन विस्थापितो के साथ नही किया गया । इसलिए वे आज भी इधर उधर भटक रहे है ।

हमार राष्ट्रपति जी का भिलाई और रूरकेला के कारखानो का उद्घाटन करन का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ मगर रूरकेला के मजदूरो के लिए जहा टाउन बनाया गया याने हमीरपुर उसके कारण जो लोग विस्थापित हुए उनका कही भी जिक्र नही है । हमीरपुर वालो ने यह माग की थी कि उनको कोई दूसरी जमीन दी जाये और रूपया एडवान्स दिया जाये जिससे वे अपने मकान बना ले । मगर उनकी कोई सुनवाई नही हुई, और उन्हे जबरदस्ती उन के मकानो से निकाल दिया गया और बडे अफसोस की बात है कि उनके मकानो को बुल डोजर चला कर तोड दिया गया । उनके सम्बन्ध में हमने जब जब भी इस सदन में सवाल पूछा तो यही जवाब दिया गया कि विस्थापित लोगो को फिर से बसाने का काम प्रान्तीय सरकार का है ।

16 18 hrs.

[SHRI MOHD IMAM *in the Chair*]

मगर ताज्जुब तो यह है कि जब इतना बडा कारखाना राष्ट्र के गौरव के लिए बना तो केन्द्रीय सरकार ने विस्थापित लोगो को बसाने के लिये क्यो नही ज्यादा जोर दिया । केन्द्रीय सरकार ने कभी उडीसा की सरकार पर यह दबाव नही डाला कि उन्हें जल्द से जल्द बसाया जाये ।

अब मै सिचाई योजनाओ के बारे मे भी कुछ कहना चाहता हू । मै ऐसे इलाके से आता हू जहा पर कि मेजर सिंचाई योजना नही चलायी जा सकता । लेकिन वहा पर छोटी स्कीमो पर सरकार रुपया खर्च कर सकती थी । इन सिचाई योजनाओ पर हमारी सरकार ने करोडो रुपया खर्च किया मगर हमारे इलाके मे कोई फल नही निकला । मै दक्षिण बिहार, सिंहभूम से आता हू । वहा पर सरकार ने छोटी सिंचाई योजनाओ के अन्तर्गत ब्राह्मणी और कैदा पर लगभग सात लाख रुपया खर्च किया, और अनुमान किया गया था कि इससे एक हजार एकड जमीन सीची जायेगी । लेकिन जब भी सिचाई की जरूरत हुई तो किसानो ने पाया कि दोनो डैम सूखे है । तो सरकार पर लोगो का विश्वास कैसे रहे कि पचवर्षीय योजनाओ से देश की खेती की पैदावार मे भी वृद्धि हो सकती है । तो मेरा यही सुझाव है कि सरकार जो भी योजना बनावे और उस पर रुपया खर्च करे तो उसके लिए एक कमेटी बनावे जो कि यह जाच करे कि उस योजना पर सचमुच में रुपया खर्च

[श्री श० च० गंडसोरा]

हुआ है या नही और अगर खर्च हुआ है तो उससे कोई लाभ भी हुआ है या नही ।

खाद्य समस्या पर यहा दो रोज से काफी बहस हो रही है और अन्न की पैदावार को बढाने के लिए सरकार ने भी बहुत कोशिश की है । हमने सुना है कि इस साल अनाज की पैदावार अच्छी हुई है । मगर साथ ही साथ बहुत से सदस्यो ने बताया है कि दरे ऊपर को ही चढ रही है ।

अब हम खाद्य की पैदावार को बढाने के लिए भूमि सुधार की बात शुरू कर रहे है । कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये हम लोगो को खेती करने की सलाह देने जा रहे है । मुझे तो सन्देह है कि जमीन का पूलिंग करने से पैदावार मे वृद्धि हो सकती है । मै तो सरकार को यह सलाह देना चाहूगा कि आज भी हमारे देश मे करीब ६ करोड एकड जमीन परती पडी हुई है । उसे लेकर तो पहले सरकार आबाद करे और भूमिहीन किसानो को वह जमीन दे । इसी तरह से हमारे जिले मे बहुत सी जमीन प्रोटेक्टेड फारेस्ट मे है जिसमे कि कोई न अच्छी लकडी है और न उस पर घना जगल है । लेकिन फारेस्ट विभाग ने उसको अपने अधीन कर रखा है । अगर सरकार इस जमीन को रिक्लेम करे और लोगो को दे दे तो इससे बहुत पैदावार बढ सकती है और जो जमीन बेकार पडी हुई है वह उपजाऊ हो जायेगी ।

यहा पर बहुत से सदस्यो ने काआपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा फार्मिंग की बात कही है । इस बारे मे मै एक सीधी सी बात कहना चाहता हू और वह यह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग मे लोग उस तरह काम नही करेगे जिस तरह अपनी जमीन पर करते है । लोग देखेंगे कि वह करे तो मै भी करू जब ऐसी बातें होगी तो शायद ही पैदावार बढे । अगर कोआपरेटिव सोसाइटीज चलने लगेगी तो खेतों पर मजदूर काम करेंगे । जमीन के मालिक कहेगे कि मजदूर काम करते है तो हम क्यो काम करे और मजदूर को तो अपनी तनख्वाह की फिक्र होती है उसे काम की बहुत फिक्र नही हो सकती । तो इस तरह जब काम होगा तो मुझे सन्देह है कि कोआपरेटिव फार्मिंग से पैदावार बढेगी ।

और यह कोआपरेटिव फार्मिंग, जैसा कि कुछ मेम्बरो ने कहा है, नया नही है । मेरे ख्याल से इस बारे मे पहले अनुभव प्राप्त किया जा चुका है । पहली योजना के समय एक टीम बनी थी जिसको इस कोआपरेटिव फार्मिंग के सम्बन्ध मे अध्ययन करने का मौका दिया गया था । उन्होने कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे मे जिसका मैकिण्ड फाइव इयर प्लान मे जिक्र है पृष्ठ २०२ पर लिखा है ।

'A few of these societies have been successful, but many of them have experienced practical difficulties for which they have not always been able to secure the necessary guidance The result is that after a time efforts which begin with enthusiasm are given up as failures"

इसलिए मै कहना चाहूगा कि खेती कोआपरेटिव आधार पर न करके खेती करने के दूसरे साधन जैसे नए नए औजार, अच्छा बीज तथा खाद आदि का इन्तिजाम वगैरह ही कोआपरेटिव बेसिस पर करे और ऐसी चीजे है जिनका प्रबन्ध गरीब किसान अकेले मे नही कर सकते है ।

अन्त मे, मै यह कहना चाहता हू कि अगर हमारी सरकार यह चाहती है कि देशवासियो का जीवन स्तर ऊंचा उठे और उसको ऊचा उठाने के लिये अगर वह सीलिंग जमीन पर लगाना चाहती है तो मै इसका विरोध नही करता हूं । मै कहता हू कि सीलिंग हो

लेकिन सीलिंग इस तरह न हो जिससे कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपने रहन सहन का अच्छा इन्तिजाम अपनी आमदनी मे न कर सके और न अपने बाल बच्चो का ही अच्छी शिक्षा दे सके। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि कही ऐसा न हो कि आज जो गरीब आदमी है वह आज से भी ज्यादा गरीब हो जाए। इस वास्ते मैं कहना चाहता हू कि आप इतनी कम सीलिंग न रखे जिस मे कि उक्त परिणाम सामने आये।

Shri J B S Bist (Almora) Mr Deputy-Speaker Sir the President's Address catalogues the commendable works which Government have been carrying on for the economic uplift of the nation This also gives us an opportunity to tell this House and through this House to the country the problems which face the region from which we come

I would like to deal with the problem of the people of the Tibetan border The Chinese occupation of Tibet has had a tremendous impact upon them On the economic side it has meant their being deprived of their only source of living that is, trade with Tibet In spite of the agreement of 1954 restrictions have been imposed on the export of borax, wool and salt from Tibet to India The U P Government in their turn have imposed restrictions restricting the foodgrains to be sent to Western Tibet Unless the trade agreement is revised and our people assured that they will not be deprived of this trade with Tibet Government will have to contend with a people with no source of living or with no means of living and people who have seen and who are seeing the tremendous development which is taking place in Tibet I would submit also that the ideological impact of communism on these people cannot be lost sight of because they are so close to that area

In Tibet mighty jet planes are to land in Lhasa, and a network of roads is being made to connect distant corners About nine months ago, I was told that motors would be coming up to Gyanimandi and Lipu Lake These are two in the extreme of that border from which one would pass places on to the Kungri Bingri pass and the Lipu Lake pass to Milam and Garbyang respectively in our Border As against this it will take about 20 days to reach from here to the remotest village on the borders on our side that is in our parts of the border

16 30 hrs

[SHRI C R PATTABHI RAMAN *in the Chair*]

This is the state of things These people on our border are not merely intelligent but they are also impressionable and I think if we cannot do anything substantial for them, they may form potential recruits for Communism in the border area The State Government does not have the resources to tackle the gigantic problems which face these people and I submit they are a very legitimate charge on the Government of India

I have brought this matter to the notice of the House because I think the Government's attention should be seriously drawn to this area When last in Almora I was informed that in the last fortnight of December, some Chinese came into Garbyang which is in our border area I suppose they came to look at the topography of the region But I am convinced that the news I received was correct because I was told that our outpost which generally remained at Dharchula—went up to Garbyang What reports they have sent to the Government I do not know But I would request Government to make inquiries and find out what the facts are

I have a grievance also I find that no senior officer ever does go to see these borders Maps do not give the idea completely I would suggest that the old practice which was existing

[Shri J B S Bist]

before, under which a Deputy Commissioner was ordered to visit these posts and see things for himself within two years of his appointment, should be revived I wonder if any Sub-divisional officer of that area has ever been there It would be interesting to know whether any Deputy Commissioner has, since independence was attained, has ever gone there and whether any officials who may have gone there took note of the things as they exist there

This also underlines the fact that the posting of an outpost at Dharchula does not serve the purpose I think this incident shows that it must be posted at Garbyang It is not a place where men cannot live in winter The whole of the population do not come to the plains There are villagers who remain there But certainly, proper facilities must be provided to these outposts and those people should be relieved in a reasonable period from that place which is in the extreme border and somewhat desolate

The other thing I would like to submit is this I have been informed that people across the border claim that some territory which lies within our border is theirs I have information that this is taught to students of the primary schools even, when geography is being taught May I request Government to enlighten itself on this point? It is an important matter and I hope my submission will be attended to

I suggest that the Government of India should establish a special agency for development of these regions stretching from Ladakh in the north-west to North Assam in the East Some of these regions have been categorised as scheduled districts and received Central grants according to the Constitution But others which probably are in U P do not receive anything Besides inclusion of these areas as scheduled areas I would stress that a special development agency be formed whose first task should be to make out an alternative economy for these regions I personally feel that this is necessary

I may here refer to a committee set up by Shri A P Jain, our Food Minister, to go into the problem of food production in the hilly and inaccessible areas I would like to know what this committee has done up to now Personally, I believe that this committee can serve no useful purpose It has to be remembered that in the hills, with all attempts and with the co-operation of all, food to meet the actual demands of the people cannot be produced I am definite on that At the most with the best of irrigation at least in the Almora District, food produced will not last for more than 6 months Why not spend money on horticulture and other industries?

I need not elaborate these points at present I may take them up if I get a chance in the Budget discussions There is horticulture already in the hills, I believe But it is not of that pattern which will tempt the agriculturists to give up their fields and a maund or two of wheat in the expectation of some horticulture return which will accrue in the long run I think that has to be attended to seriously

Recent geological investigations have shown that these regions are rich in mineral deposits Zinc, copper and dolomite have been discovered in the Almora region But in the absence of communications these could not be exploited for commercial purposes Linking all these areas with a network of roads and railways is absolutely necessary if any development is to be made in these areas That is the first thing which has to be done

I may here also mention a fact that some years ago it was said that Delhi would be connected with Kathgodam by a broad gauge line *via* Rampur and Rudrapur This, certainly, would have helped the economy of that place I

believe some survey was also made; but nobody knows where the project has gone Such statements which make the people feel that they are going to get something, but which are later washed off like that is a thing very disappointing May I request Government to consider this point again and take up this project? Once the railway links are completed I am sure these regions will more than compensate Government for the investment which it will be making Now, this fact does not seem to show that Government are anxious to develop the economy of these regions May I request the Government to consider the matter very seriously? In conclusion I have to request that something more should be done to preserve the culture of these regions The AIR should endeavour to establish small broadcasting units and broadcast programmes in Kumaoni, Garhwali and other indigenous languages

Shri Thevar (Srivilliputhur) Sir while speaking on the Presidential Address, I want to say some words on the foreign policy and our Commonwealth link We are having a wonderful Commonwealth where our partners want to have the wealth as common but not our sovereignty We have also created an impression in the whole world—a thing which is impractical in politics—that we have achieved everything through non-violence In all countries in every place, we know there were parties attracted to the left and the right Both were patriots and both had their quota In the same manner, in this country also, the leftists, while having the Bhagavad Gita, entered the gallows, many died in the Andamans They were considered to be non-Gandhites Never mind The non-violent creed was rather possible when we were a slave nation But after becoming a Republic, we are having a military budget of hundreds and hundreds of crores Even then we go on talking the same thing whenever we talk of Goa or Pakistan We allow our military to march against the poor Nagas and we allow our bullets to go into the hearts of the political opposition, the labourers and the kisans No man is able to understand this creed This decency and decorum and all this wonderful preaching, are also a deceit

In the post-war period, everybody is talking of peace Our wonderful United Nations are having their disunited notions They talk of peace but peace is going to pieces It has become a League of Nations, No II We have made the world understand that democracy has come and that the human standards are so high and that nobody can invade another country or even dream of doing so The opposite has happened It was done by a democratic country and at that time the big brother of democracy, America was keeping quiet I refer to the Suez episode We thought that it would check the democratic rank and file doing that When the matter come to itself in Lebanon, the very same big brother showed his claws and teeth in a more nasty manner than even England, with their wonderful Sixth Fleet and their marines, they wanted to threaten the little country but in spite of this policy the little country was up to the challenge and so the matters came to an end

We believe that there should be democracy all over the world through our non-violent methods What about the military dictatorship not only in Pakistan but in other countries also? It is there in Thailand, in Burma and all the other places It is encircling India We need not be concerned about Thailand or Burma Burma is away from the Commonwealth Thailand is considered to be in the SEATO We shall come to that matter afterwards But what about Pakistan, a member of the Commonwealth? If the military dictatorship is to be allowed and if that has to be sponsored by the wonderful western

[Shri Thevar]

nations, are we not be have our eyes opened and are we not to send a protest? If you allow this sort of military dictatorship, how are we to maintain our democracy? Will not our democracy enter into a demonocracy'? What is this? Again, they have bases not for mere aeroplanes but for rockets and for the latest weapons and the bases are built in Pakistan near the Afghan mountains

Now I refer to the boundaries We are having a wonderful system In spite of our having a Republic for over 11 years, we have not yet demarcated our boundary Even a small family, after having a partition will have its own boundary with a very small wall or if not a wall at least a line The utensils and the properties will be shared proportionately But we are not having such a thing If anything has occurred we say that as the boundary has not yet been demarcated we cannot have anything to do with that The Members of Parliament exaggerate the situation

Then the Pakistan Minister comes and our Prime Minister and the Pakistan Minister have consultations and in spite of knowing fully article 3 of the Constitution they exchange places knowing fully that it is against the Constitution When questions are raised about it it said No no, it has nothing to do with article 3 It is only a disputed area So you need not do anything with it' If it is a disputed area why does legislation come in? When something has to be done, according to the Constitution there is legislation Because they are in a majority it comes in When something else has to be done they say it is a disputed area Is it not a regular controversy? If this is to come from the mouth of the very big people, how are we to swallow it* Giving respect to elders should not end in sacrificing principles After all, we are now in a situation where we see the small firing across the border area near Pakistan entering into a real business

The year 1959 has appeared and it has become important I feel, and I also want to give a warning in particular to the Government and in general to the country, that it is going to be an episode like 1939 This is going to be a crucial year Very many people are thinking that the second world war ended because it is news and it is a statement But we all educated men know it the first world war started in 1914 and ended in 1918 The Versailles Treaty was signed in 1919 and the troop went home Now the second world war started in 1939 and it was supposed to have ended in 1945 the peace treaties have been signed but the troops have not gone home Either in the name of mutual assistance or in the name of occupation or in the name of delegation or in the name of some delegates sponsoring moves they are remaining in the places where they ought not to

Regarding the principal allies they are having all lies for their wonderful programme Also we feel that we are safe with the west We say that we are not on a line with them All right As we are having this wonderful programme of non violence we are having that non-alignment with them also If we are really non-violent we need not have any military budget with crores of rupees spent Those crores of rupees could be utilized for some other purpose, like planning or anything else But if we are to protect our country, we must have model weapons and modern weapons and weapons with which we can cope with the situation What is the use of buying weapons which are obsolete and that too from the English companies * * ? What is this?

* * Expunged as ordered by the Speaker

We are unable to understand this diplomacy and the standard is slowly going down and down Diplomacy, if it is to be without decency or honesty, is nothing but hypocrisy If that boundary is to be crossed, it cannot be called diplomacy, it is sheer hypocrisy Unfortunately, the second World War has made none the victor and nobody the vanquished It is a lull in the warfare going on They have understood that They know that the second World War has ended in creating a third and so, the occupation troops are there, the mutual assistance troops are there and the United Nations are having disunited notions

We are thinking that peace has come, but peace is going to pieces Are we not going to be vigilant over this matter? Are we not going to have an idea regarding the danger which is confronting us? We talk of unity How are we to have unity? We talk of co-existence—something wonderful We advise nations having hydrogen and atom bombs to have co-existence, but should we not have courtesy to have co-existence with our political opposition? We resort to shooting and all sorts of things whenever occasion arises and when it suits our purpose In spite of non-violence we have our shooting incidents and we refuse to have judicial enquiry regarding the shooting in Ramanathapuram

An Hon Member: And in Bombay and Ahmedabad

Shri Thevar In the name of truth, we suppress the news If this sort of truth and non-violence is to be the principle of our great country and the great Congress, where will it lead to? In spite of our having a wonderful philosophy on our mouths, what do we do? We need not even maintain a standard of democracy, it will be better for us to maintain the human standard at least

Parties may differ in views, but every man has his responsibility towards the nation This is a House where there have been great men who have made very great sacrifices and also new-comers with very great principles In spite of our greatness, culture and all that, if any man is to talk about Hindu religion, you simply dub him as a communalist If another man comes up with an economic theory, you dub him as a communist If some other man tries to say something, you cap him with some position in this committee or that committee With this sort of procedure, how can you have a healthy opposition? You cannot have it If you want to have it, you will have to change your procedure I do not say that you do not want to have it, but you are purposely avoiding that You know better than we all how to proceed, but I do not understand the real reason behind it

When there was an adjournment motion this morning regarding Pakistan firing, our revered Prime Minister was not in a position to answer the questions His reply was rather lamentable He simply says that the position is the same as described by the Member and the adjournment motion is necessary, but the motion need not come as a practical thing They say, our forces will retaliate With what will our forces retaliate? We know our forces are very fine and numerically stronger, but what about the latest weapons? The weapons which are in the hands of the Pakistanis are thousand times better than ours Whenever we ask about it, we are told, "It is a military secret, you need not probe into that" With that, you finish Do you really believe that your weapons can cope up with the situation against the Pakistanis?

What about the Hyderabad business? Sidney Cotton in the name of a groundnut merchant, carried weapons to Hyderabad and the mischief was a very dangerous one But, fortunately, on account of the death of Jinnah,

[Shri Thevar]

leaving on both sides an episode which was not known to the public, Rajendra Sinhji captured the position and they made the weapons their own in one night. So we say we had our police action, we did all this work I do not wish to go into the matter, I simply mentioned it Because, you are all big men, you can understand that This much clue I can give

Regarding Kashmir what is this? We allow them to have Kashmir and we remain in Jammu It is not only Pakistan but it is a Pakistan in Pakistan Fully knowing that, we want them to remain there and we allow them to remain there We have already entered into a pact to allow them to remain there

Mr. Chairman: I think the hon Member's time is up He has already taken 15 minutes

Shri Thevar. I want five more minutes So many hon Members have taken 20 minutes I was a witness to that

Mr Chairman. He may finish as early as he can

Shri Thevar: Regarding Kashmir we simply say that they are occupying But they are not occupying with their might They are occupying with our acquiescence When Kashmir was invaded we sent our army even without the consultation of the Commander-in-Chief, General Cariappa because we wanted that to be the base for the westerners in the name of Pakistan It may be unpalatable because truth cannot be palatable But when we probe into the question this is what we find We believe this But are they proving this truth to our friendship? They want to create scare and they want to create a lull They want to create all sorts of nuisance in the name of aid What is the aid? They give military aid to the enemies of ours and then they begin to give aid for our food problem, and that too not to our satisfaction It is not the quality which we are in need of The quality is third-rate or fourth-rate which they use to feed their horses That sort of wheat is given to us and we are not in a position to swallow it What can we do?

Then regarding the position of the leftists and rightists, there was one wonderful privileges motion against Shri E M S Namboodiripad, the Chief Minister of a State, who wrote some letter in the course of his work It was considered to be a very big *thing Now this wonderful Mathai* business has come and it is creating a controversy We are dealing with that in a manner of business and not as a privilege It has come to that Why? We need not stoop to such low levels There are very many things which must come

After all, what is this Mathai affair? What is it? After the scandalous Mundhra business, a man who worked in the American Embassy was allowed to be a spy in the Secretariat of Delhi It was not an ordinary affair They allowed it, and when they allowed it he has done his own job He cannot but do it After this a statement comes from a very great man like our Prime Minister 'I allowed him that when I was in a wrong mood" What is this? This sort of wrong mood is not only dangerous to the prestige of our Prime Minister but it is also dangerous to the country, it is not only dangerous to the country but it is dangerous to the whole non-whites, it covers the whole Asians If he is an ordinary man, he can be in a wrong mood, but not the Prime Minister of a country, and that too at this juncture in the year 1959 when the spies are working like wolves and our Secretariats are being burnt At this juncture we are keeping quiet when

we hear the news that it was attempted twice and the third time it became ashes Now what is this thing? What were our intelligence people doing?

Regarding the food problem even the Congress members say—though I am not able to follow Hindi fluently, I could follow a little—that it has failed, failed failed They said it three times We all know that But the Government has to deal with this problem We find that in this case the political leaders have become dealers in corruption nepotism and all those things But nobody is thinking of dealing with the problems of the country

17 hrs

When this is the position, how are we to cope up with corruption If we go into the food problem and the problem of land ceilings and all those things—it may be very nice to talk but when we go into the practical affair we will be muddling and putting the country into a dangerous position not only economically but morally also When we are having the military danger about, we need not have economic disaster also in the name of this and that which we are not having in mind and also about which we are not having clear ideas We talk of ceiling all right If ceiling is to come about, why not let it start with the salary of the hon Prime Minister himself and from the urban area? You must set a standard The urban area must come first and then the rural area While keeping the urban area with their wealth and all that if you go to the rural area you are not serious But, you want to keep the 80 per cent of the population under the tutelage of the 20 per cent and then once again you want to play the game of the Western model I seriously request you not to have anything towards the leftists and not to think that they are this and that I do agree that there are very many leftists who talk in an irresponsible manner and who talk at a wrong time But in the name of responsibility I want the rightists not to become docile and degraded and by that bring the country to disaster

With this I conclude, Sir

17 02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday February 18, 1959/Magha 29, 1880 (Saka)